चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

11 अगस्त–17 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

इराक़ की आग भारत पहुंची

मौलाना सलमान नदवी के कारनामों से देश की खुफिया एजेंसी में खलबली मच गई. मौलाना नदवी ने इराक में नरसंहार करने वाले आतंकी अल-बगदादी को इस्लामिक दुनिया का ख़लीफ़ा मान लिया और पांच लाख सैनिकों को इराक भेजने की पैरवी करके धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की. यह बात और है कि अधिकांश लोगों ने मौलाना नदवी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग गफलत में आ गए. कुछ सुन्नी युवा भावना में बहकर इराक जाने के लिए तैयार हो गए और उसके जवाब में कुछ शिया युवा भी इराक जाकर अल-बगदादी से लड़ने के लिए तैयार हो गए. मौलाना नदवी ने यह विवादास्पद बयान 7 जुलाई को दिया था, लेकिन अब वह अपने बयान से मुकर गए हैं और मीडिया पर दोष मढ़ रहे हैं. सवाल यह है कि मौलाना नदवी ने यह खंडन पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने लोगों की भावना भड़कने क्यों दी? मौलाना सलमान नदवी के विवादास्पद बयान से उठे बवाल और खुफिया एजेंसी में फैली सनसनी पर पेश है चौथी दुनिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट...

प्रभात रंजन दीन

खूंखार आतंकवादी संगठन के रूप में एकबारगी उभरे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के सरगना अबू बक्र अल बगदादी का एक मिनट का ऑडियो टेप और लखनऊ के प्रमुख इस्लामी शोध संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के डीन मौलाना सलमान नदवी का विचित्र-विवादास्पद बयान केंद्र एवं राज्य की खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. बगदादी के टेप और नदवी के बयान का कुप्रभाव जांचने-परखने में खुफिया एजेंसियां एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं. खुफिया एजेंसियों की चिंता है कि बगदादी के बुलावे और नदवी के उकसावे पर इराक के युद्ध में उतरने के लिए भारतीय युवकों की आईएसआईएस में भर्ती का कहीं लखनऊ ही केंद्र तो नहीं बन रहा!

शियाओं के ख़िलाफ़ क्रूर युद्ध की शुरुआत करने वाले आईएसआईएस की तरफ़ से कुछ भारतीयों के भाड़े पर लड़ने की ख़बरें अभी पड़ताल का विषय ही थीं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रमुख इस्लामी शोध केंद्र दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के शरिया फैकल्टी के डीन मौलाना सलमान नदवी के बयान से सनसनी मच गई. देश ही क्या, दुनिया भर की निगाहें लखनऊ पर टिक गईं कि यह कौन-सा बयान आ गया और इसके पीछे आख़िर इरादा क्या है? मौलाना सलमान नदवी ने पांच लाख भारतीय सुन्नी युवकों की फौज बनाकर उसे इराक में शियाओं के ख़िलाफ़ उतारने की हिमायत की. इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सुन्नी युवकों की फौज बनाने का आह्वान सऊदी अरब से किया और सऊदी अरब सरकार को इस बारे में पत्र भी लिख डाला.

नदवी का बयान ख़तरनाक: आईबी, केंद्र सरकार चुप

अराजकता की हदें लांघने वाली इतनी आज़ादी भारतवर्ष में ही मिल सकती है. ऐसे सनसनीखेज बयान के बावजूद भारत सरकार की तरफ़ से न कोई आधिकारिक बयान आया और न किसी क़ानूनी कार्रवाई की सुगबुगाहट ही दिखाई दी. यह वही नदवी हैं, जिन्होंने खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बक्र अल बगदादी के प्रति खुला समर्थन जताया था और स्वयंभू ख़लीफा होने की उसकी घोषणा को मान्यता दी थी. इसके बावजूद देश में इसके बरक्स किसी किस्म की समुचित कार्रवाई होती नहीं देखी. ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार की तरफ़ से चुप्पी तो साध ली गई, लेकिन यह मुद्दा इतना गंभीर है कि इस पर देश की खुफिया एजेंसियां सतर्क और सक्रिय हो गई हैं. गृह मंत्रालय ने इस मसले पर कोई मुखर प्रतिक्रिया नहीं जताई है, लेकिन संदेहास्पद गतिविधियों की निगरानी और प्रतिक्रियात्मक बयानों की समीक्षा बड़ी सूक्ष्मता से की जा रही है.

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के आतंकवाद मामलों के वरिष्ठ समीक्षक भी यह मानते हैं कि अगर समय रहते स्थिति न संभाली गई, तो आतंकी अराजकता का अगला पड़ाव भारतवर्ष ही बन सकता है. एक तरफ़ आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के समर्थन में खुलेआम बयानबाजियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ़ उस संगठन का सरगना भी भारतवर्ष के युवकों को युद्ध के लिए आमंत्रण दे रहा है. उधर, अलकायदा भी भारतवर्ष में जेहाद शुरू करने का जैसे अल्टीमेटम ही दे रहा है. आईएसआईएस सरगना अबू बक्र अल बगदादी के ऑडियो टेप केवल इराक ही नहीं, बल्कि लखनऊ के उन इलाकों में भी बज रहे हैं, जो सुन्नी बहुल सघनता के लिए जाने जाते हैं. इस टेप में भारतीय सुन्नी युवकों को आईएसआईएस में शामिल होने का खुला आमंत्रण देते हुए बगदादी को साफ़-साफ़

(शेष पृष्ठ 2 पर)

साफ़ नहीं मौलाना नदवी की सफाई

लखनऊ के प्रमुख इस्लामी शोध संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के डीन मौलाना सलमान नदवी से इस सिलसिले में इस संवाददाता ने बातचीत की. मौलाना नदवी ने पांच लाख सुन्नियों की फौज बनाने की वकालत किए जाने के अपने बयान के बारे में बताने से पहले इराक में नूरी अल मालिकी द्वारा सुन्नियों का कत्लेआम कराए जाने की तीखी निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल मिलकर शिया और सुन्नियों के बीच दुश्मनी पैदा कर रहे हैं और पूरे संसार में उनके एजेंट इसे फैला रहे हैं. मौलाना नदवी ने अपने बयान पर आते हुए इतना ही कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते उनका यह फर्ज है कि देश-दुनिया में होने वाली घटनाओं पर वह दीन, कुरान और हदीस के मुताबिक ही बयान दें. मौलाना नदवी ने यह भी कहा कि आईएसआईएस के प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी को भी उन्होंने अमनो अमान कायम करने की सलाह दी है. अपने विवादास्पद बयान के बारे में नदवी ने इतना ही कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. फिर आपने उस अंग्रेजी अख़बार को अपना खंडन क्यों नहीं भेजा? इस सवाल पर मौलाना नदवी ने कहा, अख़बार को खंडन भेजा गया है. लेकिन, उस अख़बार के स्थानीय संपादक ने साफ़-साफ़ कहा कि मौलाना नदवी की तरफ़ से कोई खंडन नहीं आया है.■

...और जब बात बिगड़ गई

मौलाना सलमान नदवी ने विवादास्पद बयान देकर सनसनी फैला दी. मौलाना नदवी के मुताबिक उन्होंने इराक में नरसंहार कर रहे आईएसआईएस के सरगना अल-बगदादी को 7 जुलाई को पत्र लिखा था. जबकि उन्होंने 17 जुलाई को यह पत्र अपने फेसबुक पर प्रकाशित किया. मतलब यह कि उन्होंने 7 जुलाई को पत्र लिखकर मीडिया को ख़बर नहीं दी. इस ख़बर को सबसे पहले एक उर्दू अख़बार ने पहले पेज पर लीड स्टोरी बनाकर प्रकाशित किया था, लेकिन खलबली तब मची, जब इस ख़बर को एक अंग्रेजी अख़बार ने 26 जुलाई को अपने पहले पन्ने पर छापा. अगर यह भी मान लिया जाए कि मीडिया ने 7 जुलाई को दिए गए इस बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, तो भी यह बात समझ में नहीं आती है कि मौलाना नदवी ने आधिकारिक खंडन भेजने में इतनी देर क्यों कर दी. उन्होंने अपना आधिकारिक खंडन फेसबुक के जरिये 31 जुलाई को जारी किया. बयान सही था या उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मौलाना नदवी के बयान से भावनाएं भड़क रही थीं. सुन्नी युवा इराक जाकर अल-बगदादी के आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे. इसके जवाब में शिया युवाओं ने भी इराक जाने के लिए कमर कस ली थी. लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कती रहीं. जो नुक़सान होना था, वह होता रहा. माहौल बद से बदतर होता चला गया, लेकिन मौलाना नदवी ने मीडिया को दोष देने के अलावा जख्मों पर मरहम रखने वाला एक भी बयान नहीं दिया. हैरानी तो इस बात की है कि आज भी वह अल-बगदादी को एक आतंकवादी बताकर कर उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं. जबकि यह पूरी दुनिया देख रही है कि अल-बगदादी और उसके लड़ाकू इराक में नरसंहार का ऐसा तांडव कर रहे हैं, जो न सिर्फ़ ग़ैर इस्लामी है, बल्कि अत्यंत वहशियाना और अमानवीय है.■

गांधी को नहीं जानती हैं अरुंधति राय 03

पटना कब बनेगा पाटलिपुत्र 06

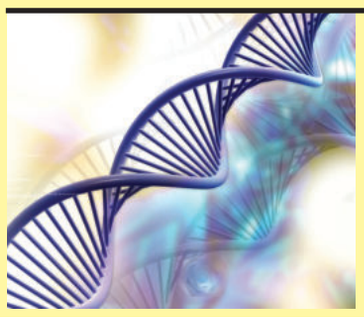

सौ बीमारियों का एक इलाज 10

साई की महिमा 12

इराक़ की आग भारत पहुंची

पृष्ठ एक का शेष

सुना जा सकता है. क़रीब एक मिनट का यह ऑडियो टेप खास तौर पर रमजान के संदेश के नाम से जारी किया गया है.

ऑडियो टेप में बगदादी के बयान का उर्दू तरजुमा भी शामिल है. इस संदेश में भारतीयों को आमंत्रण देते हुए आईएसआईएस की कतार में चीनी, अमेरिकी, फ्रांसीसी, जर्मन और आस्ट्रेलियन युवकों के भी शामिल रहने की बात कही गई है. 28 जुलाई को दिल्ली के सराय काले खां इलाके में गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी ने भी कहा है कि वह युवकों को लश्कर में भर्ती कराने का काम कर रहा था. खुफिया एजेंसियां इस अहम सुराग पर काम कर रही हैं कि कुरैशी उन युवकों को आईएसआईएस के हवाले करने में केंद्रीय भूमिका तो नहीं अदा कर रहा था. अब तो कुरैशी के भाई के बारे में भी पता चल गया, जो कोलकाता के अलीपुर जेल में बंद है और वहीं से देश-दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को मॉनीटर कर रहा था. खुफिया एजेंसियों ने उसके और पाकिस्तान में बैठे उसके सूत्रधारों के बीच जेल से हो रही बातचीत भी पकड़ी है.

बहरहाल, खुफिया सूत्र बताते हैं कि भारत के मुस्लिम युवकों को न केवल आईएसआईएस, बल्कि चेचेन्या, अफगानिस्तान और सीरिया में भी लड़ाया जा रहा है. तमिलनाडु के कई युवकों के सीरिया में लड़ने की आधिकारिक पुष्टि हुई है. आईएसआईएस की तो इतनी धूम मची कि भारत के तक़रीबन हज़ार से अधिक युवक इराक में शियाओं के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरे हुए हैं. जबकि उनके इराक में फंसे होने की बात कहकर भारतवर्ष में नियोजित भ्रम फैलाया जा रहा है. अफगानिस्तान में इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के तालिबानों के साथ लड़ने की भी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि अलकायदा भारतवर्ष में जेहाद के नाम पर आतंकी अराजकता फैलाने की तैयारी में है. अलकायदा ने इसे गजवा-ए-हिंद का नाम दिया है, जिसका मतलब है, निर्णायक जंग. शुरुआत में तो इसके लिए अरब युवकों को भर्ती किया गया. अब इसमें कश्मीरी युवकों को शरीक किया जा रहा है.

तहरीक-ए-तालिबान ने तो कश्मीर में अपना दफ्तर खोलने तक का बाकायदा ऐलान कर दिया है. हरी पर्वत की दीवारों पर लिखे हुए वेलकम तालिबान के नारे इस ऐलान की पुष्टि करते हैं. आईबी के एक आला अधिकारी ने बताया कि अलकायदा का भी एक ऑडियो टेप मिला है, जो अल सहाब की तरफ़ से जारी है और उसमें साफ़ तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों के मुस्लिम युवकों को ग्लोबल जेहाद में शरीक होने की अपील की गई है. ये वही प्रदेश हैं, जहां इंडियन मुजाहिदीन आतंकी गतिविधियों में शामिल है और अपने संगठन में युवकों की भर्ती कर रहा है. अलकायदा के कंधे पर सवार होकर इंडियन मुजाहिदीन भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का होने की जद्दोजहद कर रहा है. नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के दस्तावेज स्पष्ट बताते हैं कि अलकायदा और तालिबान, दोनों ही इंडियन मुजाहिदीन को मजबूत करने में लगे हैं. यासीन भटकल और रियाज भटकल जैसे आतंकियों का इस्तेमाल इसी में हो रहा है.

आईएम के कई सदस्य अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तालिबानों के साथ लड़ रहे हैं. पाकिस्तान भी चाहता है कि तालिबानों और अलकायदियों के युद्ध का केंद्र पाकिस्तान की बजाय भारत बन जाए. इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सारे हथकंडे अपना रही है. पाकिस्तान सीमा से आतंकियों को भारत में ढ़केलने का एक सूत्रीय कार्यक्रम इसी इरादे का नतीजा है. लश्कर-ए-तैयबा में केरल के युवकों को भर्ती कराने का मामला एनआईए पकड़ चुकी है और कुख्यात टी नजीर एवं सरफराज नवाज समेत 13 आतंकियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट से सजा भी मिल चुकी है. इन्हीं लोगों द्वारा भर्ती किए गए चार युवक जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में मारे गए थे. इनमें से अब्दुल जब्बार नामक युवक भाग निकलने में कामयाब हुआ था, लेकिन बाद में केरल पुलिस के हाथों पकड़ लिया गया था. बाद में इस मामले को एनआईए को दे दिया गया, जिसमें 24 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई.

इधर, महाराष्ट्र के चार युवकों आरिफ फैयाज माजिद, फहद तनवीर शेख, अमन नईम टंडेल और शाहीन फारुकी तनकी के आईएसआईएस के साथ इराक में लड़ने की आधिकारिक पुष्टि औपचारिक तौर पर हो चुकी है. इन युवकों के परिवारवालों से भी पूछताछ की गई है और उसके बाद आईबी की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई. इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ सुन्नी युवक मोसुल और टिकरित में आईएसआईएस के साथ शियाओं के ख़िलाफ़ चल रहे युद्ध में शामिल हैं, जबकि इनके इराक में फंसे होने की बातें कही गई थीं. महाराष्ट्र के कल्याण निवासी आरिफ फैयाज माजिद अपने तीन अन्य साथियों के साथ 23 मई को निकला था और 24 मई को उसने अपने घर वालों को फोन करके बताया कि वह और उसके साथी बगदाद में हैं.

इराक की खुफिया एजेंसी ने भारतीय खुफिया एजेंसी की छानबीन को आगे बढ़ाते हुए बताया कि उनके मोबाइल से हुई आख़िरी कॉल उनके मोसुल में होने की पुष्टि करती है, जो आईएसआईएस के कब्जे में चला गया था. आरिफ फैयाज माजिद, फहद तनवीर शेख और अमन नईम टंडेल इंजीनियरिंग के छात्र थे, जबकि शाहीन फारुकी तनकी एक कॉल सेंटर में काम करता था. आरिफ फैयाज माजिद द्वारा अपने घर के लोगों को लिखा गया पत्र भी खुफिया एजेंसी ने बरामद किया है. इन युवकों के अलावा 18 अन्य भारतीय सुन्नी युवकों के वहां होने की पुष्टि हुई, लेकिन उनका ब्यौरा यहां नहीं मिल पाया. सीरिया के भारत स्थित राजदूत रियाद कमाल अब्बास ने भी कहा था कि सीरिया के अलावा चेचेन्या, अफगानिस्तान और कुछ अन्य देशों में जेहाद के नाम पर चल रही हिंसा में भारत के आतंकी भी शरीक हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

न पुरजोर निंदा, न कोई फ़तवा

शियाओं के ख़िलाफ़ इराक में पांच लाख भारतीय सुन्नी युवकों की फौज बनाकर भेजने के बारे में सऊदी अरब सरकार को लिखे गए पत्र ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस्लामी सियासत को गड्डमड्ड करके रख दिया है. लखनऊ के दारुल उलूम नदवातुल उलमा के शरिया विभाग के डीन मौलाना सलमान नदवी द्वारा भेजे गए इस पत्र पर सुन्नी मौलानाओं को सांप सूंघ गया है, लेकिन वे इसकी निंदा के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं. मौलाना नदवी के बयान के ख़िलाफ़ कोई फतवा भी जारी नहीं हुआ. इससे इनकी अंदरूनी स्थिति आसानी से समझी जा सकती है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य मौलाना अतहर अली ने इतना ही कहा कि सऊदी अरब की सरकार को पत्र लिखने से अच्छा था कि मौलाना नदवी भारत सरकार से अपील करते कि इराक के शिया-सुन्नी विवाद का कूटनीतिक हल निकालने की कोई सार्थक पहल हो. वह खुद ही सवाल उठाते हैं कि सऊदी अरब सरकार ही क्या कर लेगी? सुन्नी युवकों की फौज बनाए जाने के बारे में नदवी के बयान पर मौलाना अतहर अली ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इससे आपसी भेदभाव ही बढ़ता है.

उलेमा काउंसिल के सदस्य मौलाना महमूद दरियाबादी ने कहा कि मौलाना नदवी द्वारा इस तरह का पत्र लिखे जाने को वह अविश्वसनीय मानते हैं. अगर यह सच है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इराक और सीरिया के विवाद को शिया- सुन्नी के एंगल से देखना और समझना गलत है. ऐसे पत्र दो समुदायों के बीच भेदभाव की खाई ही बढ़ाते हैं. लखनऊ की ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से ही मना कर दिया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने मौलाना नदवी की निंदा की और कहा कि यह पत्र देश के हितों के ख़िलाफ़ है और इससे शिया और सुन्नी समुदाय के बीच अनावश्यक तनाव बढ़ेगा. ■

आज़म खान से शिया नाराज़ क्यों?

उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर माथापच्ची हो रही है कि शिया समुदाय के लोग प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान से नाराज़ क्यों हैं? शिया और सुन्नी समुदाय के बीच फैले तनाव को आजम खान कहीं अंदर ही अंदर हवा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं! लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से खास तौर पर आजम खान ज़्यादा ही बौखलाए हैं और उनके अनाप-शनाप बयान भी सामने आए हैं. आजम खान को लगता है कि शिया समुदाय के लोगों ने भाजपा को वोट दिया और दूसरा यह कि आजम खान खुद भी सुन्नी हैं. यह तनाव इस कदर फैल गया कि अलविदा की नमाज के बाद शियाओं ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान के आधिकारिक आवास को घेरने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की लाठियां चलीं और शिया धर्मगुरु समेत कई लोग जख्मी हुए. इसके बाद तो आजम खां के ख़िलाफ़ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने मोर्चा ही खोल दिया. शिया समुदाय के लोग कैबिनेट मंत्री आजम खां को सपा से हटाने, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार करने और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले डीएम-एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं. सियासत ने वह रूप ले लिया है कि शिया समुदाय एक तरफ़ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, तो दूसरी तरफ़ आजम खान को अपने निशाने पर ले रहा है. कल्बे जव्वाद का कहना है कि अहमद पटेल और आजम खां के इशारे पर निहत्थे शिया उलेमा पर लाठीचार्ज कराया गया, ताकि दिल्ली और लखनऊ में बेची गई करोड़ों की वक्फ संपत्तियों से ध्यान हटाया जा सके. लाठीचार्ज के ख़िलाफ़ कल्बे जव्वाद और प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त राज्यपाल राम नाइक से भी मुलाकात की और अपनी मांग रखी. जव्वाद का कहना है कि अंग्रेजों के बाद सपाइयों ने ही धर्मगुरुओं पर लाठियां चलवाई हैं. ■

ज़फ़रयाब जिलानी

मौलाना दरयाबादी

अब्दुल सुबहान क़ुरैशी

मौलाना अतहर अली

शिया भी इराक जाने को तैयार

बड़ी संख्या में शिया समुदाय के युवक भी इराक जाने के लिए तैयार हैं. उनकी भी इच्छा है कि वे इराक के शिया धर्मस्थलों पर आईएसआईएस के विध्वंसक हमलों के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरें और अपने धर्मस्थलों की रक्षा करें. तक़रीबन 30 हज़ार शिया युवकों ने विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों को अपने पासपोर्ट दिए हैं और इराक जाने की व्यवस्था करने को कहा है. एक लाख से अधिक शिया युवकों ने इराक के शियाओं के प्रति अपना समर्थन जताया है. भारत में सुन्नियों की आबादी अधिक है, लेकिन शिया समुदाय के भी क़रीब चार-पांच करोड़ लोग यहां रहते हैं. इराक में लड़ने के लिए शियाओं की भर्ती का काम अंजुमन-ए- हैदरी नामक संस्था कर रही है. इस संस्था से जुड़े सैयद बिलाल हुसैन आबिदी इराक जाने की चाहत रखने वाले शिया युवकों का वीज़ा एप्लिकेशन दिल्ली स्थित इराकी दूतावास में जमा करने जा रहे हैं. दिल्ली के कर्बला रोड पर अंजुमने हैदरी का दफ्तर है. शियाओं की संस्था ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड यह कह चुका कि चार हज़ार शिया युवकों ने इराक जाने का आवेदन कर रखा है.■

मौलाना सलमान नदवी की सफाई

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام مسلمانوں کو مطلع کیا جاتا ہے، کہ سیریا اور عراق کے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف جو عوامی مسلح تحریک چل رہی ہے، اس میں جناب ابوبکر البغدادی کی تحریک "داعش" نے شام کے متعدد علاقوں کے بعد عراق کے شہر موصل اور دیگر شہروں کو نوری مالکی جیسے جابر اور مجرم کے قبضہ سے آزاد کرا کر جو نام روشن کیا تھا، اس کی بنیاد پر میں نے ایک کھلے خط میں بغدادی صاحب سے مطالبہ کیا تھا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ امن قائم کریں، انصاف کریں، مفتوحہ علاقوں میں عفو عام سے کام لیں، اور شیعہ و سنی فرقہ واریت کو دفن کر دیں۔

میں نے ۷ر جولائی کو یہ خط لکھا تھا، جس کے خلاف فرقہ واریت پھیلانے کے لئے بعض لوگوں نے مہم چھیڑی، اور "آگ" اخبار نے پہلے صفحہ کی شاہ سرخی میں فرقہ واریت کا زہر اگلا، جس کے بعد میں نے اخبارات میں بیانات بھی دیئے، کہ یہ صحافتی بددیانتی کی بدترین شکل ہے، کہ امن، عدل و انصاف، اور شیعہ و سنی بھائی چارہ کی دعوت کو الٹے معنی پہنا کر امن کو نقصان پہونچانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔

بہر حال حالات پر میری نگاہ رہی، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہ داعش سے انسانی بنیادوں پر جو مطالبات ہم نے کیے وہ پورے نہیں ہوئے، بلکہ داعش کی بعد کی کارروائیوں نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

۱- مذہب و مسلک کی بنیاد پر قتل کی کارروائیاں۔

۲- دیگر اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں غالیانہ اور متشددانہ موقف، اور ان کی تکفیر، اور ارتداد کی باتیں، بالخصوص جبهة النصرة اور الاخوان المسلمون کے بارے میں بے انتہا متشددانہ انداز۔

۳- موصل کے عیسائیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، جب کہ حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کی فتح کرتے ہوئے نہ صرف عیسائیوں کا گرجا گھر باقی رکھا، بلکہ نماز بھی اس کے باہر پڑھی، تا کہ بعد میں لوگ اسے زبردستی مسجد نہ بنا لیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو وہاں اہرامات جن کے اندر فرعونیوں کی قبریں ہیں، اور اس علاقہ کی دیگر مورتیوں کو نہیں توڑا، صحابہ کرام نے جب افغانستان کو فتح کیا تھا، تو بدھا کی مورتی کو نہیں توڑا، اور معاملہ اقلیتوں کے ساتھ رحمدلانہ اور مشفقانہ اختیار کیا، جس کے نتیجہ میں پورا ملک داخل اسلام ہو گیا، اسلئے "داعش" کی کارروائیاں اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہیں۔

۴- اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے مساجد اور مزارات کی اصلاح کی جگہ، ان کو توڑنا اسلامی فعل سمجھا، یہ بھی درست نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے مشرکوں کے ساتھ "أمرت أن اقاتل الناس" والی بات فرمائی تھی، جبکہ حکم سورہ براءت میں نازل ہوا تھا، اس لئے وہاں جو احکامات آپ نے دیئے وہ وہاں کے ساتھ مخصوص تھے، کیوں کہ جزیرۃ العرب کو ایک خصوصی حیثیت دی گئی تھی، دیگر ممالک کی فتوحات میں صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا۔

ان کارروائیوں سے داعش کی قیادت کی تنگ نظری، تشدد اور اسلام کی جھوٹی سلفی نمائندگی نظر آ رہی ہے، جو اسلام اور عالم اسلام کے لئے مضر ہے۔

ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد میں تمام مسلمانوں کو مطلع کرتا ہوں کہ "داعش" کے نعروں سے دھوکہ نہ کھائیں، اور جب تک وہ عدل و انصاف اور اسلام کی وسیع النظری کا ثبوت نہ دیں، ان سے متاثر نہ ہوں۔

ساتھ ہی ساتھ میں شیعہ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوں کی دلآزاری کو اپنا مذہب نہ بنائیں، اسلام کی نسبت ہی ظاہر کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، صحابہ اور اہل بیت میں تفریق نہ کریں، میں فرزند حسین ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے آباء و اجداد اور تمام اہلبیت کا یہی مسلک رہا ہے، سیدنا حسنؓ اور سیدنا حسینؓ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، سیدنا حسنؓ نے جن سے صلح کی، ان سے ہماری صلح ہے، اور سیدنا حسینؓ نے جن سے جنگ کی ان سے ہماری جنگ ہے، اسی متفقہ رائے کو اختیار کر کے، عالم اسلام اور مسلمانوں کے اتحاد کو موضوع بنائیں۔

میری سارے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اسرائیل کے خلاف "حماس" اور "القسام" اور "الاخوان المسلمون" کے ساتھ کھڑے ہوں، دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کریں، مصر کی موجودہ اسرائیل نواز بلکہ "یہودیوں" کی ایجنٹ حکومت اور اس کی مددگار خلیجی حکومتوں کی پالیسیوں سے اپنی نفرت اور براءت کا اظہار کریں۔

سعودیوں سے عراق میں لڑنے کے لئے پانچ لاکھ کی فوج تیار کرنے کی بات جن انگریزی اخبارات نے لکھی، وہ بادلوں اور سکیون کی باتیں ہیں، میں سمجھتا تھا کہ انگریزی اخبار کی صحافت زیادہ باوقار ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ "کوا کان لے گیا" کا شور مچاتی ہے، اور "دیہاتی بڑھی" سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔

امید ہے کہ اب میرا یہ بیان آخری سمجھا جائیگا، اور میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی جائیگی۔

سلمان الحسینی

اگست ۲۰۱۴

पत्र के मुख्य अंश

- मैंने 5 लाख फौजी भेजने की बात नहीं की.
- मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया.
- इराक़ में हो रहा क़त्ले आम ग़लत है.
- इबादतगाहों को तोड़ना ग़लत है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 23
दिल्ली, 11 अगस्त-17 अगस्त 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

दिल्ली से जाने में आनाकानी

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात कुछ बाबू दिल्ली में जड़ जमा चुके हैं और अब अपने मूल कैडर में लौटने के प्रति अनिच्छुक हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव अमित खरे का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और उनके लिए अब राजधानी छोड़ने का समय है. क्या वह ऐसा करेंगे? सूत्रों का कहना है कि खरे की सेवा बनाए रखने के लिए प्रयास चल रहे हैं. जाहिर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बिहार कैडर एवं 1985 बैच के इस आईएएस अधिकारी के लिए एक साल के विस्तार की मांग की है. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो वह शास्त्री भवन में सबसे लंबे समय तक सेवारत नौकरशाह होंगे. खरे चाईबासा के उपायुक्त रहते हुए बिहार में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला उजागर करके 1996 में सुर्खियों में आए थे. वह कथित तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा चुने और दिल्ली लाए गए थे. वह तबसे कपिल सिब्बल, एम एम पल्लम राजू और अब स्मृति ईरानी के साथ काम कर रहे हैं. यह भी ख़बर आ रही है कि खरे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के सदस्य सचिव के पद के दावेदार हैं. जाहिर है, वह एक बहुत ही सक्षम बाबू हैं! ■

आईएएस से सावधान ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और यहां तक कि सेवानिवृत्त लोगों से भी सावधान हैं. परंपरा से हटते हुए उन्होंने हाल में पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी एस आर उपाध्याय को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद के लिए नामित किया है. अब तक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के पूल से इस पद को भरा जाता था. सूत्रों का कहना है कि सुश्री बनर्जी का राज्य पंचायत चुनाव के दौरान मनमाफिक काम न करने की वजह से पूर्ववर्ती अधिकारी मीरा पांडे के साथ एक विवादास्पद रिश्ता था. विशेष सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए उपाध्याय पश्चिम

बंगाल के छठवें चुनाव आयुक्त होंगे. वह इस पद पर आने वाले राज्य सिविल सेवा के पहले बाबू हैं. पश्चिम बंगाल में बाबू बिरादरी सरकार के फ़ैसले पर विभाजित है. पूर्व आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों ने इसे अभूतपूर्व कहा है और वे इस आदेश को लेकर उलझन में हैं. वहीं अन्य बाबू आईएएस के गढ़ में सेंध लगने पर खुश हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

मुंद्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर

बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस एस मुंद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे. वह अपने वर्तमान पद से कुछ दिनों बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, तभी केंद्र सरकार ने उनकी नई नियुक्ति की घोषणा कर दी.

प्रकाश विशेष सचिव बनेंगे

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रकाश मिश्रा गृह मंत्रालय के अंतर्गत विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किए जाएंगे. यह पद अक्टूबर 2014 से 1977 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी एस जयराम के सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से रिक्त था. कई बार इस पद को भरने के प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली.

नवतेज विदेश मंत्रालय पहुंचे

केंद्र की पदस्थापना समिति ने 1980 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी नवतेज सिंह को विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव (पश्चिम) नियुक्त किया है. वह दिनकर खुल्लर का स्थान लेंगे, जो आगामी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को तीन वर्ष के अंदर तीन लाख शिक्षक नियोजित करने थे, लेकिन अभी तक एक लाख शिक्षकों का भी नियोजन नहीं हो सका. विभाग के प्रवक्ता आर एस सिंह के अनुसार, अब सारी अड़चनें समाप्त हो गई हैं और नियोजन प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी. लेकिन कब तक? इसका जवाब विभाग के पास नहीं है. हालत यह है कि पूर्व में नियोजित सभी शिक्षकों के प्रमाण–पत्रों का अभी तक सत्यापन नहीं हो सका. खुद विभागीय अधिकारी मानते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं.

गांधी को नहीं जानती हैं अरुंधति राय

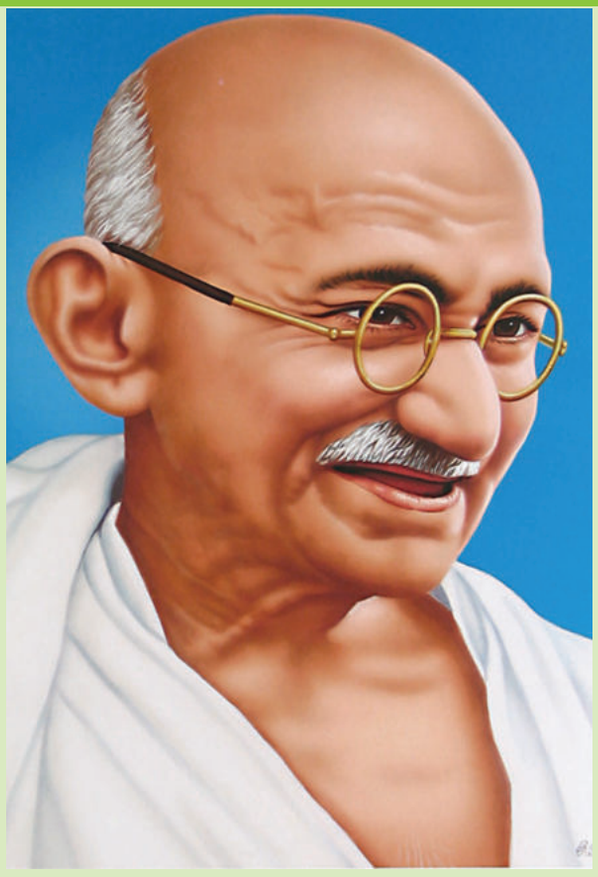

बुकर पुरस्कार से सम्मानित मशहूर लेखिका अरुंधति राय ने पिछले दिनों केरल विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि महात्मा गांधी जातिवादी थे. अरुंधति के मुताबिक़, अब समय आ गया है कि गांधी के नाम पर बने शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदल देने चाहिए और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से ही करनी चाहिए.

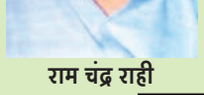

राम चंद्र राही

सचमुच जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, वे भयंकरतम आहत करने वाली घटनाओं से गुजर चुके हैं. वह 30 जनवरी, 1948 का दिन था. उससे बड़ी आहत करने वाली घटना क्या हो सकती है. हकीकत यह है कि हम लोग स्वभाव से लोकतांत्रिक नहीं हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी ही बात मानी जाए, ऐसा आग्रह रखा जाना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है. जितना यह आवश्यक है कि जितनी हमारी बात सुनी जाए, हमें अपनी बात कहने की आज़ादी हो, उतनी ही ज़रूरी बात यह है लोकतंत्र के लिए कि अपने से भिन्न विचार सुनने का धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए. 30 जनवरी, 1948 को जिस विचारधारा ने गांधी जी को अपनी कल्पना का राष्ट्र बनाने में अवरोध के रूप में देखा, उसी विचारधारा ने उनकी हत्या करने की प्रेरणा दी. गांधी अपनी साधना, सत्य एवं अहिंसा के प्रति निष्ठा, अपने अपूर्व क्रांतिकारी प्रयोगों और उनके परिणामों के कारण लोकमान्य हुए. यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी अपने व्यक्तिगत सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में विभिन्न अहिंसक शक्ति के प्रयोगों के परिणामस्वरूप स्वीकार्य हुए थे. वह ग्रंथ की उपज नहीं थे. लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़कर और ग्रंथों के अध्ययन से किसी विषय के जानने–समझने के अभ्यासी हैं. हमारे लिए गांधी को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गांधी एक अभिनव संघर्ष के बीच से निखरे हुए व्यक्ति हैं.

उन्हें उनके विचारों और प्रयोगों को एक साथ सामने रखकर समझने की कोशिश करनी पड़ती है. दुनिया में कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, जिसका कहीं न कहीं, किसी न किसी द्वारा विरोध न हुआ हो. खासकर ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने निर्भयता के साथ अपने अनुभूत सत्य को, प्रयोगसिद्ध सत्य को समाज के सामने रखने का साहस किया. इतिहास साक्षी है कि उन्हें इसकी भारी क़ीमत भी चुकानी पड़ी है. गांधी उन्हीं साहसी प्रयोगवीरों में एक अनुपम व्यक्ति हैं. अरुंधति रॉय ने गांधी की जो आलोचना की है, उसे पूरी तरह मैंने पढ़ा नहीं है. समाचारों के रूप में छिट–पुट सुना और पढ़ा है. वह एक ख्याति प्राप्त, बहुचर्चित लेखिका हैं, विश्व स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. उनका एक बड़ा पाठक वर्ग होगा. इधर के कुछ वर्षों में उन्होंने गांधी के विचारों को मानने वाले जन–आंदोलनों से जुड़कर कुछ करने की भी कोशिश की है, लेकिन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए किन्हीं विचारों और मूल्यों के आधार पर सीधे संघर्ष में उतरना अपने पर दांव लगाने जैसा होता है. जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने जन–आंदोलनों में आंशिक भागीदारी की है. कुछ समय और शायद यत्र–तत्र धन भी खर्च किया है, लेकिन शायद वह भी यह दावा नहीं कर पाएंगी कि समाज की किसी समस्या को हल करने के लिए स्वयं को उन्होंने दांव पर लगाया हो, अपने अस्तित्व और सुरक्षा के आधार को ख़तरे में डाला हो. ग्रंथों के लिखने और संवादों द्वारा अपने विचार लोगों तक पहुंचाने, उनको मान्यता दिलाने की कोशिश और गांधी के अहिंसक संघर्ष के प्रयोगों में एक बुनियादी फर्क है. गांधी स्वयं को दांव पर लगा देते हैं, अपने अनुभूत सत्य को प्रयोगसिद्ध करने के लिए और इसी बिंदु पर आकर हम भारत की जाति व्यवस्था के प्रति गांधी के दृष्टिकोण और प्रयोगों को समझना चाहेंगे.

अस्पृश्यता भारत के माथे पर एक कलंक है, यह गांधी ने महसूस किया, तो केवल उन्होंने इसके बारे में लेख नहीं लिखे. उन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ क्रांतिकारी और बुनियादी क़दम उठाए. सफाई का काम अस्पृश्यता के भाव को टिकाए रखने का सबसे बड़ा आधार था और उन्होंने अपने आश्रमों में स्वयं परिवार और सहयोगियों के साथ सफाई का कार्य शुरू किया, जिसमें पाखाना सफाई भी शामिल था. मैं स्वयं जब गांधी विचार की एक संस्था में वर्ष 1956 में दाखिल हुआ, तो मुझे दूसरे दिन से ही पाखाना सफाई का काम सहजता के साथ स्वीकार करना पड़ा. जाति व्यवस्था में सवर्ण और अवर्ण या छूत और अछूत के भेद की सबसे मजबूत बुनियाद है, रोटी–बेटी के संबंधों के समय ऊंच–नीच की भावना का निर्णायक रूप में प्रस्तुत होना. गांधी के जीवन को थोड़ा भी जानने और समझने वाला इससे अवगत होगा कि साबरमती आश्रम के रसोई घर में दलित की सादर उपस्थिति से परिवार में पैदा हुए विवाद के दौरान गांधी जी ने अपनी बहन को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहा था और उस दलित को रसोई घर में बनाए रखा. इसी तरह गांधी जी ने यह घोषणा कर रखी थी कि मैं उन्हीं शादियों में शामिल होऊंगा, जिनमें एक पक्ष दलित समुदाय का होगा. अध्ययन करने वालों को इस विषय पर भी शोध करना चाहिए कि गांधी की प्रेरणा से कितनी शादियां दलित और सवर्ण या छूत और अछूत परिवारों के बीच हुई थीं. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आंध्र प्रदेश के श्री रामचंद्र राव गोरा का. वह स्वयं ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मण और दलित के बीच भेद पैदा करने वाले सारे विभाजनकारी तत्वों को अपने जीवन से, परिवार से निकाल बाहर किया था. उनके सभी लड़के और लड़कियों ने अंतरजातीय विवाह किए थे. गांधी विचार को मानने वाले देश भर में ऐसे एक नहीं, बल्कि अनेक उदाहरण हैं, जहां शादी के रिश्तों में छूत और अछूत के भेद को व्यवहार में समाप्त किया.

महात्मा गांधी ने जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, तो दलितों की सेवा के लिए बनाई गई उस संस्था की ज़िम्मेदारी सवर्ण समुदाय के लोगों को सौंपी और कहा कि सदियों–सदियों से सताए गए इन दलितों की सेवा हम सबको प्रायश्चित भाव से करनी है और हरिजन सेवक संघ का काम इसी आधार पर आगे बढ़ा. गांधी जी एक गतिशील व्यक्तित्व के रूप में देखे जाने चाहिए. गतिशीलता का अर्थ यह है और इसमें वैज्ञानिकता भी है कि अगर कल तक हमारी यह मान्यता थी और आज वह गलत सिद्ध हो रही है, तो हमें खुले मन से और नि:संकोच उसे छोड़ना चाहिए और नई भूमिका में आना चाहिए. यह ठीक है कि गांधी ने शुरू में वर्ण व्यवस्था की कुछ अच्छाइयों को माना था, लेकिन जैसे–जैसे शास्त्रों के दायरे निकल कर गांधी समाज के जीवन में पैठते गए और हकीकतों से रूबरू हुए, तो उन्होंने पाया कि भारत के बुनियाद को कमजोर करने वाले तत्वों में अस्पृश्यता या जाति व्यवस्था सबसे अधिक विध्वंसक भूमिका अदा करती है.

बावजूद इसके बीच–बीच में अरुंधति राय जैसे किताबी लोग या राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे लोग गांधी के बारे में ऐसे बेबुनियादी सवाल उठाते रहे हैं. वर्षों पहले जब बहन मायावती जी ने राजनीति में प्रवेश किया था, तो गांधी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन भाजपाई मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं. और अब, अरुंधति राय ने गांधी पर जातिवादी होने का आरोप मढ़ा है. प्रख्यात व्यंग्यकार स्वर्गीय हरिशंकर परिसाई ने एक बार अपने एक व्यंग्य लेख में एक कहानी प्रस्तुत की थी, जिसके नायक ने अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने प्रवचन का विषय घोषित किया था, भगवान बुद्ध की बेवकूफियां. इसी तरह अनेक अपकथनों से उसने स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की कोशिशें की, जो अंतत: विफल हुईं.

मैं नहीं जानता कि अरुंधति राय किस मकसद से गांधी जी को जातिवादी घोषित कर रही हैं, पर मुझे इसका जरा भी भय नहीं है कि उनके ऐसे लेखों एवं भाषणों से इस देश की जनता और दुनिया के उन करोड़ों लोगों, जो गांधी को जानने–समझने में जुटे हैं, की धारणा बदल जाएगी और वे गांधी को जातिवादी मानने लगेंगे. गांधी जी आज एक विश्व मानव के रूप में स्थापित हैं और दुनिया के चिंतक एवं विचारक उनके विचार दर्शन को मानवता के भविष्य के रूप में स्वीकार करते हैं. यह संभव है कि अरुंधति राय इस तरह की बातें करके कुछ समय तक अख़बारों और अन्य सूचना प्रसारण तंत्रों की चर्चाओं में बनी रहें, लेकिन इससे उनका कोई स्थायी लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा. मैं अरुंधति राय से जन–आंदोलनों के संदर्भ में एक–दो बार मिला हूं. उनकी लेखकीय एवं बौद्धिक क्षमता के प्रति मेरे मन में आदर है और मेरी सलाह यही है कि वह गांधी जैसे लोगों को छोटा सिद्ध करने की कोशिश के बदले ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने विचार और कर्म द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाएं, तो बेहतर होगा. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. ■

रामचंद्र राही (सचिव, गांधी स्मारक निधि) से चौथी दुनिया संवाददाता अभिषेक रंजन सिंह की बातचीत पर आधारित)

बिहार

भूखे भजन न होएं गोपाला...

अवनींद्र नाथ ठाकुर

प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नियोजित शिक्षकों को बैंक द्वारा नियमित रूप से वेतन भुगतान करने की सरकारी योजना अब तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सकी है, जबकि यह कवायद दो वर्षों से जारी है. नियोजित शिक्षकों को पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से वेतन भुगतान करने की व्यवस्था लालफीताशाही का शिकार बन चुकी है. शिक्षकों को छह माह से वेतन का चांद नज़र नहीं आ रहा है. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी हो चुकी है. शिक्षकों द्वारा सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी धरना–प्रदर्शन ने भी मांझी सरकार की कश्ती डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

राज्य सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों को उनके पदस्थापन ज़िले के चिन्हित बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा, मगर यह योजना आंशिक रूप से ही क्रियान्वित हो सकी है. निर्णय के तहत तमाम नियोजन इकाइयों द्वारा अपने बैंक खाते संबंधित बैंक में खोले जाने थे और उन्हें शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए एक स्टैंडिंग एडवाइस भी संबंधित बैंक को देनी थी, लेकिन सब कुछ कछुवा गति से चल रहा है और शिक्षक हाल–बेहाल इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं. शिक्षा विभाग ने ज़िलास्तरीय अधिकारियों को इस संदर्भ में कई स्मरण पत्र भी भेजे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी. शिक्षा विभाग ने फरवरी माह तक सभी शिक्षकों का बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन यह काम आज तक पूरा नहीं हो सका.

उधर अस्थायी शिक्षक अपनी सेवा स्थायी करने और सरकारी वेतनमान देने के लिए दबाव डाल रहे हैं. उनका तर्क है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए. मौक़े की नजाकत देखते हुए विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप–मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अस्थायी शिक्षकों की सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि मोदी जब खुद उप–मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सरकारी वेतनमान देने और सेवा स्थायी करने की मांग मानने से साफ़ इंकार करते हुए कहा था कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं. अब जदयू से अलग होने के बाद विधानसभा चुनाव में शिक्षकों का समर्थन जुटाने की खातिर उन्होंने पैतरा बदल लिया है.

राज्य सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों को उनके पदस्थापन ज़िले के चिन्हित बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा, मगर यह योजना आंशिक रूप से ही क्रियान्वित हो सकी है. निर्णय के तहत तमाम नियोजन इकाइयों द्वारा अपने बैंक खाते संबंधित बैंक में खोले जाने थे और उन्हें शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए एक स्टैंडिंग एडवाइस भी संबंधित बैंक को देनी थी, लेकिन सब कुछ कछुवा गति से चल रहा है और शिक्षक हाल–बेहाल इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को तीन वर्ष के अंदर तीन लाख शिक्षक नियोजित करने थे, लेकिन अभी तक एक लाख शिक्षकों का भी नियोजन नहीं हो सका. विभाग के प्रवक्ता आर एस सिंह के अनुसार, अब सारी अड़चनें समाप्त हो गई हैं और नियोजन प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी. लेकिन कब तक? इसका जवाब विभाग के पास नहीं है. हालत यह है कि पूर्व में नियोजित सभी शिक्षकों के प्रमाण–पत्रों का अभी तक सत्यापन नहीं हो सका. खुद विभागीय अधिकारी मानते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं. विगत वर्षों में लाखों शिक्षकों के नियोजन के बावजूद छात्र–शिक्षक अनुपात 58:1 है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह अनुपात 30:1 होना चाहिए. ग़ौरतलब है कि संविधान की धारा 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है. नए स्कूल खुले हैं, प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण भी हुआ है, लेकिन छात्र–शिक्षक अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ. ■

feedback@chauthiduniya.com

> हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद जितने भी राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किए गए, सभी ने पृथक विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की. इसके बावजूद 108 साल पुरानी इस मांग पर अब तक किसी भी सरकार (केंद्र एवं राज्य) ने न्याय करने की ज़रूरत नहीं समझी. इसकी वजह विदर्भ के राजनीतिक नेतृत्व का कमजोर होना रहा, लेकिन वर्तमान में स्थितियों में बदलाव आया है. भाजपा, जो छोटे राज्यों के गठन की समर्थक है, उसकी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है.

पृथक विदर्भ क्यों?

प्रवीण महाजन

विदर्भ राज्य की मांग 108 साल पुरानी है. यह मांग सर्वप्रथम 1905 में उठाई गई थी, जब बेरार ज़िला निजामशाही से मुक्त होकर अंग्रेजों के अधीन आ गया था. 1938 में सीपी एंड बेरार राज्य विधानसभा ने मराठी भाषियों के लिए अलग विदर्भ राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था. स्वतंत्रता के बाद राज्य गठन आयोग ने भी विदर्भ राज्य की सिफारिश की थी. 1948 में जेवीपी (पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉ. पट्टाभि सीतारमैया) कमेटी ने भी विदर्भ राज्य बनाने की सिफारिश की थी. राज्य पुनर्गठन आयोग ने विदर्भ राज्य की बार-बार अनुशंसा की. इसके बावजूद विदर्भ राज्य नहीं बन पाया. इसके बाद कई छोटे राज्यों का गठन हुआ, लेकिन राजनीतिक बिसात पर विदर्भ को हमेशा मात मिलती रही. पिछले 54 सालों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे विदर्भ का उद्धार तभी है, जब वह महाराष्ट्र की गुलामी से मुक्त हो जाए. यह मत स्पष्ट रूप से विदर्भ की जनता का है और इसकी अभिव्यक्ति जनमंच, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति एवं नवराज्य निर्माण महासंघ (भारत) विदर्भ द्वारा विभिन्न ज़िलों में कराए गए जनमत संग्रह से हो चुकी है. बावजूद इसके राज्य सरकार विदर्भ का पिछड़ापन दूर करने के प्रति गंभीर नज़र नहीं आती. पश्चिम महाराष्ट्र का सरकार में दबदबा होने के कारण विदर्भ की उपेक्षा बदस्तूर जारी है. स्वतंत्र तेलंगाना की मांग विदर्भ के बाद शुरू हुई थी और उसका गठन हो भी गया, लेकिन विदर्भ के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ. विदर्भ की परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि में भी कटौती करके पश्चिम महाराष्ट्र का पेट भरा जाता रहा.

लगता है, विदर्भ को महाराष्ट्र में पिछड़ेपन के लिए ही जोड़ा गया. जब-जब पृथक विदर्भ के लिए आंदोलन हुआ, संयुक्त महाराष्ट्र के पैरोकारों ने फूट डालकर उसे विफल करने का षड्यंत्र किया. बार-बार एक ही तर्क देकर कि अलग होने पर विदर्भ की सरकार के पास इतना भी राजस्व नहीं होगा कि वह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन दे सके, विदर्भ की जनता को ठगा-छला गया. राजनीतिक, औद्योगिक एवं भौगोलिक दृष्टि से विदर्भ एक समृद्धशाली राज्य बनने की क्षमता रखता है. प्रकृति ने भरपूर वन संपदा-खनिज भंडार की सौगात विदर्भ को दी है. जल संपदा भी पर्याप्त है, लेकिन संसाधनों के अभाव और सरकारी नियम-कायदों के चलते उसका दोहन जनहित में नहीं किया जा सका. विदर्भ के हिस्से में जो भी बड़ी परियोजनाएं आईं, उन्हें सरकार ने कभी फलीभूत होने नहीं दिया. महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना गोसीखुर्द, जिसके निर्माण कार्य से नेता-ठेकेदार मालामाल होते रहे हैं, लेकिन गोसीखुर्द पिछले 27-28 सालों से अपने अधूरेपन को लेकर सिसक रही है. इस परियोजना के चलते विस्थापित हुए लोग आज भी मुआवजे और पुनर्वास के लिए शासन-प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं. कहने को नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत बूटीबोरी भी है, परंतु वहां स्थापित होने वाले उद्योगों को सरकार पर्याप्त बिजली-पानी मुहैया कराने के प्रति कभी गंभीर नहीं रही. नतीजतन उद्योगों का पलायन अन्य जगहों या राज्यों में होने लगा.

विदर्भ में उत्पादित बिजली से मुंबई सहित अन्य इलाके जगमगा रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनता के नसीब में सतत बिजली कटौती की मार डाल दी गई है. यहां के किसान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं. युवक-युवतियां रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं. सरकारी नौकरियों में पश्चिम महाराष्ट्र का दबदबा है, विदर्भ की हिस्सेदारी मात्र 8 फ़ीसद है. पिछले 7-8 सालों से नागपुर में मिहान प्रकल्प, कार्गो हब बनाने का ढिंढोरा सरकार और राजनेताओं द्वारा पीटा जा रहा है. बेरोज़गार युवा आस लगाए बैठे हैं कि कब उनके भाग्य खुलेंगे और उन्हें घर के पास नौकरी मिलेगी, जिससे वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर सकेंगे. जिस गति से मिहान का कार्य चल रहा है, उससे तो लगता है कि अभी 25 साल और लगेंगे. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने घोषणा की कि मिहान उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे साकार करने के लिए वह पूरा जोर लगा देंगे. जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि विदर्भ के युवाओं को मिहान के साकार होने का इंतज़ार कब तक करना होगा, कहा नहीं जा सकता. वजह मुंबई में बैठने वाली कोई भी सरकार विदर्भ के साथ न्याय कर पाएगी, इसका भरोसा यहां की जनता को नहीं है. इसलिए अब एक ही बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य का गठन होना ही चाहिए. बिना अलग हुए विदर्भ का उद्धार नहीं होने वाला. यह आवाज़ हर राजनीतिक दल से उठ रही है, मात्र शिवसेना को छोड़कर. डर यह सता रहा है कि कहीं मिहान का भी हश्र बूटीबोरी औद्योगिक वसाहत की तरह न हो जाए. यदि विदर्भ राज्य बनता है, तो यहां की सरकार गोसीखुर्द, मिहान जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी, जिससे यहां उद्योग स्थापित होंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को नौकरी के लिए पुणे-मुंबई पलायन नहीं करना पड़ेगा. सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं, तो किसानों के खेत पानी के अभाव में सूखेंगे नहीं. किसान आत्महत्या के कलंक से विदर्भ को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कृषि उपज आधारित उद्योग स्थापित कर उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार अपने भाषणों में किसानों का उद्धार करने की बात करते हैं. यहां पैदा हो रही बिजली से अपनी ज़रूरतें पूरी करके विदर्भ उसे अन्य राज्यों को भी बेच सकेगा. अलग होने पर विदर्भ अपना पिछड़ापन छोड़कर एक प्रगतिशील एवं विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना लेगा.

यदि भौगोलिक रूप से देखा जाए, तो विदर्भ में 11 ज़िले हैं. ब्रह्मपुरी और खामगांव ज़िलों के गठन की मांग मान ली जाए, तो यह संख्या 13 हो जाएगी. गढ़चिरौली ज़िले का विभाजन कर अहेरी ज़िले का गठन किया जाए, तो यह संख्या 14 हो जाएगी. यवतमाल में वणी को ज़िला बनाने की मांग मान ली जाए, तो यह संख्या 15 हो जाएगी. इस लिहाज से देखा जाए, तो विदर्भ में 65 की बजाय 90 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे. जब देश के अन्य हिस्सों में छोटे राज्यों का गठन हो सकता है, तो फिर पृथक विदर्भ का क्यों नहीं? विदर्भ हर लिहाज से राज्य बनने योग्य है. यहां राजधानी बनाने को लेकर भी न कोई समस्या है और न मतभेद. नागपुर पहले भी मध्य भारत की राजधानी रहा है और भविष्य में भी सारे संसाधनों के साथ तैयार है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करती रही है. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों का गठन किया था, तब भी पृथक विदर्भ की मांग उठी थी, लेकिन शिवसेना के विरोध के चलते विदर्भ के साथ न्याय नहीं हो सका. तेलंगाना राज्य के गठन के दौरान भी पृथक विदर्भ की मांग उठी, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार ने प्रणब मुखर्जी समिति का गठन करके उस पर पानी डालने का काम किया. कांग्रेस के वैदर्भीय नेताओं ने आलाकमान के आगे घुटने टेक दिए.

हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद जितने भी राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किए गए, सभी ने पृथक विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की. इसके बावजूद 108 साल पुरानी इस मांग पर अब तक किसी भी सरकार (केंद्र एवं राज्य) ने न्याय करने की ज़रूरत नहीं समझी. इसकी वजह विदर्भ के राजनीतिक नेतृत्व का कमजोर होना रहा, लेकिन वर्तमान में स्थितियों में बदलाव आया है. भाजपा, जो छोटे राज्यों के गठन की समर्थक है, उसकी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है. विदर्भ को राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में नितिन गडकरी जैसा पृथक विदर्भ समर्थक नेता भी मिला है. पूर्ण बहुमत होने के कारण अब शिवसेना के बाधक बनने का भी बहाना नहीं रह गया. इसके बावजूद यदि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे विरोध करते हैं, तो उन्हें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की वह घोषणा याद दिलाई जा सकती है, जिसमें उन्होंने शिवसेना-भाजपा सरकार बनने के पहले कहा था कि यदि दो वर्षों में विदर्भ का विकास न हुआ, तो मैं स्वयं विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग कर दूंगा. उनके जीवनकाल में विदर्भ का पिछड़ापन दूर हुआ नहीं, इसलिए पृथक विदर्भ का विरोध करने और संयुक्त महाराष्ट्र का दंभ भरने का शिवसेना को कोई अधिकार नहीं है. इसके अलावा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी को संसद न भेजकर विदर्भ की जनता ने अपने इरादे साफ़ कर दिए हैं. अब विदर्भ के साथ न्याय करने की ज़िम्मेदारी भाजपा सरकार की है, जिसने अपने तीन लोकसभा चुनावों के घोषणापत्रों में पृथक विदर्भ का समर्थन करते हुए अपनी सरकार बनने पर उसके गठन का वादा किया. अब वह अवसर आ गया है कि भाजपा अपना वादा पूरा करे. अपनी इस मांग को लेकर पृथक विदर्भ समर्थक सभी संगठनों ने नागपुर से दिल्ली तक आंदोलन करने का मन बनाया है. यदि सरकार नहीं चाहती है कि तेलंगाना की तरह अलग विदर्भ आंदोलन हिंसात्मक रूप ले, भारी जान-माल का नुक़सान हो, तो उसे इस मसले पर तत्काल क़दम उठाने की ज़रूरत है. ■

लेखक नवराज्य निर्माण महासंघ (भारत) विदर्भ प्रदेश के महासचिव हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पर्याप्त उत्पादन के बावजूद लोड शेडिंग की मार

महाराष्ट्र में सबसे अधिक बिजली उत्पादन विदर्भ में होता है. इसके बाद भी यहां के लोगों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ती है. राज्य सरकार ने विदर्भ में क़रीब 85 पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दी है. इसके अलावा क़रीब 50 प्रस्ताव मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं. विदर्भ की शोकांतिका यह है कि उसकी ज़मीन पर उक्त प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, वह भी कृषि योग्य भूमि पर. इतना ही नहीं, सिंचाई के पानी की धार भी पॉवर प्लांटों की ओर मोड़ दी गई है. पीने का पानी भी पॉवर प्लांटों को ज़रूरत पड़ने पर देने की तैयारी है. पॉवर प्लांटों के करार में यह प्रस्ताव सरकार की ओर से सम्मिलित किया गया है कि उनके द्वारा उत्पादित बिजली पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई को दी जाएगी. यानी ज़मीन, पानी एवं अन्य संसाधन विदर्भ के इस्तेमाल होंगे, लेकिन उसके हिस्से आएगा मात्र अर्सिंचन, प्रदूषण और लोड शेडिंग. शायद यही कारण है कि किसानों के खेत सूख रहे हैं, आत्महत्याएं निरंतर हो रही हैं और सरकार पैकेज का खेल खेलने में जुटी हुई है. ■

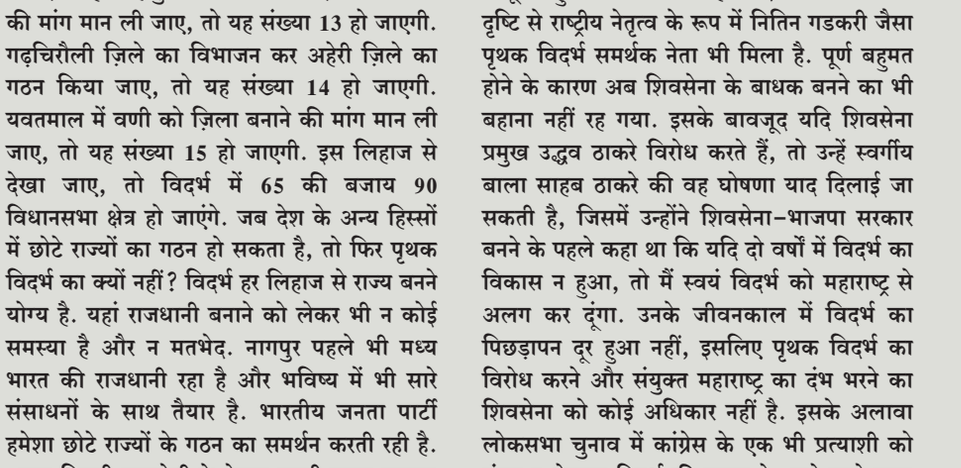

अनुच्छेद 371 (2) की व्यवस्था विफल

राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के तहत वैधानिक विकास मंडलों का गठन किया गया था, परंतु वह भी विदर्भ की दृष्टि से पूरी तरह विफल रहा. पहले तो 38 सालों तक उनके गठन को महत्व नहीं दिया गया. लंबे संघर्ष के बाद उन्हें वर्ष 1994 में स्थापित किया गया. हालांकि, विदर्भ वैधानिक विकास मंडल सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में कार्य करता है, पर इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति कहें या साजिश, राज्यपाल के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया. लिहाजा पश्चिम महाराष्ट्र का अनुशेष पूरा हो गया. मराठवाड़ा का पूरा होने के क़रीब है. मात्र एक विदर्भ ही ऐसा है, जिसका अनुशेष कम नहीं हो रहा. राजनीतिक दबदबे के कारण पश्चिम महाराष्ट्र ने अपना अनुशेष सबसे पहले पूरा किया और विदर्भ को उपेक्षित छोड़ दिया गया.

> राजनीतिक समीक्षकों की मानें तो यूपी की डामाडोल कानून–व्यवस्था पर राजनाथ की चुप्पी के पीछे मुलायम से उनकी नजदीकी एक बहुत बड़ी वजह है. गृह मंत्री बनने के बाद पिछले दिनों राजनाथ सिंह लखनऊ आए थे तब कुछ मीडियाकर्मियों ने लगातार बिगड़ती क़ानून–व्यवस्था के नाम पर अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का सवाल किया, तो राजनाथ सिंह ने महज यह कहकर इस सवाल को टाल दिया था कि समय आने पर देखा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि सपा सरकार की नीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है.

मोहनलालगंज कांड पर राजनाथ मुलायम क्यों...!

रवि कुमार

राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे मोहनलालगंज के बालसिंहखेड़ा गांव के एक प्राइमरी स्कूल प्रांगण में एक विधवा युवती के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. मीडिया ने गैंगरेप व हत्या की इस घटना को दिल्ली के दामिनी कांड से भी वीभत्स बताया तब जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई. और उदासीन पड़े शासन–प्रशासन भी इस वारदात को लेकर तेजी बरतना शुरू की. अंत में गाहे–बगाहे सपा सरकार भी चौतरफा दबाव के बाद गैंगरेप की इस घटना को लेकर गंभीर होती है और पुलिस प्रशासन को पारदर्शी ढंग से इस मामले की गहन जांच करने का फरमान जारी करती है. लेकिन राजनीतिक गलियारे से लेकर लखनऊ के आम लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोहनलालगंज कांड पर केंद्रीय गृहमंत्री और लखनऊ संसदीय के सांसद राजनाथ सिंह का रुख इतना मुलायम क्यों हैं! इस संवेदनशील कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री की चुप्पी का राज क्या है? कहीं इसकी वजह राजनाथ की मुलायम से नजदीकियां तो नहीं?

यहां सवाल उठना भी लाज़िमी है क्योंकि राजनाथ सिंह बतौर केंद्रीय गृह मंत्री पूरे देश की निगरानी के लिए स्थापित क़ानून–व्यवस्था की निगरानी तंत्र के मुखिया हैं. हालांकि जिस क्षेत्र में यह जघन्य कांड हुआ है वह राजधानी लखनऊ से तकरीबन 15–16 किमी की दूरी पर स्थित है. मोहनलालगंज संसदीय सीट भी भाजपा के ही कब्जे में है. ग़ौरतलब है कि मोहनलालगंज प्रकरण को लेकर अभी तक गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से मात्र एक औपचारिक रिपोर्ट ही तलब की है, यानी महज खानापूर्ती. इस मामले की रिपोर्ट कब पूरी होगी, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में आने व उनके बार–बार निर्देश देने के बावजूद इस कांड की जांच–पड़ताल की गुत्थी सुलझने के बजाए दिन–ब–दिन उलझती ही जा रही है. कभी पुलिसिया जांच में यह बताया जाता है कि युवति के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, यह केवल एक व्यक्ति की करतूत है. बहरहाल मामले की जांच अभी चल रही है. लेकिन गुत्थी सुलझने की बजाए उलझती चली जा रही है. मृतका के परिजन व तमाम सामाजिक संगठन रोजाना प्रर्दशन करके मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं. नतीजतन, यूपी में बदहाल होती कानून–व्यवस्था खासकर महिला सुरक्षा को लेकर हर दिन अखिलेश सरकार को कभी विरोधी राजनीतिक दलों के तो कभी सामाजिक संगठनों के बगावती सुर सुनने पड़ रहे हैं. सड़क से लेकर विधानसभा तक मोहनलालगंज कांड की गूंज सुनाई पड़ रही है. सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.

राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह कहना है कि लोस चुनाव में राजनाथ की राह को पहले मुलायम सिंह ने अहम भूमिका निभाई और केंद्र में सत्तासीन होने के बाद अब राजनाथ की बारी आ गई थी कि वे सपा प्रमुख का अहसान कैसे उतारें. प्रेक्षकों की मानें तो लोकसभा चुनाव में मात खाए मुलायम अब केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति में हैं.

इस सब से इतर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती कानून–व्यवस्था के मसले पर चुप्पी साध रखी है. यहां सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले प्रदेश की खस्ताहाल कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर राजनाथ सिंह सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके रुख में नरमी कैसे आ गई. सपा सरकार के खिलाफ वह कठोर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं. जबकि प्रदेश में आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है. आलम यह है कि मोहनलालगंज गैंगरेप पर पहले विवादास्पद बयान देने वाले यूपी के पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल अज़ीज कुरैशी ने भी प्रदेश से विदा होते–होते ही इस प्रकरण की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया था. अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मराठी नेता राम नाईक ने प्रदेश के राज्यपाल की कमान संभाल ली है, उन्होंने पहले भी यूपी की अनियंत्रित होती कानून–व्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी.

राजनीतिक समीक्षकों की मानें तो यूपी की डामाडोल होती कानून–व्यवस्था पर राजनाथ की चुप्पी के पीछे मुलायम से उनकी नजदीकी एक बहुत बड़ी वजह है. गृह मंत्री बनने के बाद पिछले दिनों राजनाथ सिंह लखनऊ आए थे तब कुछ मीडियाकर्मियों ने लगातार बिगड़ती क़ानून–व्यवस्था के नाम पर अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का सवाल किया तो राजनाथ सिंह ने महज यह कहकर इस सवाल को टाल दिया था कि समय आने पर देखा जाएग और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार की नीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है. वहीं मुलायम–राजनाथ के पुराने नजदीकी संबंधों को लेकर यूपी भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इसी दोस्ती की वजह से लोकसभा चुनाव के लिए एक साल पहले से घोषित लखनऊ लोकसभा सीट से सपा डॉ. अशोक बाजपेयी को हटाकर अंतिम समय में अखिलेश सरकार में मंत्री प्राफेसर अभिषेक मिश्रा को लखनऊ से उम्मीदवार बना दिया था, परिणामस्वरूप सपा उम्मीदवार के रूप में अभिषेक राजनाथ के आसपास कहीं ठहर नहीं पाए और वोटकटुआ की भूमिका निभाते हुए भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने की कुव्वत रखने वाली कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के ब्राह्मण वोटरों को काफी हद तक अपनी ओर खींच लिया. लोकसभा चुनाव के पूर्व जब भी राजनाथ लखनऊ पहुंचे उन्होंने विशेषकर कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर सपा सरकार को जमकर घेरा. यहां तक कि प्रदेश भाजपा की टीम ने भी इस मुद्दे पर लगातार सपा सरकार पर पलटवार किया. लेकिन जब मोहनलालगंज कांड को लेकर मीडिया से लेकर देश–प्रदेश के तमाम नागरिक संगठन और यहां तक कि दिखावटी ही सही प्रदेश सरकार भी हरकत में दिख रही है, तो केंद्र में बैठे राजनाथ औपचारिक भूमिका क्यों निभा रहे हैं?

राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह कहना है कि लोस चुनाव में राजनाथ की राह में पहले मुलायम सिंह ने अहम भूमिका निभाई और केंद्र में सत्तासीन होने के बाद अब राजनाथ की बारी आ गई थी कि वे सपा प्रमुख का अहसान कैसे उतारें. प्रेक्षकों की मानें तो लोकसभा चुनाव में मात खाए मुलायम अब केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति में हैं. ऐसे में उनकी और समस्त समाजवादी पार्टी की उम्मीदों की साइकिल अखिलेश सरकार के प्रदर्शन पर आकर टिक गई है. वर्तमान सपा सरकार का कार्यकाल लगभग आधा बीत चुका है. ऐसे में मुलायम व अखिलेश के अलावा पूरी सपा के राजनीतिक अस्तित्व का आधार अब यूपी ही रह गया है. ऐसे में प्रदेश में बदहाल कानून–व्यवस्था को लेकर सपा सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है. यदि शासनकाल के बीच में ही केंद्र की सिफारिश पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो सपा प्रमुख की बेचैनी बढ़ना लाज़िमी है. अब यही वक्त है जब राजनाथ मुलायम के काम आ सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

गुटबाज़ी और अतिउत्साह भाजपा को ले डूबा

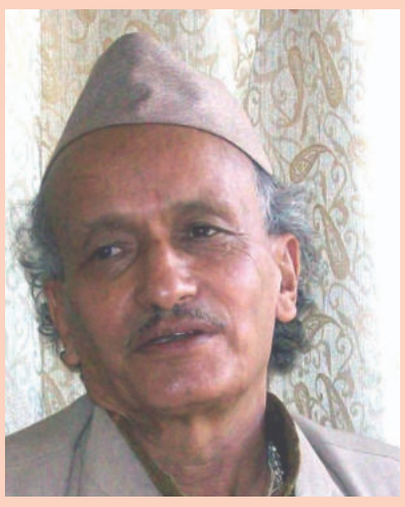

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में गुटों में विभाजित भारतीय जनता पार्टी के नेता इस क़दर आपस में भितरघात का खेल खेलने में मशगूल रहे कि राज्य में तीन विधानसभा सीटों पर हुए उप चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा. राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों भुवन चंद्र खंडूड़ी,भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक के तीन गुटों में बंटी भाजपा ने दो माह पूर्व हुए लोकसभा चुनावों में दो विधानसभा क्षेत्रों में शानदार बढ़त हासिल की थी वहां भाजपा को कांग्रेस प्रत्याशियों के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा है. सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी अल्पमत सरकार को बहुमत दिलाने के लिए जो ताना बाना बुना, उसमें भाजपा ऐसी उलझी कि सोमेश्वर व डोईवाला की महफूज समझी जाने वाली सीटें भी भाजपा गंवा बैठी.

डोईवाला सीट पहली बार कांग्रेस के कब्जे में आई है. 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में भी सोमेश्वर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. डोईवाला सीट पर निशंक को शानदार जीत मिली थी. मोदी लहर में संपन्न संसदीय चुनाव में भाजपा ने राज्य में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था और राज्य की पांचों लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया था. निशंक को हरिद्वार से सासंद बनाने में डोईवाला क्षेत्र की जनता ने बड़ी बढ़त प्रदान कर निशंक और मोदी दोनों का मान रखा था.

विधानसभा चुनाव में कोटद्वार से जनरल खंडूड़ी की हार के लिए हुई भितरघात के लिए पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर आरोप लगे थे. त्रिवेन्द्र सिंह की हार के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर निशंक पर भीतरघात करने का आरोप और उनके खिलाफ नारा भी लगाया. इस बार जब निशंक अपने चहेते को टिकट दिलाने में डोईवाला सीट से टिकट दिलाने में असफल हुए. राजनाथ सिंह के समर्थक खेमे के त्रिवेन्द्र सिंह रावत को डोईवाला से प्रत्याशी बनाया गया. इस वजह से निशंक पर कोटद्वार में खेले गए खेल की पुनरावृत्ति करने का आरोप लग रहा है. एक बार फिर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हार की वजह से सवालों के घेरे में है. चुनाव के दौरान किए गए अदूरदर्शी निर्णयों को भी पार्टी की हार से जोड़ कर देखा जा रहा है.

प्रदेश के तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव भाजपा के सूबाई नेतृत्व के लिए काफी अहम माने जा रहे थे. कारण यह कि लोकसभा चुनाव की जीत को मोदी लहर से जोड़ा गया, ऐसे में उपचुनावों में भाजपा प्रदेश नेतृत्व को खुद को साबित करने का मौका मिला था, वह उसमें वह नाकाम साबित हुई. भाजपा इन चुनावों में शुरू से ही कमजोर नजर आ रही थी. लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के सभी कद्दावर नेताओं के केंद्र की राजनीति में चले जाने से प्रदेश इकाई कमजोर हुई है. प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष के अलग–अलग गुटों से जुड़ने के कारण चुनाव में भाजपा तालमेल नहीं बैठा पाई. टिकट बंटवारे में भी यह गुटबाजी साफ नजर आई. भाजपा का प्रदेश नेतृत्व उपचुनावों में भी काफी हद तक मोदी लहर के भरोसे ही रहा जो इन चुनावों में कहीं नज़र नहीं आई. यहां तक कि भाजपा, कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी मुद्दा नहीं बना पाई. यही नहीं, प्रत्याशियों के चयन को लेकर व्यवहारिकता का ध्यान भी नहीं रखा गया. सोमेश्वर सीट पर जिस रेखा आर्य को भाजपा टिकट देने से कन्नी काटती रही, उन्होंने ने ऐन वक्त में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर दस हजार से अधिक मतों से इस सीट पर जीत दर्ज की. यहां तक कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव से भी भाजपा ने कोई सबक नहीं लिया. नतीजतन भाजपा को तीनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है. उपचुनाव में भाजपा की हुई करारी हार ने प्रदेश संगठन की कलई खोल कर रख दी है. सबसे खास बात यह है कि उपचुनाव के मतदान के एक सप्ताह पहले तक संगठन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि डोईवाला,धारचूला और सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के लिये पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में मिलकर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति को अंतिम रूप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. डोईवाला के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सोमेश्वर के भाजपा प्रत्याशी मोहन राम आर्य एवं धारचूला के प्रत्याशी बीडी जोशी ने स्वयं ही बूथ मैनेजमेंट को अंजाम दिया. सूत्रों की माने तो यदि संगठन की ओर से यह बात पहले ही बता दी गई होती, तो प्रत्याशी पहले से ही बूथ मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते. लिहाजा कम समय में प्रत्याशियों से जो बन पड़ा उतना उन्होंने किया. इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची भी प्रचार के लिये संगठन की ओर से जारी नहीं की गई जबकि कांग्रेस ने काफी पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी. स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता केवल प्रचार के नाम पर फर्ज अदायगी करते रहे. पार्टी के दिग्गज नेता तो प्रचार में उतरे ही नहीं. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही डोईवाला, धारचूला और सोमेश्वर में प्रचार के लिए पहल की उनके भी चुनावी दौरे की तिथि को प्रदेश भाजपा ने मंजूरी नहीं दी. व्यक्तिगत स्तर पर भाजपा प्रत्याशियों ने कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं को प्रचार के लिए बुलाया. प्रदेश भाजपा की ओर से अपने स्तर पर न ही कार्यकर्ताओं और न ही नेताओं के लिये कोई वाहन की व्यवस्था की गई. जो कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई वह प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर ही की. प्रदेश स्तर के कुछ हैवीवेट नेता जरूर अपने हिसाब से प्रचार के नाम पर इधर–उधर की राजनीति करने में जुटे रहे. उप चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि संगठन की ओर से थोड़ी बहुत भी मदद मिली होती तो पार्टी की उप चुनाव में इस तरह की दुर्दशा नहीं होती. प्रत्याशियों के मुताबिक संगठन की ओर से उप चुनाव को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रही. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठने वाले जिम्मेदार नेताओं से जब कभी भी आवश्यक चीजों की मांग की गई तो उनका एक ही जवाब मिलता कि मोदी लहर है इसलिये चिंता की कोई बात नहीं है. ज्यादा खर्च करने की जरूरत इस उप चुनाव में नहीं है. तीनों सीटें भाजपा की झोली में ही आएंगी.

मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमालयी आपदा की मार झेल रही जनता के प्रति अब तक कुछ भी नही किया है. इसी कारण राज्य की जनता ने भी मोदी को आईना दिखाने में भी देर नहीं की. मोदी ने अपने मंत्री मंडल के गठन में भी जिस तरह उत्तराखंड, हिमाचल के सांसदों को जगह नहीं दी, इसका असर भी मतदान पर पड़ा. हरीश रावत की जन सेवा रंग लाई, कांग्रेस जब देश में अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे समय मिली यह शानदार जीत कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर संजीवनी का काम करेगी. मोदी को भी एक बार आत्ममंथन करना होगा कि अपनी फिदरत से देश की सत्ता और भाजपा संगठन पर भले ही कब्जा हासिल कर लिया हो, लेकिन उन्हें जनता के भरोसे पर भी खरा उतरना होगा. जनता को लोगों को अर्श से फर्श पर बैठाने में देर नहीं लगती.■

feedback@chauthiduniya.com

पटना कब बनेगा पाटलिपुत्र

डॉ. अनिल सुलभ

ईसा से 304 वर्ष पूर्व भारत की यात्रा पर आए प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने यदि यह न लिखा होता कि भारत के इस महानतम नगर पाटलिपुत्र (पटना) की सुंदरता एवं वैभव का मुकाबला सुसा और एकबताना जैसे नगर भी नहीं कर सकते, तो शायद आज भारत के गंदे नगरों में गिना जाने वाला पटना कभी इतना सुंदर था, यह मानने के लिए लोग तैयार न होते. आज का पटना देखकर मेगास्थनीज के इस बयान पर सहसा विश्वास नहीं होता, किंतु यह यथार्थ है. मेगास्थनीज ने ही नहीं, इसके ठीक 715 साल बाद जब सन् 411 में विश्व विश्रुत चीनी यात्री फाहियान इस नगर में दाखिल हुआ, तो वह भी यहां की सुंदरता, वैभव एवं उच्च सांस्कृतिक छटा देखकर चकित और अभिभूत था.

सम्राट अशोक के राजमहल की चर्चा करते हुए एक जगह फाहियान ने लिखा है कि नगर के मध्य में स्थित राजमहल और अन्य आगार, जो अब पुराने हो गए हैं, ये सब किन्हीं आत्माओं के अशरीरी यानी दिव्य आत्माओं द्वारा बनाए गए मालूम होते हैं. जिस प्रकार पत्थरों के खम्भे, दीवार, द्वार और उन पर की गई नक्काशियां, स्थापत्य एवं मूर्ति कला का काम दिखता है, वह मनुष्यों द्वारा किसी भी प्रकार संभव नहीं है. पाटलिपुत्र इतने बड़े कालखंड तक न केवल देश की राजधानी होने का गौरव रखता था, बल्कि यह उच्च सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित था. चाहे वह मौर्यवंश का शासनकाल हो या गुप्त वंश का या फिर महान सम्राट अशोक का, वस्तुत: यह भारत के स्वर्णिम अतीत का दैदिप्यमान व्याख्यान था. नागरिक सुविधाओं एवं सामाजिक चेतना के धरातल पर यहां की व्यवस्था और नागरिकों की पहचान एक आदर्श के रूप में थी. पाटलिपुत्र अत्यंत समृद्धशाली था. गंगा, सोन एवं पुनपुन नदियों के त्रिकोण में अवस्थित और विस्तृत यह विशाल नगर वैभव का पर्याय माना जाता था. घरों में समृद्धि और सौंदर्य बोध सहज परिलक्षित होता था, किंतु पाटलिपुत्र के घरों में ताले नहीं लगा करते थे. यह एकमात्र सूचना सोचने पर विवश करती है कि कैसा रहा होगा पाटलिपुत्र? कैसी रही होगी उसकी शासन–व्यवस्था? और कैसे रहे होंगे वहां के नागरिक?

पाटलिपुत्र का अवसान वस्तुत: भारत की अधोगति का पर्याय बन गया. 9वीं शताब्दी के बाद भारत विदेशी आक्रांताओं एवं ग़ैर मुल्की हुक्मरानों की जागीर बन गया और यही स्थिति भारत की आज़ादी के पूर्व तक बनी रही. देश की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा दी गई. अकृतज्ञ देश ने धीरे–धीरे पाटलिपुत्र को भूलना शुरू कर दिया. दुनिया का यह सबसे खूबसूरत शहर विध्वंश का शिकार हो चुका था. अगली दो शताब्दियों तक इतिहास के पृष्ठों से हटकर एकदम से गुमनाम हो गया यह नगर. पुण्य सलिला गंगा किंकर्तव्यविमूढ़ सी पाटलिपुत्र की गौरव गाथा को गुमनामी के अंधेरे में जाती मूकदर्शक बनी देखती रह गई. इसके किनारे पर पत्तन पोर्ट भर रह गया था, जिससे जलमार्गीय व्यवसाय यहां होता रहा.

माना जाता है कि ग्यारहवीं–बारहवीं शताब्दी में इसी पत्तन के निकट एक जागृत देवी का आविर्भाव या प्राकट्य हुआ, जिसे शक्ति पीठ का स्थान हासिल हो चुका था. माना जाता है कि यह स्थल आध्यात्मिक दिव्यता से पुन: जागृत हुआ और पत्तन के निकट होने के कारण इस देवी को पत्तन देवी कहा जाने लगा. धीरे– धीरे यह स्थान पत्तन देवी के कारण ख्याति प्राप्त करने लगा और फिर एक नए नगर का उत्थान शुरू हुआ. कालांतर में इसे पत्तन कहा जाने लगा, जो अंग्रेजों के समय में अपभ्रंश होकर पटना हो गया. पाटलिपुत्र के अवसान के बाद और बिहार राज्य के पुनर्गठन तक यह नगर इतिहास में कोई विशेष स्थान नहीं बना सका. बंगाल से अलग होने के बाद जब बिहार राज्य का अस्तित्व बना, तो पटना उसकी राजधानी बना. तबसे यह नगर फिर से देश की मुख्य धारा में लौटा है. इसके पूर्व मध्यकाल में 1541 में जब भारत का तत्कालीन शासक शेरशाह सूरी बंगाल से जलमार्ग द्वारा लौटते हुए यहां पहुंचा था, तो यहां का वातावरण उसे भी रास आ गया. उसने यहां एक किले का निर्माण कराया. फिर बाद में इसे सूबे की प्रशासनिक राजधानी भी घोषित किया. लेकिन, शेरशाह के शीघ्र अवसान ने इसकी लौटती गरिमा को पुन: पीछे धकेल दिया. मुगल काल में अधिकांश समय तक इस सूबे की राजधानी बिहार शरीफ में रही.

समग्र इतिहास की जानकारी मिलने के बाद स्वाभाविक रूप से इस नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के मन में इसका नाम परिवर्तन करके फिर से पाटलिपुत्र करने की प्रेरणा जगनी शुरू हुई. यहां के नागरिक अपने पुराने गौरवशाली वैभव एवं उच्च सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने लगे और अपने लेखों–व्याख्यानों में अपने स्वर्णिम अतीत की गाथा उच्च स्वर में गाने भी लगे. पिछली शताब्दी में दुनिया के विभिन्न देशों एवं नगरों के नाम परिवर्तन की सूचना ने भी यहां के नागरिकों के मन में उम्मीद की नई किरण जगाई. पाटलिपुत्र की विदग्ध एवं पीड़ित आत्मा, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा छोड़े गए मलबे और पटना नामक छाया के नीचे दब गई थी, फिर से अपनी मुक्ति के लिए छटपटाने लगी.

नगर के प्रबुद्ध जनों ने इसका नाम पाटलिपुत्र करने के लिए पहली बार 1985–86 के दौरान एक मजबूत और ठोस पहल की थी. जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल मेजर जनरल एस के सिन्हा ने उस वक्त इस जनभावना की अगुवाई की. भारतीय सेना से अवकाश लेने के पश्चात उन्होंने इसे एक अभियान की शक्ल दी थी. लगभग एक लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त एक मांगपत्र भी सौंपा गया था, जिसमें पटना का नाम परिवर्तित कर उसे पाटलिपुत्र करने की बात कही गई थी. तत्कालीन सरकार ने भी नाम परिवर्तन की मांग को उचित माना था और उसकी औपचारिक स्वीकृति के लिए आवश्यक निर्णय लेने की अंतिम तैयारी भी कर ली गई. लेकिन, शायद तब वक्त को यह मंजूर नहीं था. जैसा कि आम तौर पर होता है, हर नेक काम के पीछे एक बुरा साया पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ और एक नई सुबह से पहले ही सूर्यग्रहण लग गया, जो आज तक जारी है.

पुन: दूसरी बार नगर के जागरूक प्रबुद्धजनों द्वारा इन पंक्तियों के लेखक (डॉ. अनिल सुलभ) की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र जागरण अभियान समिति नामक एक संस्था का गठन कर 2005 में यह आंदोलन आरंभ किया गया, जिसमें सभी समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुलकर भाग लिया. इस महत्वपूर्ण विषय पर सबकी एक राय थी. नगर के प्रत्येक चौक–चौराहों पर गोष्ठियां, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रम चलाए गए. त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति प्रो. अरुण कुमार, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल आर एस गवई, प्रसिद्ध समाजसेवी हारुन रशीद, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एस एन पी सिन्हा, मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेजर बलबीर सिंह भसीन समेत नगर के सभी बुद्धिजीवी और सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यकर्ता उत्साह के साथ इन आयोजनों में भाग ले रहे थे. 2007 में बिहार विधान परिषद में एक संकल्प लाकर सरकार से पटना का नाम परिवर्तित कर पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव रखा गया. प्रो. अरुण कुमार स्वयं सदन का सभापतित्व कर रहे थे. सदन में उपस्थित राज्य सरकार के प्राय: सभी मंत्रियों ने एक साथ खड़े होकर सदन में यह आश्वासन दिया कि पटना का महानगर के रूप में विस्तार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस विस्तृत नगर का नाम पाटलिपुत्र होगा. उत्तर देने वाले मंत्रियों में नंद किशोर यादव एवं अश्वनी चौबे भी शामिल थे, किंतु आज तक यह काम अन्य सरकारी आश्वासनों की तरह निरा–आश्वासन बनकर रह गया.

राज्य सरकार से बेहतर तो भारत का निर्वाचन आयोग सिद्ध हुआ, जिसने इस अभियान के संचालकों एवं पटना के सजग नागरिकों की भावनाओं का आदर करते हुए नए परिसीमन में पाटलिपुत्र नामक एक संसदीय क्षेत्र बनाया. भारत के सदन में अब पटना नहीं है. दूसरे क्षेत्र का नाम पटना साहिब है. इस दौरान देश के कई नगरों के नाम परिवर्तित कर दिए गए. बंबई मुंबई हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया और पांडिचेरी पुडुचेरी हो गया. लेकिन, इन सबसे पहले पटना का नाम बदल कर पाटलिपुत्र करने के लिए आवाज़ उठाई गई थी, मगर वह आज तक नहीं हो पाया. जबकि दुनिया में अब तक जितने नगरों एवं देशों के नाम बदले गए हैं, उन सबमें सबसे अधिक पात्रता इस नगर की है और पहला हक़ भी इसी का बनता है. यह हक़ पाटलिपुत्र को अब तक नहीं मिला. लेकिन, अतीत की काल कोठरी में कैद पाटलिपुत्र की आत्मा अब सभी दरो–दीवार तोड़कर बाहर निकल आने को व्याकुल है. देखना है कि पाटलिपुत्र के रूप में भारत की यह आत्मा कब कैद से मुक्त होती है? ■

पाटलिपुत्र का अवसान वस्तुत: भारत की अधोगति का पर्याय बन गया. 9वीं शताब्दी के बाद भारत विदेशी आक्रांताओं एवं ग़ैर मुल्की हुक्मरानों की जागीर बन गया और यही स्थिति भारत की आज़ादी के पूर्व तक बनी रही. देश की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा दी गई. अकृतज्ञ देश ने धीरे–धीरे पाटलिपुत्र को भूलना शुरू कर दिया. दुनिया का यह सबसे खूबसूरत शहर विध्वंश का शिकार हो चुका था. अगली दो शताब्दियों तक इतिहास के पृष्ठों से हटकर एकदम से गुमनाम हो गया यह नगर.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly
Chauthi Duniya
Santosh Bhartiya
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> जहां तक कैंप की हालत का सवाल है तो यह इंसानों के रहने लायक नहीं है. बजबजाती हुई गंदी नालियां, नालियों में आधे डूबे हुए सरकारी नलों से पीने का पानी भरती हुई लड़कियां. घरों की हालत ऐसी कि एक अस्थाई रूप से टिन की छत डाल कर एक 8 वर्ग मीटर के छोटे से कमरे में एक परिवार के औसतन 5 से 9 लोग रहने को मजबूर हैं.

दो देशों के बीच पिसते बिहारी शरणार्थी

उर्दू के मशहूर और बदनाम कहानीकार सआदत हसन मंटो की एक कहानी है टोबा टेक सिंह जो वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के परिपेक्ष्य में लिखी गई है. कहानी का ताना-बाना लाहौर के पागलखाने के इर्द-गिर्द बुना गया है. इस के ज्यादातर किरदार पागल हैं. कहानी का मुख्य पात्र विशन सिंह इस दुविधा में गिरफ्तार हो जाता है कि उसका गांव टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? और जब उसे हिंदू और सिख पागलों के साथ भारत भेजा जाता है तो वह भारत या पाकिस्तान के बजाय नो मैनस लैंड में दम तोड़ देना ज्यादा पसंद करता है. टोबा टेक सिंह की कहानी 1947 के बाद भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अनेकों बार दोहराई जा चुकी है और आगे भी जाने कितनी बार दोहराई जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है. बिशन सिंह जिस मनोदशा से गुजर रहा था ठीक उसी स्थिति में आज भी बांग्लादेश में तकरीबन 1.5 लाख बिहारी शरणार्थी हैं जो एक बेहतर और सुरक्षित ज़िन्दगी की तलाश में पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वह न तो पाकितानी हैं और ना ही बंगलादेशी, भारतीय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. उनके पास संयक्त राष्ट्रसंघ की संस्था रेडक्रॉस द्वारा बनाए गए शरणार्थी शिविरों में जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने के इलावा और कोई चारा नहीं है. मंटो के विशन सिंह के पास एक विकल्प तो था कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसी का भी चुनाव ना कर सकने की स्थिति में नो मैनस लैंड में अपनी जान दे सकता था. लेकिन इन उर्दूभाषी बांग्लादेशी बिहारियों की त्रासदी यह है कि उन्हें दो गज़ ज़मीन भी मयस्सर नहीं है जिसे वो अपना कह सकें.

शफीक आलम

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर में स्थित कैंप तक़रीबन 30 हज़ार बिहारी शरणार्थियों की रिहाइशगाह है. इसी साल जून महीने की 14 तारीख को शब-ए-बारात के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर मामूली कहा सुनी हुई. जिसके बाद धारदार हथियारों से लैस एक भीड़ ने इस कैंप के 10 लोगों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जला डाला. पुलिस प्रशासन ने इस घटना को दो बिहारी गुटों की आपसी लड़ाई कहकर मामले को रफा-दफा करने कि कोशिश की, जबकि स्थानीय निवासियों ने सत्ताधारी दल आवामी लीग के सांसद को इस घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. घटना की जांच के लिए गठित जांच समिति अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. अखबारों में छपी रिपोर्टों के मुताबिक अभी तक समिति को कोई ऐसा सुबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर किसी के खिलाफ मुक़दमा कायम किया जा सके. बहरहाल, जांच का नतीजा जो भी हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस कैंप में रहने वाले लोग संगीन मानवीय त्रासदी का शिकार हैं. उनके अधिकारों का हनन कोई अनोखी बात नहीं है.

जहां तक कैंप की हालत का सवाल है तो यह इंसानों के रहने लायक नहीं है. बजबजाती हुई गंदी नालियां, नालियों में आधे डूबे हुए सरकारी नलों से पीने का पानी भरती हुई लड़कियां. घरों की हालत ऐसी कि एक अस्थाई रूप से टिन की छत डाल कर एक 8 वर्ग मीटर के छोटे से कमरे में एक परिवार के औसतन 5 से 9 लोग रहने को मजबूर हैं. 30 हज़ार लोगों के लिए सिर्फ 200 सार्वजानिक टॉयलेट. यह ऐसी स्थिति है जिसमें प्राइवेसी तो दूर उसकी कल्पना भी बेकार है. स्कूल के नाम पर वालंटियर्स द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूल. जिसके बाद शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, जो बहुत खुशकिस्मत हुए उन्हें कॉलेज का मुंह देखने का मौक़ा मिल गया. वहां भी बिहारी होने का ताना और उपेक्षा. पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कोई नौकरी नहीं. जीविका का प्रमुख साधन सिलाई-कढ़ाई और मेकेनिक का काम. बांग्लादेश में बिहारी मुसलमानों (जिन्हें सरकारी जुबान में एसट्रेंडेड पाकिस्तानी या फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जाता है और ये लोग खुद को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद करते हैं) के लिए बने 70 कैम्पों की कम-ओ-बेश ऐसी ही हालत है.

एसट्रेंडेड पाकिस्तानियों के हक की लड़ाई लड़ने वाली संस्था एसट्रेंडेड पाकिस्तानी जनरल रिपैटरिएशन कमिटि (एसपीजीआरसी) के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में कुल एक लाख साठ हजार उर्दू बोलने वाले बिहारी शरणार्थी हैं. इन सभी 70 कैम्पों में केवल सात स्कूल हैं. 19 हजार स्कूल जाने योग्य बच्चों में से केवल 275 बच्चे स्कूल जाते हैं. वर्ष 2008 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक लाख साठ हजार उर्दू भाषी लोगों में से केवल 60 हज़ार लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किये गए. इन शरणार्थियों की हक़ की लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवक एहतशामुद्दीन अरशद के मुताबिक वोटिंग का अधिकार देना केवल दिखावा था. उनका कहना है कि इंटरनेशनल रेडक्रॉस ने उनसे एक विकल्प लिया था सबने पाकिस्तान का विकल्प चुना था. यहां के नेता बिहारियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं. अब सवाल यह है कि यह फंसे हुए बिहारी कौन हैं? 40 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इनकी हैसियत शरणार्थियों की क्यों है? उनकी इस दशा के लिए ज़िम्मेदार कौन है?

बांग्लादेश के बिहारी मुसलमान वह लोग हैं जो 1947 में भारत विभाजन के बाद खासतौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुसलमानों के लिए बने नये-नवेले देश पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी पाकिस्तान) चले गए थे. ज़ाहिर है पाकिस्तान की बुनियाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नाम पर रखी गई थी. लेकिन विडंबना यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए बने देश में एक दूसरे अल्पसंख्यक यानि बंगालियों की अनदेखी होने लगी. इस अनदेखी को बंगला भाषी पाकिस्तानी सहन नहीं कर सके और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया.

बांग्लादेश के बिहारी मुसलमान वह लोग हैं जो 1947 में भारत विभाजन के बाद खासतौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुसलमानों के लिए बने नए-नवेले देश पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी पाकिस्तान) चले गए थे. ज़ाहिर है पाकिस्तान की बुनियाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नाम पर रखी गई थी. लेकिन विडंबना यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए बने देश में एक दूसरे अल्पसंख्यक यानि बंगालियों की अनदेखी होने लगी. इस अनदेखी को बंगला भाषी पाकिस्तानी सहन नहीं कर सके और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया. धीरे-धीरे यह आंदोलन पृथकतावादी हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया. और वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश नाम का एक नया देश वजूद में आ गया. चूंकि पाकिस्तान सरकार ने सरकारी नौकरियों में, व्यवसाय में उर्दू भाषी बिहारी लोगों को तरजीह दी थी. इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के बहुसंख्यक बंगाली, बिहारियों को पाकिस्तानी वर्चस्व के प्रतीक के तौर पर देखने लगे थे. वर्ष 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में बिहारी लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था, जिसकी वजह से पहले से ही तनावपूर्ण बंगाली-बिहारी रिश्तों में और कड़वाहट पैदा हो गई.

बांग्लादेश की स्थापना और 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौजों की हार के बाद बंगालियों का गुस्सा बिहारियों पर टूट पड़ा. रातों-रात लाखों लोग अपने घरों और नौकरी से बे-दखल कर दिए गए. इसके बाद वो सभी रेडक्रॉस द्वारा स्थापित शरणार्थियों शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए. इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कराए गए सर्वे में ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा ज़ाहिर की थी. वर्ष 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरम्यान एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ. इसके अनुसार पाकिस्तान इन शरणार्थियों को पाकिस्तान में आबाद करने पर राज़ी हो गया था. इस समझौते में यह कहा गया था कि तीन वर्ष की अवधी में सभी शरणार्थी पाकिस्तान चले जाएंगे. लेकिन इस दौरान तकरीबन एक लाख लोगों की पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो पाई थी और तकरीबन डेढ़ लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका रह गया. क्योंकि इस राह में पाकिस्तान की ब्यूरोकेसी आड़े आ गई और कई तरह की अनावश्क शर्तें लगाकर लोगों की पाकिस्तान वापसी में अड़चनें पैदा कर दीं. एसपीजीआरसी के वरिष्ठ नेता अब्दुल जब्बार खान कहते हैं के 1974 से आज तक 40 साल गुजर गए हैं और हम आज भी उस हवाई जहाज का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे हमें पाकिस्तान जाना है.

इस दौरान एसपीजीआरसी ने अनगिनत धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, मार्च और जुलुस निकाले. यहां तक की 1981 में भारत के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए लॉन्ग मार्च की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें बांग्लादेश की सरहद पर गिरफ्तार कर लिया गया. बहरहाल, जुलूसों का सिलसिला आज भी जारी है. लेकिन बिहारी शरणार्थियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए कोशिशें हुईं लेकिन अभी तक उसका भी कोई असर नहीं हो सका. 1974 के बाद सबसे पहले 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों की संस्था युएनएचसीआर ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया. ताकि इन शरणार्थियों को पाकिस्तान में बसाया जा सके. वर्ष 1982 में कुवैत, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की आर्थिक सहायता के बाद 4600 बिहारियों को पाकिस्तान में बसाया गया. पाकिस्तान की सरकार ने सैद्धांतिक रूप में कभी भी बिहारी शरणार्थियों की पाकिस्तान वापसी से इंकार नहीं किया. हालांकि राबिता अल आलमी इस्लामी की पहल पर नवाज़ शरीफ के वजीर-ए-आला रहते कि पंजाब असेंबली ने इन सभी शरणार्थियों को पाकिस्तानी पंजाब में आबाद करने के लिए एक प्रस्ताव भी मंज़ूर कर लिया था. लेकिन 1988 में जनरल जिया-उल-हक की मौत के बाद सत्ता में आई बेनजीर हुकूमत ने राष्ट्रवादी सिंधियों के दबाव में आकर इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. और एक बार फिर बिहारी शरणार्थियों को उम्मीद की किरण दिखाई देने के बाद उनके हाथ मायूसी लगी. वर्ष 1992 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक साझा बयान में यह कहा गया की दोनों देशों के बीच फंसे हुए 3000 पाकिस्तानी परिवारों को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा. 1993 में 325 लोगों के पाकिस्तान आने के साथ ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, लेकिन इसी बीच कराची में सिंधी राष्ट्रवादियों ने दो बम धमाके किए जिसमें 22 लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे. इसके बाद इस प्रस्ताव पर रोक लग गई थी.

बिहारी शरणार्थियों की पाकिस्तान वापसी एक बार फिर अधर में पड़ गई जब वर्ष 1995 में पाकिस्तान सरकार ने 130 बांग्लाभाषी लोगों को यह कहकर बांग्लादेश वापस भेज दिया गया कि वे अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे. पाकिस्तान का यह भी कहना था कि 16 लाख बांग्लादेशी पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं. ज़ाहिर है पाकिस्तान का यह रवैया बिहारी शरणार्थियों को पाकिस्तान वापस न बुलाने का बहाना बन गया. बांग्लादेश ने अपेक्षित रूप से इन बंगालियों को लेने से साफ़ इंकार कर दिया. इस परिपेक्ष्य में पाकिस्तान वापसी की उम्मीद लगाए कुछ बिहारियों को यह एहसास होने लगा कि पाकिस्तान वापसी का रास्ता बहुत कठिन है. लिहाज़ा उन्होंने 2004 में वोटिंग राईट के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जिसके बाद 2008 में कोर्ट ने उन्हें वोटिंग का अधिकार दे दिया. वोटिंग का अधिकार तो मिल गया लेकिन अभी तक इनका नेशनल आईडी कार्ड नहीं बन पाया है. इस वजह से उनकी नागरिकता अभी तक अधर में लटकी हुई है.

हालांकि अब ज्यादातर बिहारी शरणार्थी अब यह समझ गए हैं कि उनकी पाकिस्तान वापसी का रास्ता आसान नहीं है इसलिए वह अब बांग्लादेश में ही अपने नागरिक अधिकारों की बात करने लगे हैं. लेकिन बांग्लादेश में अभी भी उनके लिए हालत जस के तस बने हुए हैं. उधर पाकिस्तान अस्थिरता का शिकार है. बलूचिस्तान में वैसे ही हालत पैदा हो रहे हैं जैसे 1970 से पहले बांग्लादेश में थे. सिंधी किसी भी कीमत पर और मुहाजिरों को अपनी ज़मीन पर बसाने के लिए तैयार नहीं हैं. पंजाब और खैबर पख्तून ख्वा में भी अराजकता की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में ये बिहारी शरणार्थी मुस्लिम देशों की संस्था आर्गेनाईजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन और संयक्त राष्ट्र संघ के दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और 40 साल से ज्यादा गुज़र जाने के बाद भी ये लोग आज किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

संपादकीय

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री अपने विचार जनता के सामने रखें

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला देखिए. जस्टिस काटजू ने कुछ खुलासे किए और जो सार्वजनिक डोमेन में आ गए हैं. न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा फिर से सामने आ गया है. पूरी दुनिया में जज ही जज की नियुक्ति करते हैं. यही प्रथा सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपनाई, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार नियुक्तियां करती है. इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल का उपयोग किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल काफी खामोश रहते हैं. यह पता नहीं चल पा रहा है कि विभिन्न मसलों पर उनके विचार क्या हैं? शायद वह अभी भी अपना मन बना रहे हैं या अपने सलाहकारों पर निर्भर हैं. फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के कई ऐसे मसले हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए. सबसे पहले, कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं, जहां दुर्घटनावश या जानबूझ कर ऐसे काम किए गए, जिससे अल्पसंख्यक प्रभावित हुए हैं. महाराष्ट्र के एक शिवसेना सांसद ने एक खानपान पर्यवेक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया. अब कोई व्यक्ति भले ही अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन एक सांसद को एक कनिष्ठ कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. अगर वह खुश नहीं हैं, तो एक प्रक्रिया के तहत शिकायत कर सकते थे. लेकिन, सांसदों द्वारा इस तरह का कृत्य लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है.

इन लोगों के सत्ता में आने के बाद से, मैं महसूस कर रहा हूं कि हिंदू कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा है, लेकिन इससे उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे इस देश की हज़ारों साल पुरानी संस्कृति या इस देश के अनुशासन को खराब कर दें. महाराष्ट्र सदन या विभिन्न राज्यों के सदन वह जगह है, जहां उन राज्यों के सांसद और महत्वपूर्ण लोग आते और ठहरते हैं. उसे एक उचित गेस्ट हाउस की तरह चलाया जाना चाहिए. भोजन की गुणवत्ता को लेकर विवाद या झगड़ा नहीं किया जा सकता है. सांसदों को अगर जनता द्वारा सम्मान चाहिए, तो उन्हें अपनी सीमा के भीतर ही रहना चाहिए. यह सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार पर निर्भर है कि वे इस मसले का हल कैसे निकालते हैं.

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला देखिए. जस्टिस काटजू ने कुछ खुलासे किए और जो सार्वजनिक डोमेन में आ गए हैं. न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा फिर से सामने आ गया है. पूरी दुनिया में जज ही जज की नियुक्ति करते हैं. यही प्रथा सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपनाई, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार नियुक्तियां करती है. इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल का उपयोग किया गया. और, अब वे कहते हैं कि यह काम एक कॉलेजियम करेगा, जो पिछले 21 सालों से वजूद में है. यह पूरी तरह से गलत है. इस सरकार के पास यह प्रक्रिया पलटने का साहस होना चाहिए.

दुनिया भर के लोकतंत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अंतिम फ़ैसला कार्यपालिका का होता है. हां, व्यक्तिपरक तत्वों से बचने के लिए एक प्रक्रिया हो सकती है. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का कॉलेजियम हो सकता है या न्यायिक नियुक्ति के लिए एक सलाहकार बोर्ड हो सकता है, लेकिन अंतिम नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा नहीं, कार्यपालिका द्वारा की जानी चाहिए. दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों में धीरे-धीरे सरकार ने अपनी ताकत खो दी और न्यायपालिका या अन्य लोगों ने इस शून्य को भरने का काम किया. शून्य की स्थिति हमेशा एक शून्य जैसी नहीं होती, कोई न कोई उस शून्य को भरता ही है. कार्यपालिका को फिर से अपना अधिकार हासिल करना चाहिए. यह इस सरकार या उस सरकार का सवाल नहीं है. सरकार एक सतत इकाई है.

इसी तरह हम अन्य बहुत-सी चीजें देख रहे हैं. सबसे पहले कहा गया कि संसद के समय में कटौती होगी, फिर कहा कि नहीं होगी. वित्त विधेयक पहले ही पारित कर दिया गया है, इसलिए अगर सचमुच उनके पास कोई काम नहीं है, तो अगले दो सप्ताह तक वे क्या करेंगे? सिर्फ़ इसलिए कि आपने सत्र की घोषणा की है, उसे चलने देना चाहिए? अगर कोई काम नहीं है, तो सत्र स्थगित हो. अगर कोई काम है, तो जब तक वे कांग्रेस या अन्य दलों के साथ बातचीत नहीं कर लेते हैं, तब तक एक भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं करा सकते हैं.

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू (जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय भी मिला हुआ है) चुनाव हार चुके सांसदों एवं मंत्रियों के आवास खाली

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू (जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय भी मिला हुआ है) चुनाव हार चुके सांसदों एवं मंत्रियों के आवास खाली कराने में अधिक व्यस्त हैं. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को उठाया और कहा कि मंत्रियों को उनके बंगले खाली करने चाहिए.

कराने में अधिक व्यस्त हैं. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को उठाया और कहा कि मंत्रियों को उनके बंगले खाली करने चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट का काम है? पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री बंगला खाली कर रहे हैं या नहीं, यह न तो सुप्रीम कोर्ट का और न एक मंत्री का काम है, बल्कि इसके लिए एक संसदीय आवास समिति है. यह एक बहुत छोटी बात है. असंतुष्ट पार्टी अदालत में जा सकती है. यहां सुप्रीम कोर्ट वेंकैया नायडू के आदेश की आड़ में सुओमोटो मामले को ले लेता है और नायडू अपने ही सहयोगियों का अपमान करने के लिए मजबूत क़दम उठा लेते हैं. यह शुभ संकेत नहीं है. यह कमजोर सरकार की निशानी है. जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी भी नहीं जानते कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और इन लोगों को प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं?

विदेश नीति: विदेश मंत्री ने नेपाल की यात्रा की. अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं. यह आसान नहीं है. नेपाल एक पड़ोसी देश है और उसके साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं. मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री को सही ढंग से सूचित किया जाएगा और हम नेपाल के साथ मुद्दे को जटिल नहीं बनाएंगे. वहां एक बदलती राजनीतिक स्थिति है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल है. नेपाल अभी तक अपना संविधान नहीं बना पाया है. भारत को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसे अपनी पसंद का एक संविधान बनाने में मदद करनी चाहिए. बेशक, वह एक संप्रभु देश है और हम एक सीमा से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी के रूप में और लोकतंत्र का एक लंबा अनुभव होने के नाते हम उन्हें एक बेहतर संविधान बनाने में मदद कर सकते हैं.

स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अवसर है, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं. इस मौक़े पर उन्हें छोटी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों पर बात करनी होगी. इस अवसर पर महाराष्ट्र सदन वाली घटना या कुछ भ्रष्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसी बातें नहीं की जा सकती हैं. यहां तक कि अगर पिछली सरकार के ख़िलाफ़ कोई शिकायत भी है, तो उसे उठाने या बताने के लिए स्वतंत्रता दिवस सही अवसर नहीं है. वहां उन्हें यह बताना है कि अगले पांच सालों के लिए वह क्या सोच रहे हैं. यह वह अवसर है, जब प्रधानमंत्री को अपने दिल की बात कहनी होगी. भारत को लेकर उनका विजन क्या है, यह बताना होगा. आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सच्चाई के साथ खड़े रहने का गुरुमंत्र

यह संयोग था कि 1977 में जन आकांक्षा की प्रतीक जनता सरकार बन गई थी तथा यह दूसरा संयोग था कि पाठकों का विश्वास रविवार को मिल गया था. रविवार ने पत्रकारिता के उच्च प्रतिमानों के अनुसार सरकार पर नज़र रखने का काम अपने आप ओढ़ लिया था. रविवार के नेतृत्व का मानना था कि उनका काम किसी की शान में कसीदे पढ़ना नहीं, बल्कि जहां खराबी या सड़न है, उसे जनता के सामने लाना है. रविवार ने यह भी तय किया था कि वह जनता की तकलीफ़ों को लगातार सरकार के सामने रखेगी. दोनों स्थितियों का वर्णन साफ़ शब्दों में हो और रिपोर्ट में कई पक्षों का समावेश हो तो हो, पर रिपोर्टर को सच्चाई का वर्णन करना ही चाहिए. रविवार का मानना था कि सच्चाई कभी दो पक्षों के साथ खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए सच्चाई जिस पक्ष के साथ हो, रिपोर्टर को उसका साथ देना चाहिए और रिपोर्ट के पक्ष में उसे खड़ा होना चाहिए. संपादक (अकबर और एसपी) ने अपने रिपोर्टरों को यह विश्वास दिला दिया था कि यदि उनकी रिपोर्ट सही होगी, तो वे उनका हर स्थिति में साथ देंगे. कई मौक़े आए, जब सरकार और संपादक के दोस्तों ने उन पर दबाव डाला कि रिपोर्ट का खंडन छाप दिया जाए या रिपोर्ट ही न छपे, पर संपादक ने कभी नहीं माना. वे हमेशा अपने रिपोर्टर की सच्चाई पर खड़े रहे, शायद यह उस समय अंग्रेजी और हिंदी में पहली बार हुआ था. हिंदी के बारे में मैं निश्चित हूं कि यह पहली बार ही हो रहा था.

इसीलिए रविवार पहली पत्रिका थी, जिसने धर्मयुग, हिंदुस्तान और दिनमान से अलग, बिल्कुल अलग शैली प्रारंभ की. दिनमान इसे नहीं कर सका या करना नहीं चाहता था या उसके संपादक का भरोसा इन बातों में नहीं था. पर दिनमान का पराभव आपातकाल से प्रारंभ हुआ और उसके बाद के दिन उसकी पूर्णाहुति के दिन थे. जब चौथी दुनिया निकला, तब तक दिनमान का आभा मंडल लगभग उदास हो चुका था. एसपी ने एक दिन मुझे बताया कि समीर जैन, जिन्होंने टाइम्स ग्रुप की ज़िम्मेदारी संभाल ली थी, ने उनसे कहा था कि या तो पब्लिकेशन से उन्हें पैसा मिले या क्रेडिबिलिटी मिले. यदि दोनों नहीं मिलते, तो वह उसे क्यों निकालें? उनकी यही थ्योरी दिनमान के बंद होने का कारण बनी. शायद यही कारण बाद में रविवार के भी बंद होने का बना, क्योंकि आख़िरी दिनों में रविवार न तो पैसा दे रही थी और न ही क्रेडिबिलिटी. यह भी संयोग था कि जो क्रेडिबिलिटी रविवार को एसपी के समय मिली, वह बाद में कायम नहीं रह पाई. इस सवाल पर बाद में विचार करेंगे कि क्या कप्तान का व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके हटते ही सब कुछ तहस-नहस हो जाता है?

उन दिनों हिंदी पत्रकारिता में यह बिल्कुल अनोखी बात हुई थी. सबसे पहली बात कि हिंदी जगत में संपादक कोई नौज़वान भी हो सकता है. यह बात उन दिनों के हिंदी सत्ताधीशों को पची नहीं. दूसरी बात यह कि रिपोर्ट बिल्कुल नए लड़के लिखें, दरअसल यह तो कुछ लोगों के लिए और भी अस्वीकार्य स्थिति थी. रिपोर्ट भी ऐसी, जो लोगों को चौंका दे. उसमें अलंकार, उपमा अथवा अनुप्रास के लिए कोई स्थान ही नहीं होता था. सीधे-सादे शब्दों में रिपोर्ट. रिपोर्ट में एक पक्ष को सही और दूसरे को साफ़-साफ़ गलत कहा जाता था. न तो उसमें तुम भी सही और तुम भी सही होता था और न तुम्हारा भी पक्ष और तुम्हारा भी पक्ष होता था. जिसे तिलमिलाना हो तिलमिलाए, जनता के सामने सही तस्वीर रखी जाती थी. पाठकों ने रविवार का हाथोंहाथ हृदय से स्वागत किया. उदयन शर्मा पुन: खेल से राजनीतिक विषयों पर आ गए तथा छह महीने बीतते न बीतते उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया. उदयन रविवार के पहले संवाददाता व विशेष संवाददाता थे.

एसपी ने कलकत्ता में ऐसे साथियों की अपनी टीम बनाई, जो नई भाषा के साथ नई दृष्टि भी रखते थे. पर

रिपोर्ट में एक पक्ष को सही और दूसरे को साफ़-साफ़ गलत कहा जाता था. न तो उसमें तुम भी सही और तुम भी सही होता था और न तुम्हारा भी पक्ष और तुम्हारा भी पक्ष होता था. जिसे तिलमिलाना हो तिलमिलाए, जनता के सामने सही तस्वीर रखी जाती थी. पाठकों ने रविवार का हाथोंहाथ हृदय से स्वागत किया. उदयन शर्मा पुन: खेल से राजनीतिक विषयों पर आ गए तथा छह महीने बीतते न बीतते उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

उनका सबसे बड़ा योगदान देश में ऐसे नौज़वानों की तलाश कर उनसे रिपोर्ट लिखवाना था, जिनके पास राजनीति के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण भी थे. आज के अधिकांश बड़े पत्रकारों का लेखन या तो रविवार से प्रारंभ हुआ या रविवार ने उन पर धार लगाकर उन्हें नई पहचान दी. जो नौज़वान पत्रकार दैनिक पत्रों में, राज्यों में काम करते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन एसपी ने दिया. शैलेश, जयप्रकाश शाही, राजीव शुक्ल, टिल्लन रिछारिया, राजेश बादल, आलोक तोमर, संतोष तिवारी, राकेश कोहरवाल, बनवारी, अनुपम मिश्र, राजेंद्र छाबड़ा, अतुल कुमार, प्रमिला जैसे न जाने कितने नाम हैं, जिन्हें रविवार ने वह पहचान दी, जो उन्हें उनके अपने अख़बार नहीं दे पा रहे थे.

इन सबने पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ ही किया था और इन्हें बड़ी रिपोर्ट लिखने का मौक़ा मिल गया. रविवार की अपनी टीम के नेता उदयन शर्मा थे. उदयन के साथ ही एसपी ने स्वामी त्रिवेदी, अरुण रंजन व संतोष भारतीय की टीम बनाई. एसपी ने पहली बार नौज़वानों पर खुद तो भरोसा किया ही, जनता को भी बताया कि नौज़वानों पर भरोसा करना चाहिए. उस भरोसे ने ही रविवार को इतिहास रचने का मौक़ा दे दिया. एसपी ने स्थापित पत्रकारों से भी लिखवाया, पर उनका स्वयं का भरोसा उन पर ज़्यादा था, जो नई दृष्टि रखते थे. एसपी एवं अकबर ने एक और कमाल किया था. दोनों ने मिलकर रविवार को संडे का अनुवाद बनने ही नहीं दिया, बल्कि दोनों ने दोनों पत्रिकाओं के बीच स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता भी पैदा की. इसकी मिसाल देखनी हो, तो संडे और रविवार के पुराने अंक देखने चाहिए. कौन पहले कितनी बेहतरीन कवर स्टोरी करता है, इसकी होड़ लगी रहती थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात सितंबर में अमेरिका में होने वाली है. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी इसकी पूर्व तैयारी के लिए भारत आए हैं. दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री की इस भारत यात्रा का उद्देश्य भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की पूर्व तैयारी के साथ-साथ नरेंद्र मोदी को थोड़ा लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार करना है. अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों से दंगों का दोषी करार देते हुए वीजा नहीं दिया था. अब नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ बदले हालात में रिश्ते सामान्य किए जाएं. पर इसके पीछे अमेरिका की अदालत में हुआ यह खुलासा भी है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ-साथ भारत के कुछ नेताओं की भी जासूसी कराई, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री एवं वर्तमान राष्ट्रपति

यह नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा है

प्रणब मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गड़करी और संभवत: अरुण जेटली का नाम शामिल है. इस खुलासे से यूरोपीय देशों में शोर-शराबा हुआ, काफी ख़बरें आईं, लेकिन हिंदुस्तान में काफी संयत ख़बरें आईं और इस ख़बर को दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि अब हालात बदले हुए हैं. अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर काफी शोर मचाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते इस सारे मामले को सिरे से ख़ारिज करने का प्रयास किया गया. पर जब भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के साथ बातचीत में इस मुद्दे को उठाया, तब यह साफ़ हो गया कि भारत सरकार संसद में इस जासूसी कांड को देश में हुई जासूसी के साथ जोड़ रही है, अमेरिका द्वारा हुई जासूसी के साथ नहीं जोड़ रही है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने से पहले अगस्त के आख़िरी हफ्ते में इस्लामाबाद जाएंगे और वहां उनकी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत होगी. इस बातचीत में सारे विवादास्पद मुद्दे होंगे और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कश्मीर पर उसमें बातचीत नहीं होगी. कश्मीर पर भी बातचीत होगी. इस बातचीत का एक ही नतीजा निकलेगा कि कश्मीर पर बातचीत जारी रहे, लेकिन व्यापार के रास्ते खोलने की पहल हो. अगर ऐसा होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच नए रिश्ते बनेंगे. अगर दोनों देश खुलेआम पर्यटकों को एक-दूसरे के यहां आने की अनुमति देते हैं या पर्यटन वीजा थोड़ा आसानी से देना प्रारंभ करते हैं, तो यह भी दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की दिशा में काफी सार्थक पहल होगी, दोस्ती बढ़ेगी. भारत और पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि दोनों देशों में आतंकी गतिविधियां करने के लिए किसी को भी वीजा की ज़रूरत नहीं है और न पासपोर्ट की. आतंकी गतिविधियों या जासूसी गतिविधियों में लिप्त लोग बिना वीजा-पासपोर्ट काम करते हैं. अब दुनिया भर में संचार साधन इतने विकसित हो गए हैं और आने-जाने के इतने रास्ते खुल गए हैं कि जिन ट्रेडिशनल बातों का जिक्र होता है, जिसमें वीजा एवं पासपोर्ट प्रमुख है, उनका कोई महत्व नहीं रह गया है. दरअसल, वीजा और पासपोर्ट की बात दोनों देशों के हुक्मरान अपनी-अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं, इसलिए जनता को मूर्ख बनाने की जगह उसे आपस में मिलने देने की कोशिश अगर दोनों सरकारें करें, तो अच्छे रिश्ते बहाल होने की दिशा में यह सबसे बड़ा सार्थक क़दम होगा.

जिस चीज की मुझे आशंका है, वह पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अमेरिका में होने वाली गतिविधियां देखने से पैदा हुई है. ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका उन्हें यह सलाह दे सकता है कि भारत कश्मीर का मसला हल करने की दिशा में थोड़ी सार्थक या ठोस पहल करे. इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो, तो उसे अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार करनी चाहिए. अब तक भारत की यह नीति रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत में, चाहे वह कश्मीर का मसला हो, आपसी संबंधों का हो या व्यापार का, उसमें किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी कभी स्वीकार नहीं की गई. भारत स्पष्ट राय देता रहा है कि द्विपक्षीय बातचीत होगी, त्रिपक्षीय नहीं. लेकिन, अब शायद अमेरिका यह मानता है कि यदि वह कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई पहल करे, तो भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका समुचित अनुकूल उत्तर देंगे.

अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन का साथ ले सकता है और चीन भी अपनी महत्ता दिखाने के लिए अमेरिका का साथ देने में शायद हिचकिचाए नहीं और दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालें, पर मुझे पूरी आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री इस दबाव को पूरी आसानी के साथ न सिर्फ़ अस्वीकार करेंगे, बल्कि दोनों को अपनी हद में रहने की मित्रतापूर्ण चेतावनी भी दे देंगे. भारत के लिए कश्मीर एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भारत के लिए कश्मीर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है, क्योंकि इस तर्क के आधार पर कि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए या वहां के मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे देना चाहिए कि अगर वे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, तो यह ख़तरनाक सिद्धांत होगा. भारत के हर गांव में मुसलमान रहते हैं और अगर कहें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं. भारत 125 करोड़ लोगों का देश है, गांवों का देश है. हर गांव में मुसलमानों के 10 से 500 तक घर हैं. घर ज़रूर 10 से 500 तक हैं, लेकिन वहां पर सारे मुसलमान अल्पसंख्या में हैं. अगर इस तर्क को मान लें, तो फिर सांप्रदायिक ताकतें यह सवाल खड़ा करेंगी कि जो सिद्धांत कश्मीर में लागू हो रहा है, उसे भारत के गांवों में क्यों नहीं लागू किया जाए? इसलिए हमारे गांव से मुसलमान जाएं चाहे जहां और रहना चाहें तो रहें. इससे हिंदुस्तान के गांवों में दंगा फैलने का ख़तरा पैदा हो जाएगा. भारत के पास न इतनी सेना है और न पुलिस कि हर गांव में सुरक्षाबलों को लगाया जाए, जिससे मुसलमानों की रक्षा हो सके. दरअसल, यह सिद्धांत भारत में गांव-गांव में दंगा कराने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश की ताकतें हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान स्थित वे ताकतें हैं, जो दोनों देशों में शांति नहीं कायम होने देना चाहतीं.

मेरा ऐसा मानना है कि अगर भारत कश्मीर को अपने साथ रखना चाहता है, तो सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि कश्मीर उसके लिए धर्मनिरपेक्षता का एक मुद्दा है. अगर कश्मीर धर्मनिरपेक्ष रहेगा, भारत के साथ रहेगा, तो भारत के हर गांव में मुसलमानों की 16-17 प्रतिशत आबादी सुरक्षित रहेगी. हिंदुस्तान में मुसलमान उतने ही आज़ाद हैं, जितने पाकिस्तान में हैं. पाकिस्तान में तो फिर भी मुसलमानों के बीच दंगे, मुसलमानों के बीच आपसी लड़ाइयां सुर्ख़ियां बनती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान प्यार-मोहब्बत से रहते हैं और अपने हक़ों की प्राप्ति के लिए बाकायदा आंदोलन चलाते हैं. हिंदुस्तान में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं. हिंदुस्तान में मुसलमान राजनीति में उसी तरह हिस्सा ले सकते हैं, जिस तरह कोई दूसरा ले सकता है. अब यह मुसलमानों के ऊपर है कि वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह से किसके साथ करते हैं. ठीक वैसे ही, जैसे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक ग़ैर मुसलमानों के विभिन्न तबके, जिनमें दलित शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, पिछड़े शामिल हैं, सवर्ण शामिल हैं, ये सब कहीं न कहीं अल्पसंख्यक हैं. पर चूंकि सत्ता के ऊपर हिंदुस्तान में इतने सालों से जिस समर्थ वर्ग का कब्जा रहा है, उस वर्ग के कब्जे से आज़ादी भी मिल रही है और शिरकत भी तेजी से बढ़ रही है. हिंदुस्तान में पिछला चुनाव ऐसा रहा है, जिसमें मुसलमानों की अपनी रणनीतिक कमियों की वजह से उनकी हिस्सेदारी संसद और विधानसभाओं में कम हुई है. लेकिन, इस बात की आशा करनी चाहिए कि मुसलमान अपनी जद्दोजहद, अपनी लड़ाई, अपने हक़ों की प्राप्ति और अपने ग़रीब तबके की आर्थिक एवं शैक्षिक बदहाली ख़त्म करने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाएंगे.

पर इसके लिए सबसे से ज़्यादा आवश्यक है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बराबरी के स्तर पर बातचीत हो. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी परीक्षा है कि वह विश्व नेताओं की कतार में स्वयं को कहां खड़ा करते हैं और अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की एक ही शर्त है कि भारत के हितों के साथ न खुला, न छुपा किसी तरह का समझौता न हो. शायद यही वक्त की मांग है और यही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खुशहाली आए, इसकी भी मांग है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

हिंदू राष्ट्र में हो समग्र भारत

दक्षिण भारत का मुसलमानों के साथ अनुभव व्यापारिक तौर पर रहा. उन्होंने मुलसमानों के साथ व्यापार का अनुभव लिया, न कि मुस्लिम शासन का. मुस्लिम शासन काफी बाद में वहां पहुंचा. इसी प्रकार किसी भी तरह के हिंदू इतिहास को लिखते समय भक्ति आंदोलन के बारे में सोचना ही होगा, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में तमिल कवियों ने ही की थी. यह आंदोलन बाद में उत्तर भारत में पहुंचा. हिंदुत्व सिर्फ़ संस्कृत के ज्ञान का उत्पाद नहीं है, क्लासिकल तमिल का भी इसमें काफी योगदान है.

नई नवेली भाजपा सरकार को लेकर तुरंत सुधार की अत्यधिक आशाएं अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं. बजट में ऐसा दिखाई दिया कि सरकार टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है, न कि 20-20 की. इसका मतलब वह लंबे समय में सुधारों की तरफ़ देख रही है. देश की सीमाओं के मामले पर भी बहसें चल रही हैं, जिसमें सरकार अपने मंत्रियों और सांसदों पर उस सख्ती के साथ लगाम नहीं लगा पा रही है, जैसे वह दूसरे मामलों में लगाती है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश मार्कंडेय काटजू ने भी पिछली सरकार पर उंगली उठाकर नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं. यह बात पूर्णतया सही है कि जितनी उंगली पिछली यूपीए सरकार पर उठाई जानी चाहिए, उतनी ही न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी.

भाजपा के गठबंधन में भी परेशानियां दिख रही हैं. शिवसेना लड़ाई के लिए बिल्कुल छटपटा रही है और निश्चित रूप से यह छटपटाहट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर है. यह पार्टी कई मामलों पर भाजपा के मत से अलग होकर बोल रही है. यहां तक कि पत्रकार वेद प्रताप वैदिक द्वारा हाफिज सईद से मुलाकात जैसे छोटे मसले पर भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया, जैसा वह दूसरे मसलों पर करती है. शायद शिवसेना अब भाजपा के लिए वैसी ही सिद्ध होने वाली है, जैसी यूपीए के लिए तृणमूल कांग्रेस हुई थी. यहां भाजपा के लिए सौभाग्य की बात यह है कि उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है. इस वजह से ऐसे सहयोगी उसके साथ कोई खेल नहीं कर सकते.

इसके अलावा भी कुछ विवाद हैं, जैसे स्कूलों में संस्कृत शिक्षा. इसकी वजह से भाजपा की विचारधारा पर कुछ गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं. यह बात लगभग सभी के लिए स्पष्ट है कि भाजपा में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो संस्कृत को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की मातृभाषा मानते हैं. नई सरकार आने के साथ ही इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि संस्कृत को विशेष वरीयता दी जाएगी, लेकिन इसे लेकर सरकार के तमिल सहयोगियों एवं पूर्व सहयोगियों, जैसे अन्नाद्रमुक में काफी रोष है. मामला यह है कि तमिल उतनी ही पुरानी भाषा है, जितनी संस्कृत. और, वह भारत में बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषा भी है.

ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचने वालों की दृष्टि काफी हद तक उत्तर भारत तक ही केंद्रित थी. वे ऐसा मानते थे कि आर्यावर्त ही पूरा भारत है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह भारतीय इतिहास को दिल्ली सल्तनत के माध्यम से ही देखने का तरीका है. प्रधानमंत्री भी अपने शुरुआती भाषणों के दौरान कह चुके हैं कि देश 1200 सालों तक गुलाम रहा है. उस दौरान बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा. उन भाषणों के अनुसार, भारत मुहम्मद बिन कासिम के समय से ही गुलाम है, लेकिन कासिम का असर सिर्फ़ उत्तर भारत तक ही हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं. यहां तक कि उत्तर भारत में भी पूरी तरह से मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व नहीं था, जब तक कि मुगल शासन नहीं आया. मुहम्मद बिन कासिम की सिंध पर जीत को पूरे भारत पर जीत नहीं माना जा सकता. ठीक वैसे ही, जैसे ब्रिटिश सेना की प्लासी पर जीत को पूरे भारत पर जीत नहीं माना जा सकता. इसके बाद कई मुस्लिम शासकों को काफी समय लग गया पंजाब और दोआब जीतने में. जबकि असम हमेशा ही दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधिकार क्षेत्र से दूर रहा. ठीक इसी तरह अंग्रेजों को भी लगभग 70 सालों का समय लग गया था भारत के अन्य हिस्सों पर कब्जा करने में.

दक्षिण भारत का मुसलमानों के साथ अनुभव व्यापारिक तौर पर रहा. उन्होंने मुलसमानों के साथ व्यापार का अनुभव लिया, न कि मुस्लिम शासन का. मुस्लिम शासन काफी बाद में वहां पहुंचा. इसी प्रकार किसी भी तरह के हिंदू इतिहास को लिखते समय भक्ति आंदोलन के बारे में सोचना ही होगा, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में तमिल कवियों ने ही की थी. यह आंदोलन बाद में उत्तर भारत में पहुंचा. हिंदुत्व सिर्फ़ संस्कृत के ज्ञान का उत्पाद नहीं है, क्लासिकल तमिल का भी इसमें काफी योगदान है. यह दक्षिण भारत का ही एक राजवंश चोल था, जिसने देश के बाहर भी विजय हासिल की, जबकि उत्तर भारत के शासक आपस में ही झगड़ रहे थे. अगर किसी नए भारत के निर्माण का विचार हिंदू सिद्धांत पर आधारित है, तो उसमें देश के सभी हिस्सों को शामिल करना चाहिए. भारत के इतिहास में ज़्यादातर उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों को ही केंद्र में रखा गया है. इस वजह से हिंदू राष्ट्रवादी भारत के इस दिल्ली सल्तनत विचार से तंग आ चुके हैं. अगर ध्यान से देखा जाए, तो वर्तमान अखंड भारत ब्रिटिश शासन का ही नतीजा है. इसलिए अगर हम किसी नए भारत का विचार कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए सभी को जोड़ना होगा और ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा मुस्लिम शासकों के महिमा मंडन से अलग हटना होगा. अब समय आ गया है कि नए भारत के निर्माण पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुत्तों के मस्तिष्क में इंजेक्शन द्वारा न्यूरल स्टेम कोशिका को प्रवेशित कर हुए शोध द्वारा दिखाया गया है कि कैंसर की गिल्टी का उपचार बहुत सफल रहा है. परंपरागत तकनीकों के प्रयोग से मस्तिष्क के कैंसर का इलाज करना कठिन होता है, क्योंकि यह तेजी से फैलता है. हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने मानव की न्यूरल स्टेम कोशिका को उन चूहों के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया, जिनकी खोपड़ियों में पहले ही से कैंसर की गिल्टियां प्रवेशित की गई थीं.

स्टेम सेल थेरेपी

सौ बीमारियों का एक इलाज

आघात अथवा मस्तिष्क में चोट के चलते कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन्स (तंत्रिका) एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का नुक़सान हो जाता है. स्वस्थ वयस्क मस्तिष्क में न्यूरल स्टेम कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो स्टेम कोशिकाओं की सामान्य संख्या को बनाए रखने या प्रजनक कोशिका बनने के लिए विभाजित होती हैं. स्वस्थ वयस्क प्राणी में जन्मदाता कोशिकाएं मस्तिष्क में ही स्थानांतरण करती हैं तथा न्यूरॉन्स की संख्या को सामान्य बनाए रखने का प्राथमिक कार्य करती हैं.

नवीन चौहान

स्टेम सेल थेरेपी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, जिसके तहत चोट अथवा अन्य किसी बीमारी में क्षतिग्रस्त ऊतकों में नई कोशिकाएं डाली जाती हैं. चिकित्सीय शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टेम कोशिका द्वारा मानव विकारों का सफल इलाज हो सकता है. विभिन्न किस्मों की स्टेम कोशिका चिकित्सा पद्धतियां मौजूद हैं, किंतु अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के उल्लेखनीय अपवाद को छोड़कर अधिकांश पद्धतियां अभी प्रयोगात्मक चरणों में हैं. चिकित्सीय शोधकर्ताओं को आशा है कि वयस्क और भ्रूण स्टेम कोशिका शीघ्र ही कैंसर, डायबिटीज, पर्किन्सन, हंटिंग्टन, सेलियाक, हृदय रोग, मांसपेशियों के विकार, स्नायविक विकार और अन्य कई बीमारियों का उपचार करने में सफल होगी. 30 सालों से भी अधिक समय से अस्थि मज्जा और हाल में ही गर्भनाल स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों की ल्यूकेमिया एवं लिम्फोमा जैसी स्थितियों में चिकित्सा हेतु किया जाता रहा है.

स्टेम सेल : स्टेम सेल की प्राप्ति के तीन स्रोत हैं. एक–गर्भस्थ शिशु के भ्रूण के तंतुओं से, जिसे भ्रूण स्टेम सेल कहते हैं. दूसरा कार्ड स्टेम सेल, जो जन्म के समय बच्चों के गर्भनाल से लिए जाते हैं. तीसरा वयस्क स्टेम सेल, जो रक्त अथवा अस्थि मज्जा (बोनमैरो) से एकत्र किए जाते हैं. आजकल बच्चों के जन्म के समय गर्भनाल से स्टेम सेल लिए जा रहे हैं, जिन्हें स्टेम सेल बैंकों में माइनस 190 डिग्री तापमान पर स्टोर कर दिया जाता है. अनुमान है कि देश में लाखों लोग अब तक ऐसा कर चुके हैं. अकेले स्टेम सेल बैंकिंग का कारोबार देश में सौ करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है. बैंक इसके लिए एक मुश्त 70 से 80 हज़ार रुपये और प्रति वर्ष 5 से 10 हज़ार रुपये शुल्क लेते हैं. जब कभी दुर्घटना अथवा किसी बीमारी के कारण शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचती है, तो बैंक में जमा स्टेम सेल लेकर उनसे प्रयोगशाला में कोशिकाएं तैयार की जा सकती हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त अंग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है.

फ़ायदा : बच्चे के स्टेम सेल से खून के रिश्ते में सभी लोगों के लिए कोशिकाएं तैयार की जा सकती हैं. भ्रूण या गर्भनाल से एकत्र किए गए स्टेम सेल ज़्यादा उपयोगी रहे हैं. गर्भनाल को अभी तक बेकार की वस्तु समझा जाता था तथा काटकर कूड़े में फेंक दिया जाता था. अब वही भावी बीमारियों से मुक्ति का जरिया बन चुका है. वयस्क व्यक्ति के रक्त या बोनमैरो से एकत्र किए गए स्टेम सेल के विकसित होने की गति धीमी होती है, जबकि भ्रूण कोशिकाओं से हर अंग की कोशिका विकसित हो जाती है. बीमार व्यक्ति का खून के रिश्ते के व्यक्ति के स्टेम सेल से उपचार किया जा सकता है. जैसे कि कोई व्यक्ति रक्त कैंसर से ग्रस्त है, तो वैसी स्थिति में खून के रिश्ते के व्यक्ति के बोनमैरो से स्टेम सेल लेकर उन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाएगा और बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा. ये कोशिकाएं कैंसर की वजह से नष्ट हो रही कोशिकाओं को बदल देंगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में स्टेम सेल पर इतना अधिक कार्य बढ़ चुका होगा कि इससे प्रयोगशाला में कृत्रिम अंग, जैसे कि गुर्दे, हृदय, लीवर आदि तैयार करना संभव हो सकेगा. क़रीब दस साल पूर्व सबसे पहले डॉ. वेणु गोपाल ने एम्स में रोगी के बोनमैरो से स्टेम सेल लेकर लैब में कृत्रिम कोशिकाएं उगाकर दिल की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदला था. कोलकाता में एक युवक के क्षतिग्रस्त स्पाइनल कॉर्ड को ऐसी ही कोशिकाओं से ठीक किया गया. कुछ मामलों में क्षतिग्रस्त कॉर्निया भी ठीक किया गया है.

संरक्षण : गर्भनाल स्टेम सेल को संरक्षित करने के लिए उच्च तकनीक और उच्च लागत की ज़रूरत होती है. गर्भनाल से ब्लड निकालने के बाद ब्लड बैंक को भेजा जाता है, जहां उसे शुद्ध किया जाता है. फिर उसे माइनस 190 डिग्री से नीचे फ्रीज किया जाता है. इस तरीके से सेल 500 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. कोई भी दंपति अपने नवजात के गर्भनाल को स्टेम सेल बैंक में संरक्षित करा सकता है.

संभावित उपचार

मस्तिष्क क्षति : आघात अथवा मस्तिष्क में चोट के चलते कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन्स (तंत्रिका) एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइटस का नुक़सान हो जाता है. स्वस्थ वयस्क मस्तिष्क में न्यूरल स्टेम कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो स्टेम कोशिकाओं की सामान्य संख्या को बनाए रखने या प्रजनक कोशिका बनने के लिए विभाजित होती हैं. स्वस्थ वयस्क प्राणी में जन्मदाता कोशिकाएं मस्तिष्क में ही स्थानांतरण करती हैं तथा न्यूरॉन्स की संख्या को सामान्य बनाए रखने का प्राथमिक कार्य करती हैं. यह दिलचस्प है कि गर्भावस्था और चोट लगने के बाद इस प्रणाली का नियंत्रण विकास में प्रयुक्त कारक करते हैं एवं वे मस्तिष्क के नए पदार्थ के निर्माण की गति को बढ़ा भी सकते हैं. हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क को चोट या आघात लगते ही विरोहक प्रक्रिया का आरंभ होता है, किंतु वयस्कों में पर्याप्त सुधार शायद ही दिखायी देता हो, जो कि मजबूती में कमी दर्शाता है. पर्किन्सन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी स्टेम कोशिका का उपयोग किया जा सकता है.

कैंसर : कुत्तों के मस्तिष्क में इंजेक्शन द्वारा न्यूरल स्टेम कोशिका को प्रवेशित कर हुए शोध द्वारा दिखाया गया है कि कैंसर की गिल्टी का उपचार बहुत सफल रहा है. परंपरागत तकनीकों के प्रयोग से मस्तिष्क के कैंसर का इलाज करना कठिन होता है, क्योंकि यह तेजी से फैलता है. हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने मानव की न्यूरल स्टेम कोशिका को उन चूहों के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया, जिनकी खोपड़ियों में पहले ही से कैंसर की गिल्टियां प्रवेशित की गई थीं. कुछ ही दिनों के भीतर कोशिकाएं कैंसर प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित हुईं और सायटोसिन डायमिनेज का निर्माण किया. एक ऐसा एंजाइम, जो ग़ैर विषाक्त समर्थक दवा को कीमोथेराप्यूटिक कारक में परिवर्तित करता है. एक परिणाम के रूप में इंजेक्शन द्वारा दिया गया पदार्थ 81 प्रतिशत कैंसर की गिल्टियां कम करने में सफल रहा. स्टेम कोशिका गिल्टी में तब्दील नहीं हो पाई. स्टेम कोशिका द्वारा उपचार से कैंसर की चिकित्सा की संभावना प्रबल हो सकती है. वयस्क स्टेम कोशिका के प्रयोग से लिम्फोमा रोग के उपचार हेतु अनुसंधान जारी है और इसके लिए मानव परीक्षण भी किया जा चुका है.

रीढ़ की हड्डी में चोट : 25 नवंबर, 2003 को कोरियाई शोधकर्ताओं के एक दल ने सूचना दी कि एक महिला रोगी, जो कि रीढ़ की हड्डी में चोट से पीड़ित था, उसके शरीर में गर्भनाल रुधिर से बहुप्रभावी वयस्क स्टेम कोशिकाओं को प्रत्यारोपित किया गया, जिसके चलते निर्धारित विधि का पालन करके उक्त रोगी बिना किसी कठिनाई और बिना किसी सहायता के चलने लगी. उक्त महिला रोगी लगभग 19 सालों तक खड़े होने में असमर्थ थी. इस अभूतपूर्व परीक्षण हेतु शोधकर्ताओं ने गर्भनाल रुधिर से वयस्क स्टेम कोशिकाओं को पृथक कर उन्हें रीढ़ की हड्डी के क्षतिग्रस्त हिस्से में प्रवेशित किया था.

हृदय की क्षति : हृदय रोगों पर किए गए कई चिकित्सीय परीक्षणों से पता चला है कि पुराने एवं नए रोगों पर समान रूप से वयस्क स्टेम कोशिका द्वारा चिकित्सा सुरक्षित, प्रभावी एवं सक्षम है. नवीन रक्त वाहिकाओं का विकास उत्तेजित करके, विकास कारकों को स्रावित करके, अन्य किसी तंत्र के माध्यम से सहायता प्रदान करके हृदय की मांसपेशी कोशिका में वयस्क अस्थि मज्जा कोशिकाओं को बढ़ाया भी जा सकता है.

गंजापन : बालों की जड़ों में भी स्टेम कोशिकाएं होती हैं और कुछ शोधकर्ता अंदाज़ लगाते हैं कि बालों की जड़ों की स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान करके उनकी जन्मदात्री कोशिकाओं को क्रियाशील कर गंजेपन के उपचार में सफलता अर्जित की जा सकती है. इस उपचार को खोपड़ी पर पहले से ही विद्यमान स्टेम कोशिकाओं को सक्रिय करके किया जा सकता है. इसके उपरांत की चिकित्सा में मात्र जड़ों की स्टेम कोशिकाओं को संकेत देकर निकट की जड़ों की कोशिका जो बढ़ती आयु के चलते सिकुड़ चुकी हो, को रासायनिक संकेतों से सक्रिय किया जा सकता है, जो कि एवज में संकेतों के फलस्वरूप पुनः निर्मित होकर बालों को दोबारा स्वस्थ बनाने में सहायक होगी.

दांत गिरना : 2004 में किंग्स कॉलेज लंदन ने चूहों में पूर्ण दांत उगाए जाने के तरीके की खोज की और वे प्रयोगशाला के भीतर ऐसा करने में सफल रहे. शोधकर्ताओं को विश्वास है कि इस तकनीक से मानव रोगियों में भी जीवंत दांत उगाए जा सकेंगे.

अंधापन और दृष्टिहीनता : 2003 के बाद से शोधकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त आंखों में कॉर्निया की स्टेम कोशिकाओं का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है. भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में समर्थ स्टेम कोशिका की एक पतली परत उगाने में कामयाबी अर्जित की. जब इन परतों को क्षतिग्रस्त कॉर्निया पर प्रत्यारोपित किया जाता है, तो स्टेम कोशिकाएं उत्तेजित एवं स्वयं दुरुस्त होकर अंततः दृष्टि बहाल करने में सहायक साबित होती हैं. इस तरह की नवीनतम तकनीक से जून 2005 में क्वीन विक्टोरिया अस्पताल इंग्लैंड में शोधकर्ताओं ने चालीस रोगियों की दृष्टि बहाल की. डॉक्टर शेराज दाया के नेतृत्व में एक दल ने रोगी, रिश्तेदार और यहां तक कि एक शव से भी प्राप्त वयस्क स्टेम कोशिका का सफलतापूर्वक उपयोग करने में कामयाबी अर्जित की. ■

अमेरिका की राह पर इजरायल

गलत आरोप लगाकर हजारों लोगों की हत्याएं करने का गुनाह करते हुए दुनिया अमेरिका को पहले भी देख चुकी है. उसकी इस हरकत की वजह से इराक आज पूरी तरह बर्बादी की कगार पर आ चुका है. इजरायल को मासूम फलस्तीनियों पर हमले करते हुए देख कर अमेरिका की याद आ रही है. बीते एक पखवाड़े से जो वजह बताकर इजरायल मासूम फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है वह वजह गलत साबित हो चुकी है. इसके बावजूद बेंजामिन नेतान्याहू इन हमलों को न रोकने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं. अब सवाल यह है कि आखिर यह जंग समाप्त कब होगी?

वसीम अहमद

पहले खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो गलती की थी उसी गलती को आज इजरायल दोहरा रहा है. इस युद्ध की शुरुआत कुवैत की रक्षा के लिए की गई थी और इसकी समाप्ति सद्दाम हुसैन से बदले के रूप में हुई थी. इस बदले की कार्रवाई में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए. 1991 में अमेरिका ने कुवैत की रक्षा के लिए कुवैत पर हवाई हमला किया था. उसके बाद गठबंधन सेनाओं की तरफ से लगातार हवाई हमले होते रहे. नतीजतन सद्दाम हुसैन की फौज परास्त होकर वापस लौट गई. इराकी फौज की वापसी के बाद खाड़ी युद्ध के लंबे समय तक चलाने का कोई औचित्य नहीं बच गया था. सद्दाम हुसैन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए था लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और हमले जारी रखे. यहां तक कि 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ्तार कर लिए गए फिर इराक की एक अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी.

यहां पर इस घटना जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि पहले खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से इराकी फौजियों की वापसी अगर एक बार हो गई थी तो फिर इराक पर अमेरिकी हमले का कोई औचित्य ही नहीं रह गया था. अमेरिका ने इराक पर व्यापक विनाश के हथियारों का बहाना बनाकर दोबारा हमला किया. जबकि सद्दाम हुसैन लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि उनके पास ऐसे कोई हथियार मौजूद नहीं हैं और उनकी फांसी के बाद अमेरिका ने यह माना कि इराक के पास कोई रासायनिक या जैविक हथियार नहीं था.

अब सवाल यह उठता है कि झूठी बूनियाद के ऊपर इराक पर जो इतनी बड़ी तबाही मचाई गई जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है. अपनी इस गलती से अमेरिका ने सबक क्यों नहीं सीखा और आज इजरायल भी वह गलती दोहरा रहा है जो अमेरिका ने इराक में की थी और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका इजरायल की इस गलती में साथ दे रहा है. इजरायल के रवैये से मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंसटीन के कथन की याद आ रही है. जब उन्हें इजरायल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी ऐसे देश का राष्ट्रपति बनना नहीं पसंद करूंगा जिसकी बुनियाद बेगुनाहों के आंसुओं, बेकसूरों के खून, उनकी सरजमीन से उन्हें उजाड़ कर की गई हो. आइंसटीन ने कई दशक पहले इजरायल की क्रूरता को महसूस कर लिया था मगर अमेरिका को आज तक इजरायल में कोई कमी नहीं नजर आ रही है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 47 सदस्य हैं उनमें 17 सदस्य किसी वजह से इस बार वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके जबकि 29 देशों ने इजरायल के खिलाफ वोट किया. अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने इजरायल के समर्थन में वोट किया था. दरअसल वो इजरायल की कारगुजारियों को सही समझता है और उसके दावे को जायज ठहरा रहा है कि इजरायल के तीनों लड़कों को अगवा और कत्ल करने में हमास का हाथ था. जबकि हमास के मुखिया पहले दिन से इस बात से इंकार कर रहे हैं लेकिन हमास की अपील सुनने की बजाए इजरायल ने गाजा पर हवाई और जमीनी हमले कर दिए. जिसके कारण 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हैं, जिनमें बड़ी संख्या औरतों और बच्चों की है. लेकिन तीन हफ्ते के बाद इजरायल पुलिस के फॉरेन प्रेस के प्रमुख इंस्पेक्टर मकीरोजन फील्ड ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के सामने खुलासा किया कि इन तीनों लड़कों के कत्ल में हमास का हाथ नहीं है. अब सवाल यह है कि छानबीन किए बिना ही गाजा पर हमला क्यों किया गया और अब जब कि सच्चाई सामने आ गई है तो इस तबाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इराक ही अवस्था यहां की भी हो जाएगी और अमेरिका की तरह इजरायल भी इसे एक मामूली गलती बताकर हजारों लोगों की मौत से दामन झाड़ लेगा. शायद यह इसलिए किया जा रहा है जिससे इजरायली रिहायशी इलाकों को और फैलाया जा सके.

अब सवाल यह उठता है कि झूठी बूनियाद के ऊपर इराक पर जो इतनी बड़ी तबाही मचाई गई जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है. अपनी इस गलती से अमेरिका ने सबक क्यों नहीं सीखा और आज इजरायल भी वह गलती दोहरा रहा है जो अमेरिका ने इराक में की थी और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका इजरायल की इस गलती में साथ दे रहा है.

हमास पर आरोप क्यों लगाए गए ?

12 जून को तीन इजरायली लड़कों को अगवा कर लिया गया. ये सभी किशोरवय लड़के थे. इन तीनों को वेस्ट बैंक के दक्षिण से अगवा किया गया था जिनमें से एक ने किसी तरह से इजरायली पुलिस से संपर्क साध कर अपहरण की जानकारी दी थी. इस कॉल को रिकॉर्ड भी किया. इस कॉल में पीछे से अरबी में बातें करते हुए लोग सुनाई दिए. यहीं से इजरायल को शक हुआ कि इनका अपहरण फलस्तीनियों ने किया है. इस शक को और मजबूती इस वजह से मिली क्योंकि इजरायली जेलों में बंद 300 फलस्तीनी कैदियों ने 50 दिनों से भूख हडताल कर रखी थी. इनमें से कई की हालत खराब है. उनकी मांग है कि इजरायल ने उन्हें बेकसूर कई सालों से जेल में बंद कर रखा है. हमास कई बार उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

इसी शक की बुनियाद पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने 15 जून को इस बात की घोषणा कर दी कि इन लड़कों को हमास ने अगवा किया है. इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियां इन लड़कों की तलाश में जगह-जगह छापे मारकर फलस्तीनियों को गिरफ्तार करने लगीं. इसके लिए जब एजेंसियों ने जनीन कैंप में घुसने की कोशिश की तो वहां मौजूद फलस्तीनियों ने उन्हें यह कहते हुए रोकने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट महमूद अब्बास इस बात से पहले ही इंकार कर चुके हैं कि लड़कों का अपहरण हमास ने नहीं किया है. इजरायल इस अपहरण के पीछे हमास की साजिश बता रहा था इसलिए उसने गाजा की उत्तरी बस्तियों को खाली करने का आदेश दे दिया. जब मामला आगे बढ़ने लगा तो इजरायल ने फौजी कार्रवाईयां शुरू कर दीं इसके जवाब में फलस्तीन की तरफ से भी कार्रवाई की गई और उसके बाद जो फलस्तीनियों के साथ हुआ वह दुनिया के सामने है.

30 जून को तीनों लड़कों की लाश अल खलील से मिली. तब यह जाकर यह राज खुला कि इस घटना के पीछे हमास का नहीं बल्कि किसी आतंकी संगठन का हाथ है. लाश मिलने के बाद जर्मनी के टीवी चैनल जेडडीएफ पर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि अपहरण के कुछ दिन बाद ही इजरायली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चल गया था कि इन सब के पीछे हमास का हाथ नहीं है. यह मामला सिर्फ अपहरण का नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो आवाजें सुनाई दे रही थीं उसमें तीनों लड़कों को गर्दन को नीचे झुकाने के लिए कहा गया और बाद में दस गोलियां चलने की आवाज भी आई. लेकिन इसके बाद भी इजरायल हमास पर आरोप लगा कर हमले करता रहा.

हैरानी की बात यह है कि इजरायल इस हमले में किसी की परवाह नहीं कर रहा है. सुरक्षा परिषद के 29 देश इस हमले की निंदा कर चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ बार फौजी कार्रवाई रोक कर शांतिपूर्वक इस समस्या को सुलझाने की अपील कर चुका है लेकिन नेतान्याहू की नियत लड़ाई को आगे तक खींचने की है. उन्होंने कहा भी है कि जब तक फलस्तीन के सारे हथियार समाप्त नहीं हो जाते तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी. इजरायल के पीएम अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी करते हुए वे रिहायशी इलाकों और बच्चों के स्कूल को भी निशाना बना रहे हैं. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिलीफ एजेंसी अवनजदा के स्कूल को स्कूल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम बीस बच्चे मारे गए. यह हमला किसी गलती की वजह से नहीं हुआ था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस गेनिज के मुताबिक इजरायली फौजी को 17 बार बताया गया था कि इस स्कूल में शरणार्थी पनाह लिए हुए हैं. इस हमले की भर्त्सना करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के गाजा में रिलीफ मिशन के डायरेक्टर बॉब टर्नर का कहना है कि इजरायली हमला जानबूझ कर किया गया जो हैवानियत की निशानी है.

ये जंग कब रुकेगी

मिस्र की तरफ से पहले भी युद्ध विराम की कोशिश की गई थी लेकिन सिर्फ 6 घंटे के विराम के बाद इजरायली हमले शुरू हो गए जिसके जवाब में हमास ने कई रॉकेट दागे. मिस्र एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है जिसके लिए नया मसौदा तैयार किया गया है जिससे दोनों देशों की सहमति हो. इस बार मिस्र ने फलस्तीन की तरफ से हमास के प्रतिनिधि को भी शामिल किया है जबकि पहले युद्ध विराम के दौरान हमास शामिल नहीं था. लेकिन सबसे बडा सवाल यह है कि इस कोशिश का क्या हश्र होगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

एक महीने के बाद पुंडलीक राव अन्य मित्रों सहित नारियल लेकर शिरडी रवाना हुए. जब वे मनमाड पहुंचे, तो प्यास लगने के कारण एक नल पर पानी पीने गए. खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने चिवड़ा खाने को निकाला, जो कुछ अधिक तीखा–सा प्रतीत हुआ.

साई करेंगे बेड़ा पार

चौथी दुनिया ब्यूरो

संत एक–दूसरे से किस तरह प्रेम करते हैं, यह इस कथा में साफ़ दिखाई देता है. एक बार वासुदेवानंद सरस्वती, जो टेबें स्वामी थे, उनसे पुंडलीक राव नामक एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे मिलने आए और साई बाबा का जिक्र किया. बाबा का नाम सुनते ही स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुंडलीक राव को एक नारियल देकर कहा, तुम जाकर मेरे भ्रात साई को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरें और सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें. पुंडलीक राव ने नारियल लेकर कहा, मैं इसे बाबा को दे दूंगा. स्वामी जी अपनी कर्मकांडी पद्धति के अनुसार दिन–रात अग्निकुंड में आग प्रज्जवलित रखते थे और उसी तरह साई बाबा की धूनी भी दिन–रात मस्जिद में जलती रहती थी.

एक महीने के बाद पुंडलीक राव अन्य मित्रों सहित नारियल लेकर शिरडी रवाना हुए. जब वे मनमाड पहुंचे, तो प्यास लगने के कारण एक नल पर पानी पीने गए. खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने चिवड़ा खाने को निकाला, जो कुछ अधिक तीखा–सा प्रतीत हुआ. उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़ कर उसमें खोपरा मिला दिया. दुर्भाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा, वह वही था, जो स्वामी जी ने साई को भेंट में देने के लिए दिया था. शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की याद आई. उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया. डरते–डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए. बाबा को नारियल के संबंध में स्वामी जी से तार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पुंडलीक राव से प्रश्न किया, मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ. पुंडलीक राव ने बाबा के चरण पकड़ कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए उनसे क्षमायाचना की. वे उसके बदले दूसरा नारियल देने को तैयार थे, लेकिन बाबा ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य किसी भी नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति साधारण नारियल से नहीं हो सकती. फिर वह बोले, अब तुम चिंता न करो. मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया और मार्ग में फोड़ा गया. तुम स्वयं में दोषी होने की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कार्य करते समय स्वयं को कार्य करने वाला न जानकर अभिमान एवं अहंकार से परे होकर कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुतगति से प्रगति होगी. साई बाबा यह आध्यात्मिक उपदेश कितना सुंदर था!

इसी प्रकार एक दूसरी कथा है. बालाराम नामक एक व्यक्ति थे, जो मुंबई के उच्च न्यायालय में वकील थे और किसी समय शासकीय विधि विद्यालय मुंबई के प्राचार्य भी. उनका पूरा परिवार सात्विक एवं धार्मिक था. एक बार उनका ध्यान आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर गया. उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका ज्ञानेश्वरी एवं अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया. वह पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे. एक बार उन्हें साई बाबा के दर्शन का लाभ हुआ. कुछ महीने पहले उनके भाई बाबुल जी और एक अन्य शख्स ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे. उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी बालाराम एवं परिवार के अन्य लोगों को सुनाए. तब सभी लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया. शिरडी में उनके पहुंचने के पहले ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं. अन्य लोगों द्वारा बाबा के उक्त वचन सुनकर बालाराम के परिवार को महान आश्चर्य हुआ. उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को पहले से कोई सूचना नहीं दी थी. सभी ने बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे. बाबा ने अन्य लोगों को बताया, ये मेरे दरबारीगण है, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था. फिर परिवार से बोले, मेरा और तुम्हारा परिचय कई जन्म पुराना है. सभी नम्र एवं सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे–बैठे बाबा की ओर निहारते रहे. उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच एवं कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई.

इसके बाद वे सब अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए गए और भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे. उस समय बाबा चिलम पी रहे थे. उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया. यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी. बालाराम के लिए तो यह अनमोल समय था. वह कई वर्षों से श्वांस रोग से पीड़ित थे, लेकिन चिलम पीते ही रोग मुक्त हो गए. उन्हें फिर कभी यह कष्ट नहीं हुआ. वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वांस रोग का दौरा पड़ा. यह वही दिन था, जब बाबा ने महा–समाधि ली. वह गुरुवार के दिन शिरडी आए थे. भाग्यवश उसी रात्रि उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया.

आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा. दूसरे दिन कांकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश पुनः दिखाई दी. कहने का आशय यह कि सभी भक्तों को बाबा में अपने इष्ट की झलक समय–समय पर मिलती रहती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

अंग्रेजी थोपी न जाए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा एवं पूर्व के जनसंघ का मुख्य नारा हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान था, पर जब से उसने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपना नया अवतार लिया है, तबसे उसकी चाल, चरित्र और चेहरे में इतना परिवर्तन आ गया है कि उसमें जनसंघ वाली पुरानी विचारधारा काफी लुप्त हो गई है. जाहिर है, उसने भी ऐन–केन–प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के लिए अपना चरित्र इतना बदल लिया है कि अब कांग्रेस और भाजपा में कहीं कोई खास बुनियादी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता. पहले कांग्रेस अंग्रेजी पर अपनी नीतियां साफ़ करने की बजाय केवल टालती रही और अब भाजपा वही कर रही है. भारत के संदर्भ में तो अंग्रेजी वह सामंती भाषा है, जो सिर्फ़ गुलामी का प्रतीक नहीं, शोषण का भी हथियार बनी. कहा जाता है कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, तो इसी तर्क के आधार पर और किस अधिकार के बूते इस देश में अंग्रेजी बनी रहेगी और हिंदीभाषियों के ऊपर थोपी जाएगी? क्या यह एक ही आधार पर दोहरे मापदंड का प्रतीक नहीं है? इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा देश– विदेश में शोषण और गुलामी की प्रतीक सामंती भाषा अंग्रेजी में संबोधन रोका जाना चाहिए.

–शिवकुमार फैजाबादी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.

अच्छे दिनों की आहट

पिछले दिनों भाजपा पूर्ण बहुमत और अपनी नई टीम के साथ सत्ता में आई. उस पर भारत के सपने पूरे करने की ज़िम्मेदारी है. नरेंद्र मोदी के आगमन ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है. उनकी कार्यशैली, कल्पना शक्ति, क्षमता एवं कौशल के बलबूते देश की दिशा बदलेगी, ऐसी उम्मीद है. जनता विकास और सुशासन चाहती है. लोगों ने इस बार चुनाव में एक बहुत बड़ा काम यह किया कि विभाजनकारी सेक्युलर राजनीति को धूल चटा दी. सेक्युलर शब्द का जितना दुरुपयोग इस देश में हुआ, उसकी मिसाल मिलना कठिन है. निश्चित तौर पर अब अच्छे दिनों की आहट मिलने लगी है. स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता और उससे संबंधित हलफनामे को लेकर विपक्ष हमला कर रहा है. वास्तव में इस तेज रफ्तार ज़िंदगी में हर चीज के लिए योग्यता आवश्यक है. इसलिए देश के रहनुमा भी योग्य एवं शिक्षित हों, यह ज़रूरी है.

–गौरव निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

अमीरों की सरकार

कवर स्टोरी–यह अमीरों का बजट है, जनता का नहीं (21 जुलाई–27 जुलाई) काफी विचारोत्तेजक है. यह लेख बताता है कि सरकार किस प्रकार अमीरों पर मेहरबान है. जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन आम बजट में महंगाई कम करने की कोई योजना सामने नहीं आई. रेल का किराया बजट के पहले ही सरकार ने बढ़ा दिया. वह सब्सिडी ख़त्म करने की बात कहती है. यदि सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, तो महंगाई और बढ़ेगी. सरकार ने एलआईसी में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने समेत अन्य क्षेत्रों में एफडीआई का रास्ता खोल दिया है. इससे हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा और देश का धन विदेशों में जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह सरकार ग़रीबों की है, लेकिन आम बजट में ग़रीब कहीं दिखाई नहीं देता. यह कैसी ग़रीबों की सरकार है? दरअसल, यह ग़रीबों की नहीं, केवल कॉरपोरेट्स और अमीरों की सरकार है.

–पवन सिंह, बलिया, उत्तर प्रदेश.

घोषणा नहीं, अमल चाहिए

आलेख–आम बजट 2014: यह किसानों के साथ धोखा है (21 जुलाई–27 जुलाई) पढ़ा, काफी तथ्यपरक है. आम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है. पिछली सरकारों भी अपने बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी समेत कई घोषणाएं कीं. केवल घोषणा करने से किसानों के अच्छे दिन नहीं आएंगे, बल्कि ज़रूरत घोषणाओं पर अमल करने की है. इस आम बजट के अनुसार, उन्हीं किसानों को कर्ज पर ब्याज में तीन फ़ीसद की छूट दी जाएगी, जो समय पर अदायगी करेंगे. सरकार ने सिंचाई समेत कई अन्य नई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन देखना यह है कि उन पर अमल कब होता है? *–रवि कुमार, रीवा, मध्य प्रदेश.*

कब आएंगे अच्छे दिन

आलेख–आम बजट न घर का और न घाट का (21 जुलाई–27 जुलाई) पढ़ा. कमल मोरारका ने सही कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जनता से चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई कम करने, रोज़गार उपलब्ध कराने समेत कई वादे किए थे, लेकिन 60 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई. नरेंद्र मोदी की सरकार केवल बड़ी–बड़ी घोषणाएं कर रही है, बुलेट ट्रेन से लेकर महंगाई कम करने तक. रेल किराया बढ़ा दिया गया, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम दोयम दर्जे के हैं, यात्रियों को घटिया खाना परोसा जा रहा है. सरकार इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. वह केवल जनता का ध्यान बांटने का कोशिश कर रही है.

–रश्मि शर्मा, भजनपुरा, दिल्ली.

निर्भीक समाचार–पत्र

चौथी दुनिया एक निर्भीक एवं तथ्य आधारित समाचार–पत्र है, जो आज के दौर में भी मिशन वाली पत्रकारिता कर रहा है. इसमें प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद नई–नई जानकारियां हासिल होती हैं. संतोष भारतीय द्वारा लिखा गया तोप मुकाबिल पढ़कर काफी अच्छा लगता है. इसमें कवर स्टोरी से लेकर जगमग दुनिया तक यानी सभी पृष्ठों पर प्रकाशित सामग्री काफी अच्छी होती है. आशा है कि चौथी दुनिया में आगे भी ऐसी ही सामग्री पढ़ने को मिलती रहेगी. *–आशीष सिंह, झांसी, उत्तर प्रदेश.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कहानी

राह का साथी

किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम ब्रह्मदत्त था. एक बार उसे किसी दूसरे गांव में कोई काम आ पड़ा. वह चलने लगा, तो उसकी मां ने कहा, बेटा अकेले न जाओ. लड़के ने कहा, तुम इतना क्यों घबराती हो मां? इस रास्ते में कोई विघ्न–बाधा नहीं है. मां ने देखा, लड़का टस से मस नहीं हो रहा है, तो उसने उसे एक केकड़ा देते हुए कहा, अच्छा, कोई और साथी नहीं है, तो तुम इस केकड़े को ही साथ ले लो. हो सकता है, यही तुम्हारे किसी काम आ जाए. मां का मन रखने के लिए लड़के ने उस केकड़े को पकड़ कर कपूर की एक डिबिया में रख लिया और उसे एक झोले में डालकर चल पड़ा.

कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका और वहीं सो गया. इसी बीच उस पेड़ के कोटर से एक सांप निकला और रेंगता हुआ ब्राह्मण के पास चला आया. सांपों को कपूर की गंध बहुत भाती है, इसलिए वह पोटली फाड़कर उसमें रखी डिबिया ही निगलने लगा. इसी बीच डिबिया खुल गई और डिबिया में रखे केकड़े ने निकल कर सांप का गला पकड़ लिया और उसकी जान ले ली. ब्राह्मण की नींद खुली, तो वह हैरान रह गया. देखता क्या है कि कपूर की डिबिया से सिर टिकाए सांप मरा पड़ा है. उसे समझते देर नहीं लगी कि यह डिबिया में रखे केकड़े का ही काम है. तब उसने सोचा कि मैंने अपनी मां की बात मान ली, सो ठीक ही किया.

शिक्षा : जीवन में अकेले रहने की बजाय एक साथी का होना लाभदायी होता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

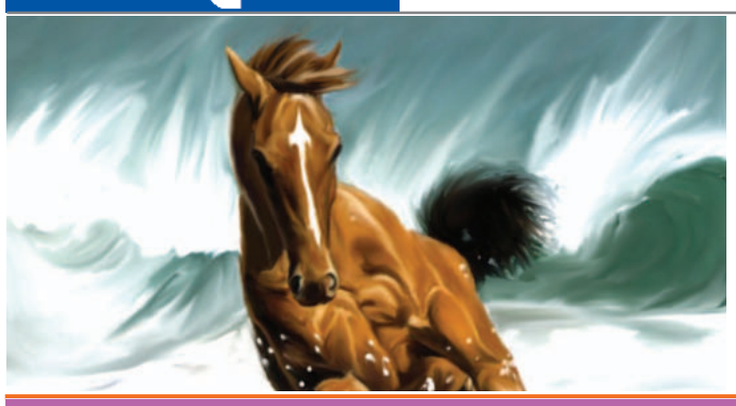

बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से. उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. सोचने लगा, भाग्य की बात है. ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों जैसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी, तो क्या?

सूत्र एक, आख्यान तीन

अनंत विजय

अपने उपन्यास कठगुलाब पर लिखते हुए मृदुला गर्ग ने कठगुलाब कैसे उगा शीर्षक से एक लेख लिखा था. उस लेख में उन्होंने माना था कि अपने परिवेश से सरोकार रखे बगैर कोई साहित्य नहीं रचा जा सकता. हां, यह परिवेश तात्कालिक समय और समस्या के दायरे में कैद नहीं होता. सब तरफ़ से कटा हुआ आदमी संन्यासी होता है और उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता. द्वन्द्व के बिना साहित्य का जन्म संभव नहीं है. उपन्यास में रचनाकार का द्वंद्व उसके पात्र इस तरह से जज्ब कर लेते हैं कि वह उससे ज़्यादा, उसका द्वंद्व बन जाता है. इसी तरह से मृदुला गर्ग की बहन एवं हिंदी साहित्य को अपने लेखन से झकझोर देने वाली मंजुल भगत ने भी लिखा है, कल्पना कितनी भी मर्मज्ञ क्यों न हो और कलम कितनी भी शक्तिशाली, लेखक को जीवन में भागीदार होना ही पड़ेगा. सच्चा लेखन जीवन से जुड़कर, जी कर ही संभव है. लेखक हर पल लेखक नहीं है. वह एक संवेदनशील व्यक्ति है, जिसके लिए जीना और लिखना, दोनों महत्वपूर्ण हैं, तभी तो जाने कब का जिया हुआ आज लिखा जाता है.

बिसात: तीन बहनें, तीन आख्यान पढ़ते हुए मंजुल भगत और मृदुला गर्ग का लिखा उपरोक्त अंश अनायास ही ज़हन में कौंध गया. हिंदी साहित्य में यह संयोग दुर्लभ है कि एक ही जिल्द में तीन कथाकार बहनों की एक ही थीम या चरित्र के इर्द-गिर्द लिखी रचना उपलब्ध हो. बिसात: तीन बहनें, तीन आख्यान में यह दुर्लभ संयोग घटित हुआ है. इस किताब में मंजुल भगत की रचना बेगाने घर में, मृदुला गर्ग का उपन्यास वंशज एवं अचला बंसल की कहानी कैरम की गोटियां प्रकाशित हैं. तीनों ही रचनाओं में परिवार है, घर है, घर का तनाव है, पिता है, पुत्र है, मां है, बहू है, बच्चे हैं. मंजुल और मृदुला के उपन्यासों का तो परिवेश भी एक है. कोठी है, नौकर-चाकर हैं, बाग-बगीचे हैं आदि आदि. वहीं अचला बंसल की कहानी में परिवेश अवश्य बदला हुआ है. वहां कोठी की जगह फ्लैट ने ले ली है. हवेली के लॉन की जगह पिता और बच्चों का कमरा है. लेकिन, इन तीन रचनाओं में जो एक कॉमन थ्रेड है, वह है पिता-पुत्र संबंध और उसके बीच का तनाव. ज़िंदगी की बिसात पर पिता और पुत्र के संबंध की कई गोटियां इधर से उधर होती रहती हैं, कभी पात्रों के रूप में, तो कभी स्थितियों के रूप में, तो कभी घटनाओं के रूप में. लेकिन, यह संबंध और उसके बीच का द्वंद्व स्थायी तौर पर हर जगह मौजूद रहता है.

अगर हम इस द्वंद्व के बारे में विचार करें, तो मंजुल के उपन्यास बेगाने घर में पिता के मन में पुत्र के ज़िंदा न होने की पीड़ा है. उपन्यास के केंद्रीय पात्र किशोर चंद्र हवेली में अपने तमाम कारकुनों के साथ रहते हुए भी निजता के एकांत क्षणों में अपना दर्द महसूस करते रहते हैं. पत्नी की याद संजोकर संदूक में रखते हैं. एक प्रसंग में उनका नौकर कहता है, एक संदूक में मालकिन की तस्वीरें थीं, जो मालिक ने दीवारों पर से उतरवा दी थीं, उन्हें सहन नहीं होती थीं. एक में बड़े पलंग का बिस्तर, चादरें, मेजपोश बगैरह थे. कितनों पर तो मालकिन के हाथ के बेल-बूटे कढ़े थे. मालिक ने उन्हें अपने लिए कभी बिछाने न दिया. बेगाने घर में मंजुल भगत ने अपने समय के परिवेश के बहाने समाज पर भी तल्ख टिप्पणी की है. जीते जी याद न करने वाले रिश्तेदार मरने के बाद गिद्धों की तरह मंडराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें संपत्ति की गंध आकर्षित करती है. इस तरह का माहौल तब भी था, अब भी है. हमारा समाज लाख दावा करे कि वह इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर गया है और आधुनिक होने की होड़ में शामिल है, लेकिन संपत्ति का लालच उन्हें तमाम आधुनिकताओं से पीछे खींच लाता है. मंजुल भगत के इस उपन्यास की एक और खास बात है कि इसमें हवेली के नौकरों के बीच के संवाद बेहद दिलचस्प हैं. भाषा पर मंजुल का अद्भुत अधिकार है और जिस कथा को आगे बढ़ाने में संवाद का सार्थक उपयोग मंजुल ने अपने इस उपन्यास में किया है, उसे पढ़ते समय संवाद की ज़हन में सिर्फ़ छवि नहीं बनती, बल्कि वे सुनाई भी देते हैं और आपको उस परिवेश में खींच कर ले जाते हैं. इसे पढ़ते हुए गांव की पुरानी हवेलियां ज़हन में उपस्थित हो जाती हैं. गनपत एवं रतनी के बीच का मूक प्रेम भी मंजुल ने बेहद खूबसूरती के साथ दबा ही रहने दिया है, लेकिन संकेत पर्याप्त दिए हैं. साहित्य में जीवन की सिर्फ़ बात ही नहीं करती थीं मंजुल, बल्कि उन्होंने अपने इस उपन्यास में ग्राम जीवन को उतार कर रख दिया है.

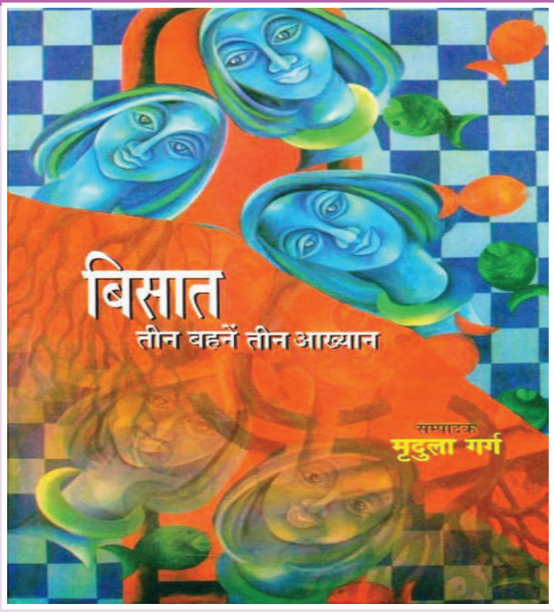

समीक्ष्य कृति-बिसात : तीन बहनें, तीन आख्यान
संपादक : मृदुला गर्ग
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 350 रुपये

इसी तरह से जब मृदुला गर्ग जिस द्वंद्व की बात करती हैं, वह उनके उपन्यास वंशज में काफी खुलकर सामने आता है. जज शुक्ला और उनके बेटे सुधीर के बीच जटिल संबंध है. इस संबंध की बुनियाद बचपन में ही पड़ गई थी. सुधीर की मां की अकाल मृत्यु और शुक्ला जी का बेटी रेवा पर अगाध स्नेह का असर सुधीर के बाल मन पर पड़ता है और वह बचपन से ही विद्रोही हो जाता है. पिता अपने पुत्र को दिल की गहराइयों से चाहते हैं, लेकिन जिस दौर की यह कहानी है, उस दौर के सारे पिता आम तौर पर कड़क मिजाज होते थे. परवरिश और पिता के रहन-सहन, मन-मिजाज ने भी सुधीर को विद्रोही बनाने में मदद की. आज़ादी की लड़ाई के दौर में सुधीर का झुकाव संघ की ओर होता है और वह संघ की विचारधारा के प्रभाव में आकर अपने पिता को अंग्रेजों का पिट्ठू तक समझने लगता है. सुधीर का जो चरित्र मृदुला गर्ग ने उकेरा है, वह बेहद जटिल और उलझा हुआ है. सुधीर के मनोविज्ञान का विश्लेषण करना आसान नहीं है. संघ की ओर झुकी आत्मा के आधार पर सुधीर अपने पिता से नफरत करता है, लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद उसके कुछ दोस्त मिठाई बांटने के लिए उससे चलने का आग्रह करते हैं, तो वह आक्रामक हो जाता है. पर सुधीर यहीं रुकता है. कालांतर में जब वह धनबाद में नौकरी करने जाता है या फिर अरनी फैक्ट्री लगाता है, तो मज़दूरों के हितों की वकालत करते हुए कॉमरेड नज़र आता है. इतने जटिल चरित्र की रचना करते हुए भी मृदुला गर्ग उसे अंत तक संभालने में कामयाब रहती हैं. इस तरह हम कह सकते हैं कि ऊपर से दिखने में यह उपन्यास भले ही पारिवारिक, पिता-पुत्र के संबंधों एवं द्वंद्वों पर लिखा गया लगे, लेकिन अगर गहनता और सूक्ष्मता से पड़ताल करें, तो आज़ादी के पहले और उसके बाद के दौर की राजनीति एवं नौकरशाही पर भी यह टिप्पणी करता चलता है.

अंत में अचला बंसल की एक अपेक्षाकृत छोटी कहानी है कैरम की गोटियां. इस कहानी का आकार भले ही छोटा है, लेकिन कैनवस बड़ा है. जिस तरह मंजुल और मृदुला ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश को कथा का आधार बनाया है, वहीं अचला ने शहरी परिवेश के आधार पर कहानी बुनी है. यहां पीढ़ियों के बदलाव का मनोविज्ञान है. कैरम की गोटियां दरअसल ज़िंदगी की काली-सफेद गोटियां हैं, जो पात्रों को चुनौती देती हैं. इन तीनों रचनाओं को पढ़ने के बाद सिर्फ़ इतना कहना चाहूंगा कि इनके लेखकों ने अपने समय का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि अपने समय के इतिहास का इस्तेमाल किया है. नतीजा यह कि बदले हुए वक्त में भी ये रचनाएं वर्तमान से क़दमताल कर सकती हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

हार की जीत

सुदर्शन (1895-1967) प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं. उनका दृष्टिकोण सुधारवादी है. मुंशी प्रेमचंद एवं उपेंद्र नाथ अश्क की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते रहे. उनकी गिनती विश्वंभर नाथ कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह एवं भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है.

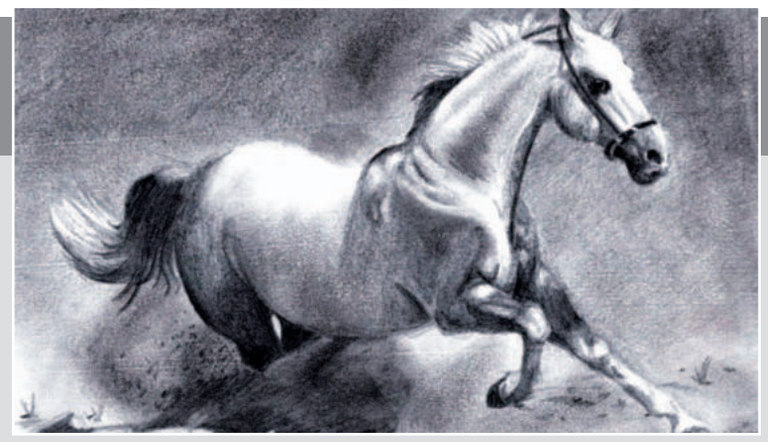

मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. भगवद् भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता. वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान. उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख-देखकर प्रसन्न होते. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि सब-कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. वह गांव से बाहर एक छोटे-से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी. वह उसकी चाल पर लट्टू थे. कहते, ऐसे चलता है, जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर आठ-दस मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता.

खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है?

खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है.

कहो, इधर कैसे आ गए?

सुल्तान की चाह खींच लाई.

विचित्र जानवर है, देखोगे, तो प्रसन्न हो जाओगे.

मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है.

उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी!

कहते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है.

क्या कहना! जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है.

बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं.

बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से. उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. सोचने लगा, भाग्य की बात है. ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों जैसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी, तो क्या?

दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए बाबा का हृदय अधीर हो गया. घोड़े को खोलकर बाहर लाए और सवार हो गए. घोड़ा वायु-वेग से उड़ने लगा. उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लोट गया. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वह अपना अधिकार समझता था. उसके पास बाहुबल था और आदमी भी. जाते-जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा.

बाबा भारती डर गए. अब उन्हें रात को नींद न आती. सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी. प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया. बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता. कभी घोड़े का शरीर देखते, कभी उसका रंग और फूले न समाते थे. सहसा एक आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना.

आवाज़ में करुणा थी. उन्होंने घोड़े को रोक लिया. देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है. बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है?

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो. रामावाला यहां से तीन मील है, मुझे वहां जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा.

वहां तुम्हारा कौन है?

दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं.

बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ कर धीरे-धीरे चलने लगे. सहसा उन्हें एक झटका-सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है. उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिश्रित चीख निकल गई. वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था. बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ निश्चय करके पूरी ताकत से चिल्ला कर बोले, ज़रा ठहर जाओ.

खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा.

परंतु एक बात सुनते जाओ.

खड़ग सिंह ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर इस तरह देखा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है. मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा.

बाबा जी, आज्ञा कीजिए. मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा न दूंगा.

अब घोड़े का नाम न लो. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना.

खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है?

सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता चला, तो वे दीन-दुखियों पर विश्वास न करेंगे. यह कहते-कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध न रहा हो.

बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है! उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था. कहते थे, इसके बिना रह न सकूंगा. इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, परंतु आज उनके मुख पर दु:ख की रेखा तक न थी. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन-दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें. ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है.

रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था. वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था. खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुलतान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. चौथा पहर शुरू होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल कर ठंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंच कर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन-मन भर का भारी बना दिया. वह वहीं रुक गए. घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप पहचान ली और ज़ोर से हिनहिनाया. अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुंह पर थपकियां देते. फिर वह संतोष से बोले, अब कोई दीन-दुखियों से मुंह न मोड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

स्मार्ट फोन मोटो एक्स प्लस 1

मोटोरोला ने बाज़ार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नया स्मार्ट फोन मोटो एक्स प्लस 1 लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. मोटोरोला का यह हैंडसेट लकड़ी जैसी सतह का है. इसमें एक ईयरपीस ग्रिल और एक लाउड स्पीकर ग्रिल फ्रंट में है, ठीक वैसा, जैसा मोटो जी में है. इसमें दो एलईडी फ्लैश हैं और इसके पीछे प्लास्टिक का मोटोरोला लोगो है, लेकिन इसकी साइड एल्युमिनियम की है. इसमें 5.1 इंच की स्क्रीन और 12 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है, जबकि फ्रंट में 5 एमपी का. कंपनी मोटोरोला मोटो एक्स प्लस 1 और मोटो–360 एक साथ बिक्री के लिए उतारेगी.■

तैरते हुए लीजिए गाने का मजा

अगर आप नहाते या तैरते वक्त गाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए बाज़ार में वाटरप्रूफ स्पीकर आने वाला है. एक्का सनब्लास्ट वाटरप्रूफ स्पीकर आप अपने साथ स्विमिंग पूल में भी ले जा सकते हैं. इसका निर्माण पायले ऑडियो कंपनी ने किया है. इस वाटरप्रूफ स्पीकर में ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे यूजर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करके मनपसंद संगीत का आनंद उठा सकते हैं. खास बात यह कि इसे 32 फीट की दूरी से भी ब्लूटूथ के जरिये संचालित किया जा सकता है. इसमें स्टीरियो स्पीकर का प्रयोग किया गया है. इस स्पीकर में माइक्रो एसडी कार्ड एवं एफएम रेडियो भी है. इसमें रिचार्जेबल लीथियम आयन बैट्री है, जिसे यूएसबी चार्जिंग केबल के जरिये आसानी से चार्ज किया जा सकता है. इसकी क़ीमत लगभग 6000 रुपये है.■

क्या आपका पार्टनर चीटर है?

आजकल सभी लोग अपने पार्टनर को लेकर सजग रहना चाहते हैं कि कहीं वह धोखा तो नहीं दे रहा है. अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो एमकपल (mcouple) एप्लिकेशन की मदद से इस चिंता से निजात मिल सकती है. यह स्मार्ट फोन की नई एप्लिकेशन है, जिसके जरिये आप किसी भी व्यक्ति की अधिकांश जानकारी हासिल कर सकते हैं.

यदि इसे आप अपने संस्थान में प्रयोग करते हैं, तो उसकी गोपनीयता भंग होने का भी डर है. अपने स्मार्ट फोन में यह एप्लिकेशन डाउनलोड करने केबाद सिर्फ़ एक बार अपने पार्टनर के मोबाइल में यह एप्लिकेशन इनकमिंग–आउट गोइंग कॉल और मैसेज में प्रवेश करानी होगा. इसके बाद यह ऐप अपना काम शुरू कर देगा और आपको उसके फोन से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा. इस एप्लिकेशन की मदद से आप अपने पार्टनर के सोशल साइट एकाउंट जैसे फेसबुक, स्काइप आदि पर भी नज़र रख सकते हैं.

ऐप केजरिये पार्टनर के फोटो एवं वीडियो भी देखे जा सकते हैं. कंपनी ने यह एप्लिकेशन खास तौर पर माता–पिता के लिए है, जिससे वे अपने बच्चों की विभिन्न गतिविधियों पर नज़र रख सकें, हालांकि इसका उपयोग धोधाधड़ी करने वाले पार्टनर का पर्दाफाश करने के लिए भी किया सकता है.■

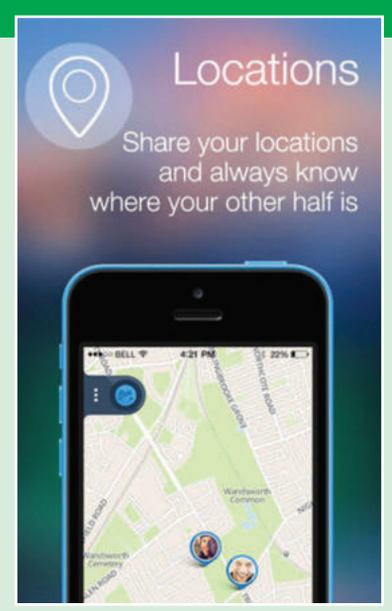

सेलकॉन का मिलेनियम वॉग क्यू-455

यह स्मार्ट फोन 3–जी को सपोर्ट करता है और किटकैट से चलता है. इसमें वाई–फाई, ब्लूटूथ और जीपीआरएस उपलब्ध है.

सेलकॉन मोबाइल्स की ओर से टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मिलेनियम वॉग क्यू–455 हैंडसेट लॉन्च किया. कंपनी ने दावा किया है कि यह देश का सबसे पतला हैंडसेट है. इस डुअल सिम स्मार्ट फोन का वजन 130 ग्राम है और इसमें 2000 एमएएच की बैट्री है. इसकी स्क्रीन 4.5 इंच की है. यह स्मार्ट फोन 3–जी को सपोर्ट करता है और किटकैट से चलता है. इसमें वाई–फाई, ब्लूटूथ और जीपीआरएस उपलब्ध है. यह 1.2 जीएचजेड क्वाडकोर प्रोसेसर आधारित है. इस फोन की इंटरनल मेमोरी 16 जीबी है और इसमें 64 जीबी तक एक्सटर्नल कार्ड सपोर्ट भी है. इसका कैमरा 8 एमपी का है और इस फोन की क़ीमत 7,999 रुपये है.■

बहुरूपिया वायरस से करें बचाव

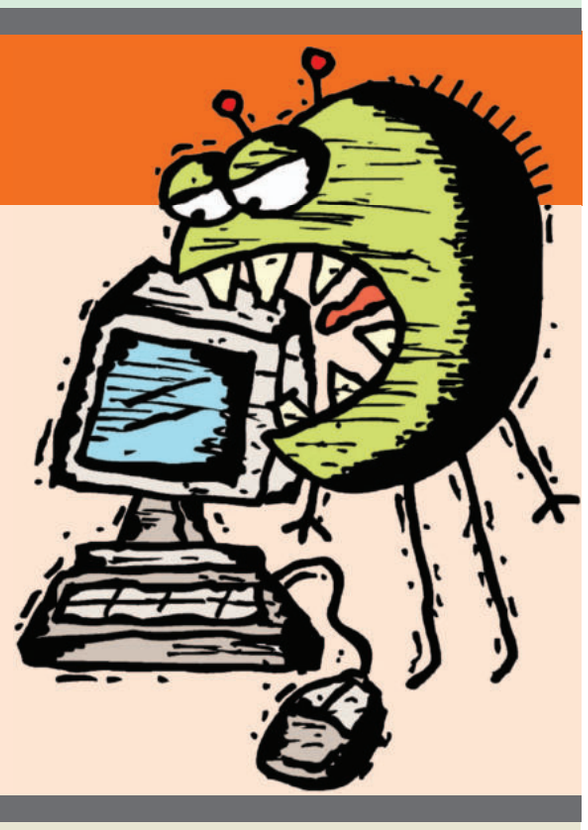

कंप्यूटर पर ब्लाडाबिंडी वायसर का ख़तरा मंडरा रहा है. साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के इंटरनेट यूजर्स को इस बहुरूपिए वायरस से सावधान किया है. यह वायरस अपनी असली पहचान छिपाने के लिए 12 रूप धारण कर सकता है और बाद में कंप्यूटर सिस्टम या यूजर की निजी जानकारी पर कब्जा कर सकता है. कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम–इंडिया (सर्ट–इन) ने कहा कि यह वायरस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब कर सकता है. यह दूसरे मालवेयर की तरह आम तौर पर पेनड्राइव एवं डाटा कार्ड से फैलता है. सर्ट–इन एक राष्ट्रीय एजेंसी है, जो भारतीय इंटरनेट क्षेत्र को हैकिंग से बचाने और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने का काम करती है. एजेंसी ने कहा है कि ब्लाडाबिंडी से बचाव के लिए फ्री मालवेयर वायरस रिमूवल टूल से कंप्यूटर स्कैन करें, विंडोज में ऑटोरन बंद कर दें और यूएसबी क्लीन या वैक्सिनेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें. ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करते रहें और उन्हें अपडेट रखें.

एंटी–वायरस और एंटी–स्पाइवेयर अपडेट रखें. एजेंसी ने सलाह दी कि यूजर को संदिग्ध वेब लिंक्स या ईमेल मैसेज के अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए. इसकी मदद से दूर बैठे हैकर को यूजर के सिस्टम तक पहुंचने का मौक़ा मिल जाता है. ब्लाडाबिंडी के कुछ प्रकार की–बोर्ड और कंप्यूटर के कैमरे पर कब्जा कर लेते हैं और जानकारी हैकर को भेज देते हैं.■

महिंद्रा मोजो–300 बहुत जल्द

कंपनी मोजो–300, 110 सीसी स्कूटर, जिसका कोड नेम जी–101 दिया गया है, के अलावा डिस्क ब्रेक के साथ नई महिंद्रा सेंचुरो 01–डी लॉन्च कर सकती है.

टू व्हीलर कंपनी महिंद्रा इस साल के अंत तक भारतीय बाज़ार में धूम मचाएगी. महिंद्रा ने चार नए टू व्हीलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है. इनमें स्कूटर, एंट्री लेवल बाइक और कुछ पिछली बाइक्स के नए वैरियंट उतारने की योजना है. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी मोजो–300, 110 सीसी स्कूटर, जिसका कोड नेम जी–101 दिया गया है, के अलावा डिस्क ब्रेक के साथ नई महिंद्रा सेंचुरो 01–डी लॉन्च कर सकती है. कंपनी मोजो बाइक कई एंडवास तकनीक और फीचर्स के साथ पेश करने वाली है. महिंद्रा मोजो में 300 सीसी क्षमता वाले दमदार इंजन का इस्तेमाल किया गया है. महिंद्रा मोजो 300 सीसी का सीधा मुकाबला केटीएम ड्यूक–390 और होंडा सीबीआर–250 आर जैसी बाइक्स से होगा. इस बाइक की क़ीमत 2 लाख रुपये तक हो सकती है. ■

बिना बिजली चार्ज होगा यूपीएस

आजकल घंटों तक बिजली न आना आम बात है, जिसके चलते मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पाते और बंद हो जाते हैं. हमें गर्मी से भी जूझना पड़ता है. ऐसे समय के लिए यूपीएस पावर एक अच्छा विकल्प साबित होता है. यूपीएस बनाने वाली कंपनी पावरसेफ ने किफायती क़ीमत यानी पांच हज़ार रुपये में पोर्टा–सोलर यूपीएस बाज़ार में लॉन्च किया है. इस पोर्टेबल लाइटिंग सल्यूशन के जरिये आप एक ही समय में 3 मोबाइल फोन, 3 सीएफएल बल्ब और एक पंखा चला सकते हैं.

यह उन क्षेत्रों के लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां मिनट–मिनट पर बिजली गायब हो जाती है. पोर्टा–सोलर यूपीएस का वजन 3 किलोग्राम है, इसलिए इसे कहीं भी लाने–ले जाने में दिक्कत नहीं होगी. इसे सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि अगर 70 वाट के पोर्टा–सोलर यूपीएस को चार्ज करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो इसे एसी पावर यानी सीधे बिजली से भी चार्ज किया जा सकता है. इस यूपीएस के साथ अलग से बैट्री जोड़ने का भी विकल्प है. यह 6–7 घंटे बैट्री बैकअप देने में सक्षम है.■

होंडा का मोबिलियो

होंडा ने अपना एमपीवी (मल्टी परपस व्हीकल) मोबिलियो भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने बाज़ार में धाक जमाने की नीति के तहत इसके दाम भी घोषित कर दिए हैं. इसके सबसे निचले पेट्रोल मॉडल की क़ीमत लगभग 6.49 लाख रुपये है, जबकि डीजल संस्करण की क़ीमत लगभग 7.89 लाख रुपये से शुरू होगी. कार की लंबाई 4.4 मीटर है. कंपनी ने कहा है कि इसमें बेहतर किस्म के अलॉय व्हील्स और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स लगे हुए हैं. पेट्रोल इंजन की बात करें, तो यह 1.5 लीटर आई–वीटेक है. इसमें 5 स्पीड गीयर बॉक्स, 119 पीएस का अधिकतम पावर और 145 एनएम का टार्क है. मोबिलियो दो इंजन ऑप्शन के साथ मौजूद है. 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर आई–वीटेक डीजल. कंपनी ने दावा किया है कि डीजल वर्जन 24.2 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल वर्जन 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. ■

कंपनी ने कहा है कि इसमें बेहतर किस्म के अलॉय व्हील्स और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स लगे हुए हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> वर्ष 2011 में ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग में तेजी आई. इसके बाद भारत रत्न के प्रावधान में संशोधन करते हुए खिलाड़ियों को भी इस पुरस्कार से नवाजे जा सकने का प्रावधान किया गया. यह बदलाव मुख्यरुप से ध्यानचंद को ध्यान में रखकर किया गया था.

ध्यानचंद से पहले सचिन को भारत रत्न क्यों?

कांग्रेस पार्टी ने देश के बहुत से संस्थानों को बर्बाद कर दिया यहां तक कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार को भी नहीं छोड़ा. सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का निर्णय उन्होंने कर लिया लेकिन ध्यानचंद के नाम को दरकिनार कर दिया, सचिन आज जितने बड़े भी खिलाड़ी क्यों न हों लेकिन ध्यानचंद का कद आज भी उनसे बहुत बड़ा है. सरकार ने सचिन को ध्यानचंद से पहले भारत रत्न देकर सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान का अपमान किया है, इस सम्मान का निर्णय किसी परिवार की डायनिंग टेबल पर नहीं किया जा सकता. यदि ऐसा हुआ है, तो यह भारत रत्न की छवि को धूमिल करता है.

नवीन चौहान

वर्ष 2011 में भारत रत्न दिए जाने के नियमों में कुछ मूलभूत बदलाव किए गए थे, जिन क्षेत्र के लोगों को यह सम्मान दिया जाता है उसमें मूलभूत बदलाव किए गए थे. जब सरकार ने यह कदम उठाया गया तब यह आशा की गई थी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जल्दी ही वह भारत रत्न से पुरस्कृत होने वाले पहले खिलाड़ी होंगे. ऐसा लोगों का इसलिए भी मानना था, क्योंकि ध्यानचंद देश ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें केवल देश में ही नहीं विदेश में भी ख्याति प्राप्त थी. लेकिन विडंबना यह है कि भारत को आजादी से पहले दुनिया में सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ी की लगातार अनदेखी की गई और हॉकी के जादूगर को भारत रत्न नहीं दिया गया. लेकिन क्रिकेट के जादूगर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उनके 200 वां टेस्ट मैच खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के ठीक अगले दिन ही भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी गई. खेल प्रेमी सरकार के इस फैसले से खुश भी थे और दुखी भी. खेल प्रमी चाहते थे कि भारत रत्न सबसे पहले उस खिलाड़ी को मिले जिसने गुलामी के दौर में भी भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई और भारतीय हॉकी को उसके सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया. ऐसी सफलता भारत को आज भी किसी खेल में नहीं मिल सकी है.

वर्ष 2011 में ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग में तेजी आई. इसके बाद भारत रत्न के प्रावधान में संशोधन करते हुए खिलाड़ियों को भी इस पुरस्कार से नवाजे जा सकने का प्रावधान किया गया. यह बदलाव मुख्यरुप से ध्यानचंद को ध्यान में रखकर किया गया था. 2013 में खेल मंत्री द्वारा उनके नाम की अनुशंसा किए जाने से पहले तक कई बार लोग ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग करते रहे हैं. खेल मंत्रालय ने इसके लिए पहल भी की. 16 जुलाई, 2013 को तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की अनुशंसा एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी. इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सहमति थी. लेकिन ध्यानचंद के मान को दरकिनार करते हुए सरकार ने 24 घंटे के अंदर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का निर्णय कर लिया. इसके पीछे क्या कारण हैं? पिछले साल ध्यानचंद को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला लगभग हो ही गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के सन्यास की घोषणा करने से अचानक सब कुछ बदल गया. 24 अक्टूबर 2013 को जाने माने वैज्ञानिक सी एन आर राव के नाम को प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन 14 नवंबर 2013 अचानक खेल मंत्रालय को सचिन का बायोडेटा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने को कहा गया, खेल मंत्रालय ने इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए बायोडॉटा प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया. नबंबर–दिसंबर के दौरान मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने थे. इस वजह से यूपीए सरकार को दोनों के नामों को स्वीकृति के लिए चुनाव आयोग भेजा, इसे चुनाव आयोग ने भी बिना किसी विलंब के अपनी स्वीकृति दे दी और सचिन को भारत रत्न देने का रास्ता साफ कर दिया.

इस विवाद ने इस वजह से तूल पकड़ा, क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत खेल मंत्रालय का लिखा एक पीएमओ का एक दस्तावेज सामने आया है कि खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद नाम की अनुशंसा की थी न कि सचिन तेंदुलकर के नाम की. आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को मिली सूचनाओं से यह भी मालूम होता है कि खेल मंत्रालय द्वारा की गई अन्य अनुशंसाओं को भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने नज़रअंदाज कर दिया. जिसमें उड़नपरी पीटी ऊषा और शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम भी शामिल थे. इस पुरस्कार के लिए की जाने वाली अनुशंसाएं पूरी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय पर निर्भर होती हैं. अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के साथ सुझाव के लिए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं. इसके बाद जिन नामों पर राष्ट्रपति सहमत होते हैं उन नामों की सूची राष्ट्रपति सचिवालय जारी करता है.

खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई,2013 को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ध्यानचंद के नाम पर भारत रत्न पुरस्कार के लिए उनके भारत में खेलों में उनके योगदान के लिए विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने देश को तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान दिया. स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद मरणोपरांत भारत रत्न पाने के सबसे काबिल उम्मीदवार हैं. उन्होंने खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया है जिससे देश गौरान्वित हुआ है. उनके चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है. जिस दौर में वह हॉकी खेला करते थे वह भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर था. वह न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी थे बल्कि वह टीम के एक बेहतरीन सदस्य भी थे. हॉकी के मैदान में अपने बेहतरीन खेल की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला. वे बेहद सामान्य, विनम्र और निःस्वार्थ व्यक्ति थे. उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए देश का एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ी के रुप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और संन्यास के बाद भी खेलों से जुड़े रहे, इसके अलावा उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है. प्रधानमंत्री खेल मंत्री जितेंद्र सिंह के पत्र से बहुत खुश हुए और पत्र को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया. दुर्भाग्यवश वह पत्र नौकरशाहों के बीच कहीं खो गया. इसके एक महीने बाद अगस्त 2013 में प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्कालीन निदेशक राजीव टोपनो ने कहा कि इस मसले(ध्यानचंद) को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के समक्ष दिसंबर में पद्म पुरस्कारों की सूची को अंतिम रुप देते वक्त रखा जाएगा. लेकिन इसके बाद इस मसले पर एक बार फिर से खामोशी छा गई. 14 नवंबर 2014 को राजीव टोपनो ने खेल मंत्रालय से सचिन तेंदुलकर का प्रोफाइल तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का अनुरोध किया. जिसे कि राष्ट्रपति को भारत रत्न के लिए भेजे जाने वाले पत्र के साथ संलग्न किया जाना था. संयोगवश सचिन तेंदुलकर उसी दिन अपने करियर का आखिरी टेस्ट मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे. इसके बाद 16 नवंबर को सचिन तेंदुलकर और सीएनआर राव को भारत रत्न दिए जाने का अंतिम निर्णय हो गया. इस पूरे वाकये में यह बात साफ नहीं हुई कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति ने भारत रत्न की घोषणा करने से पहले ध्यानचंद के नाम की चर्चा की या नहीं. लेकिन इससे एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि खेल मंत्रालय भी मानता है कि ध्यानचंद सचिन से पहले भारत रत्न पाने के हकदार थे. इसी वजह से खेल मंत्रालय ने कार्यवाही के लिए पत्र भेजने के बाद भी उस पर अमल नहीं होता है, तो इसे पूरी तरह राजनीति ही कहा जाएगा. तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव ने अक्टूबर 2013 में आंतरिक पत्र व्यवहार में लिखा कि पीए सहमत हैं अब टीएसटी से राइट अप मंगाया जाए, मुख्यचुनाव आयुक्त से अनापत्ति ली जाए और इसके बाद पीएम की तरफ से औपचारिक संस्तुति भेजी जाए. लेकिन यहां इस बात को लेकर सवाल उठता है कि सचिन तेंदुलकर को किसके दबाव में देश का सर्वोच्च सम्मान इतनी जल्दबाजी में दिया गया और इसके लिए ध्यानचंद के नाम को क्यों दरकिनार किया गया. इस मसले पर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार का इस मसले पर कहना है कि इसे लेकर राजनीति हो रही है. यह उन हजारों लाखों लोगों के लिए निराशाजनक है कि सचिन तेंदुलकर को ध्यानचंद पर वरीयता दी गई. यह मेजर ध्यानचंद के खिलाफ खेला गया एक राजनीतिक खेल है. जिस तरह हाल ही में संपन्न हुए फीफा विश्वकप में मेसी को गोल्डन बॉल खिताब देने को लेकर हमवतन मैराडोना ने आपत्ति दर्ज की थी कि मेसी को गोल्डन बॉल दिया जाना मार्केटिंग का निर्णय है, शायद ऐसा ही कुछ सचिन को भारत रत्न देने में भी हुआ, यहां बाजार के फायदे के साथ–साथ राजनीतिक फायदे भी देखे गए. सरकार चाहती तो सचिन के साथ ध्यानचंद को भी भारतरत्न दे सकती थी, लेकिन देश के बड़े–बड़े नेता क्रिकेट बोर्ड में किसी ने किसी पद पर रहे हैं या रह चुके हैं, उन्हें क्रिकेट के अलावा और किसी खेल की चिंता नहीं है. संसद में बैठे लोग सिर्फ हॉकी को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, हॉकी की खैर खबर लेने वाला कोई भी सदन में मौजूद नहीं है, इसी वजह से यह विवाद हो रहा है और सचिन के नाम को बेवजह घसीटा जा रहा है और ध्यानचंद को दरकिनार किया जा रहा है.

> स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद मरणोपरांत भारत रत्न पाने के सबसे काबिल उम्मीदवार हैं. उन्होंने खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया है जिससे देश गौरान्वित हुआ है. उनके चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है. जिस दौर में वह हॉकी खेला करते थे वह भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर था. वह न कवल एक बेहतरीन खिलाड़ी थे बल्कि वह टीम के एक बेहतरीन सदस्य भी थे. हॉकी के मैदान में अपने बेहतरीन खेल की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला.

ध्यानचंद

ध्यानचंद का देश के लिए योगदान अविस्मरणीय है. सचिन को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी पिछले कुछ समय से चल रही थी. ऐसा नहीं है कि सचिन को भारत रत्न देने से उनका कद छोटा या बड़ा हो गया है. यहां सवाल यह है कि भारत रत्न पाने का सबसे पहला हकदार कौन था सचिन या ध्यानचंद? आज नहीं कल इस विवाद के बाद ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाएगा, लेकिन यह विवाद उसी तरह का है कि राजीव गांधी को सरदार पटेल से पहले भारत रत्न दे दिया गया. दोनों ही खिलाड़ी महान हैं दोनों ने अलग–अलग दौर में अलग–अलग खेलों का प्रतिनिधित्व किया, दोनों ने ही देश कौ गौरव के कई मौके दिए और देश का सम्मान बढ़ाया. बावजूद इसके ध्यानचंद का कद सचिन से कहीं ज्यादा बड़ा है, ऐसे में उनके नाम को नज़रअंदाज किया जाना दुःखद है. सरकार को पुरस्कारों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.■

navinonline2003@gmail.com

यूपीए सरकार ने ध्यानचंद के नाम को नज़रअंदाज कर दिया और अप्रत्याशित रुप से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया. इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ध्यानचंद को दरकिनार कर दिया, जब सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान दिया जा रहा था तो कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि भारत रत्न पाने के लिए सचिन तेंदुलकर से पहले यह सम्मान ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए था, ध्यानचंद के नाम पर आम सहमति बनने के बाद अचानक से सचिन का नाम आगे आना और उन्हें भारत रत्न दिया जाना बड़ा ही नाटकीय दिखाई पड़ता है. यह फैसला भी तब किया गया जब सामान्य रूप से पुरस्कारों की घोषणा नहीं की जाती है, पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था. खेल मंत्रालय के पत्र पर प्रधानमंत्री का सहमत होना और आग्रिम

डैनी और ऋतिक आमने-सामने

डैनी और ऋतिक रोशन फिल्म बैंग बैंग में आमने-सामने नज़र आएंगे. ऐसा 28 साल बाद होगा. इससे पहले दोनों ने फिल्म भगवान दादा में एक साथ काम किया था. यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी. तब ऋतिक बाल कलाकार के रूप में नज़र आए थे. ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन भी थे. भगवान दादा के एक दृश्य में ऋतिक को अगवा करके शंभु दादा यानी डैनी के सामने लाया जाता है. ऋतिक गुस्से में भगवान दादा को पैर उठाकर मारने की कोशिश करते हैं. क़रीब 28 साल बाद कुछ उसी अंदाज में ऋतिक फिल्म बैंग बैंग में उन्हें मारते दिखाई देंगे. यह फिल्म दो अक्टूबर को रिलीज होगी. इसमें ऋतिक के अपोजिट कैटरीना कैफ हैं. फिल्म का ट्रेलर लांच हो चुका है और लोकप्रिय हो रहा है.■

सलमान संग रोमांस करेंगी नरगिस

वर्ष 2011 में प्रदर्शित फिल्म रॉक स्टार से अपना करियर शुरू करने वाली नरगिस फाखरी अभिनेता सलमान के साथ रोमांस करना चाहती हैं. नरगिस ने सलमान खान की हालिया प्रदर्शित फिल्म में आइटम नंबर किया है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हैं और बतौर अभिनेत्री सलमान के साथ काम करना चाहती हैं. बक़ौल नरगिस, अगर मुझे तीनों ख़ानों में से किसी एक के साथ काम करने का मौक़ा मिलता है, तो मैं सलमान के साथ काम करना पसंद करूंगी, वह बहुत प्रतिभाशाली हैं. हालांकि मुझे फिल्म किक में सलमान के साथ डांस करने का मौक़ा मिला, लेकिन यह काफी नहीं है. ■

रणवीर के साथ आलिया

जवां दिलों की धड़कन रणवीर कपूर और आलिया भट्ट बहुत शीघ्र एक साथ नज़र आने वाले हैं. इस बात की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि करण जौहर एक ट्वीट के जरिये की है. उन्होंने बताया कि अयान मुखर्जी और धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म अगले साल के मध्य शुरू होने वाली है, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होगी. इसी फिल्म में रणवीर और आलिया साथ नज़र आएंगे. अयान मुखर्जी इससे पहले करण जौहर की रणवीर कपूर स्टारर फिल्म ये जवानी है दीवानी निर्देशित कर चुके हैं. वह रणवीर के अच्छ दोस्त हैं और उनके साथ वेकअप जैसी सफल फिल्म भी बना चुके हैं. अब देखना यह है कि पहली बार एक साथ आ रहे रणवीर-आलिया की यह फिल्म क्या धमाल मचाती है. उधर करण जौहर अपनी फिल्म शुद्धि में व्यस्त हैं. फिल्म शुद्धि में कौन हीरो होगा, इसे लेकर भी काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसमें सलमान खान होंगे.■

बिग बॉस में सलमान!

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान एक बार फिर कलर्स पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस होस्ट करते नज़र आएंगे. हालांकि सीजन सात के दौरान उन्होंने कहा था कि संभवत: वह इसका अगला सीजन होस्ट नहीं करेंगे. शाहरुख खान से भी बिग बॉस का आगामी सीजन होस्ट कराने की चर्चा हो रही थी, लेकिन निर्माता ने सलमान को एक बार फिर शो होस्ट करने के लिए राजी कर लिया है, लेकिन इस बार सलमान हर सप्ताह 6 करोड़ रुपये लेंगे, जबकि पिछले सीजन में यह रकम 3 करोड़ रुपये थी. बिग बॉस को अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी एवं अरशद वारसी भी होस्ट कर चुके हैं. सलमान इसे लगातार तीसरी बार होस्ट करेंगे. ■

कुमार विश्वास की नई पारी

राहुल गांधी के ख़िलाफ़ अमेठी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की जमानत भले ही जब्त हो गई, लेकिन इससे उनका बॉलीवुड करियर शुरू होता दिखाई दे रहा है. ख़बर है कि रियलिटी शो बिग बॉस की निर्माता कंपनी एंडमॉल ने कुमार विश्वास से शो का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया है और उसकी एवज में पांच करोड़ रुपये की पेशकश की है. बिग बॉस का आठवां सीजन सितंबर में शुरू होना है. विश्वास ने भी एंडमॉल द्वारा उनसे संपर्क करने की बात स्वीकारी है, लेकिन इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दी. हालांकि सूत्र कहते हैं कि उन्होंने बिग बॉस के लिए हामी भर दी है. फिलहाल वह अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया में गूगल के कर्मचारियों को संबोधित करना है. उनके एक गीत को आवाज़ देने के लिए आशा भोसले तैयार हो गई हैं.■

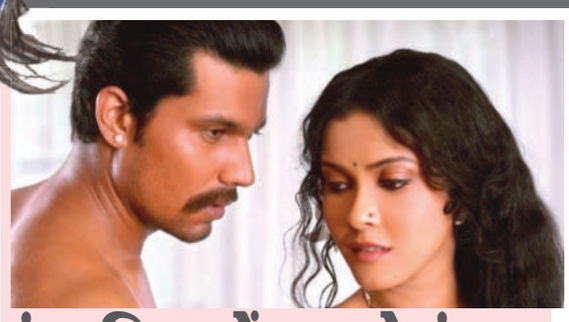

रंगरसिया में प्यार के रंग

केतन मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म रंगरसिया छह साल के इंतज़ार के बाद अब रिलीज होगी. 2008 में बनकर तैयार हो चुकी इस फिल्म के ट्रेलर पर विवाद हो गया था, सो इसे रोक लिया गया था, लेकिन यह इस बार दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. अपने संजीदा अभिनय के लिए मशहूर रणदीप हुड्डा इस फिल्म की मुख्य भूमिका में हैं और उनके अपोजिट नंदना सेन. 2011 में भी रंगरसिया को रिलीज करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी. यह फिल्म 19वीं सदी के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा एवं उनकी प्रेमिका सुगंधा के जीवन पर आधारित है और इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल गाडा हैं. रंगरसिया शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के साथ रिलीज होगी. हालांकि प्रोड्यूसर गाडा कहते हैं कि शाहरुख बड़े सितारे हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा एंगल है, जिसकी वजह से हमने इसे दीवाली पर रिलीज करने का फ़ैसला लिया. रणदीप हुड्डा के प्रशंसकों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि फिल्म रंगरसिया में उन्हें लव एंगल देखने को मिलेगा. ■

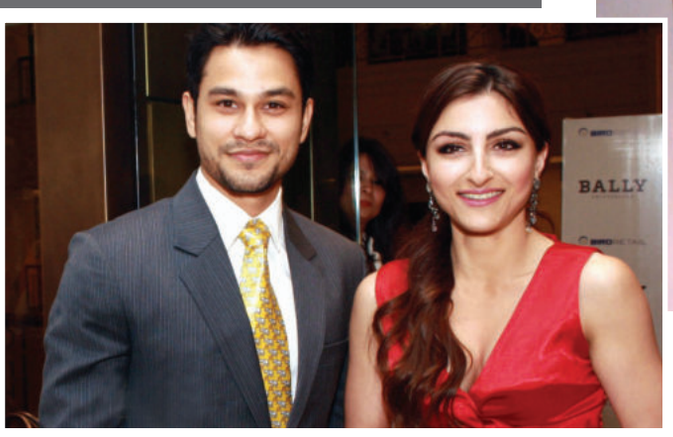

सोहा और कुणाल की सगाई

शर्मिला टैगोर की बेटी और नवाब सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने हाल में पेरिस में अभिनेता कुणाल खेमू के साथ सगाई कर ली. दोनों के बीच पिछले काफी समय से रोमांस चल रहा था. दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया. सोहा ने अपने एक ट्वीट में कहा, आपके साथ यह साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कुणाल ने पेरिस में दुनिया की सबसे नायाब अंगूठी के साथ मुझे प्रपोज किया और मैंने हां कह दिया. शर्मिला और सैफ भी दोनों के संबंधों को लेकर राजी थे. फिल्म कलयुग के स्टार कुणाल खेमू के पिता रवि खेमू ने अपने साक्षात्कार में कहा था कि जब भी दोनों शादी करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद उनके साथ होगा. दोनों ने फिल्म 2009 में आई फिल्म 99 में साथ काम किया था.■

खूबसूरत के रीमेक में सोनम

अभिनेत्री सोनम कपूर इस साल अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म खूबसूरत के रीमेक में नज़र आएंगी. यह उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म है, जिसे उनकी बहन रिया कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं. यह सोनम की पहली रीमेक फिल्म है. हृषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म खूबसूरत में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके अपोजिट थे राकेश रोशन. रेखा ने तब बबली गर्ल के रूप में जबरदस्त ख्याति हासिल की थी. इस बार राकेश रोशन का किरदार फवाद खान निभा रहे हैं और सोनम के कैरेक्टर का नाम है मिली. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

11 अगस्त–17 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

पेज 20

दोस्ती में बहुत कुछ लगा है दांव पर

बिहार में राजनीति का यह अनूठा प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती काफी कठिन होने वाली है लेकिन अगर यह प्रयोग किसी कारण से फेल हो गया तो फिर नए दोस्तों व उनके दलों में ऐसा संकट आएगा जिसे झेलने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. यह बात सभी जानते है कि लालू प्रसाद व नीतीश कुमार ने जो हाथ मिलाया है यह इन दोनों नेताओं का व्यक्तिगत फैसला है. इस फैसले तक पहुंचने में इन नेताओं ने काफी कम लोगों को अपना हमसफर बनाया. इस्लामपुर के जदयू विधायक राजीव रंजन कहते हैं कि यह एक ऐसा आत्मघाती कदम है जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने लिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई.

सरोज सिंह

लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार से सबक लेते हुए बिहार के दो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सूबे की राजनीति के सारे समीकरणों को बदल कर रख दिया है. कहा जाए तो इन दोनों नेताओं ने एक ऐसे प्रयोग का मन बनाया है जिसकी अब तक कल्पना तक नहीं की जा सकती है लेकिन पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है और बिहार में ठीक यही हुआ है. लगभग दो दशक तक लालू प्रसाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नीतीश कुमार अब यह कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ राजनीति करने वाले सभी हमारे दोस्त हैं. अभी हाल तक यानि की लोकसभा चुनाव तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक दूसरे को पानी पी पीकर कोस रहे थे लेकिन अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया. भले ही इन नेताओं का मिलन विचित्र लगे मगर सत्य यह है कि उपचुनाव की दस सीटों पर कांग्रेस, राजद और जदयू मिलकर भाजपा और उनके सहयोगियों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पहली नजर में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस की दोस्ती बहुत ही प्रभावी लगती है. लेकिन जैसे ही जमीन की राजनीति का विश्लेषण शुरू होता है तो यह बात सामने आने लगती है कि इस दोस्ती पर इन नेताओं और दलों का बहुत कुछ दांव पर लग गया है. बिहार में राजनीति का यह अनूठा प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती काफी कठिन होने वाली है लेकिन अगर यह प्रयोग किसी कारण से फेल हो गया तो फिर नए दोस्तों व उनके दलों में ऐसा संकट आएगा जिसे झेलने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. यह बात सभी जानते है कि लालू प्रसाद व नीतीश कुमार ने जो हाथ मिलाया है यह इन दोनों नेताओं का व्यक्तिगत फैसला है. इस फैसले तक पहुंचने में इन नेताओं ने काफी कम लोगों को अपना हमसफर बनाया. इस्लामपुर के जदयू विधायक राजीव रंजन कहते हैं कि यह एक ऐसा आत्मघाती कदम है जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने लिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई. कार्यसमिति की बैठक में तो बस इस फैसले पर मुहर लगाई गई. राजीव रंजन कहते हैं कि 114 में से 65 विधायक इस गठबंधन के खिलाफ हैं और 25 तारीख को जैसे ही नतीजा निकलेगा हमलोग पार्टी को टेकओवर कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि नतीजे हमारे खिलाफ आने वाले हैं. हालांकि राजीव रंजन कहते हैं कि मांझी सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी. राजकुमार सिंह और उपेंद्र चौहान जैसे नेता तो रिजल्ट आने तक का इंतजार करने को तैयार नहीं हैं. ये लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अपना आशियाना बनाने वाले हैं. बताया जा रहा है कि अगर उपचुनाव के नतीजे जदयू के पक्ष में नहीं आए तो विधायकों का एक बहुत बड़ा तबका नीतीश कुमार के विरोध में खुलकर सामने आ सकता है. वैसे भी लालू प्रसाद से गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार सबके निशाने पर आ गए हैं. पार्टी के अंदर भी उनकी ताकत कम हुई है. इसकी झलक टिकट बंटवारे में ही साफ दिख गई. नीतीश कुमार के लाख चाहने के बावजूद हाजीपुर से मोतीलाल कानन को टिकट नहीं मिल पाया. सूत्र बताते हैं कि तालमेल में यह सीट कानन के लिए ही ली गई थी. राजद यहां से दूसरे नंबर पर रहा था इसलिए स्वाभाविक था कि यह सीट जदयू को मिलती लेकिन नीतीश कुमार ने यह सीट ले तो ली पर कानन को टिकट नहीं दिला पाए. बताया जा रहा है कि शरद यादव व लालू यादव ने राजेंद्र राय के लिए वीटो कर दिया. नतीजा यह हुआ कि मोतीलाल कानन को तो टिकट नहीं ही मिला और देवकुमार चौरसिया ने निर्दलीय मैदान में उतर कर जदयू को औकात बताने का ऐलान कर दिया. इसी तरह नीतीश कुमार ने लाख चाहकर भी रश्मि वर्मा को निराश कर दिया.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

नेताजी कहिन

उपचुनाव में सांप्रदायिक ताकतों का सफाया हो जाएगा. भाजपा ने जो भ्रमजाल फैला कर रखा हुआ है उसका अंत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इस उपचुनाव में कर देंगे. लोकसभा चुनाव भाजपा ने छल से जीता है पर अब बिहार की महान जनता इस छल को समझ चुकी है और हमारा नया गठबंधन दस में दस सीटों पर कब्जा जमाएगा.

छोटू सिंह –जदयू नेता

उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दिल दिखाया है. हमारा गठबंधन अटूट है और हम सभी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन जदयू, कांग्रेस और राजद की दोस्ती स्वार्थ और धोखे की नींव पर खड़ी हुई है, इसलिए इस इमारत का गिरना तय है. उपचुनाव में एनडीए गठबंधन सभी दस सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है.

अमरेंद्र सिंह – रालोसपा नेता

नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यूं गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं. यह ट्रेन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी. लोजपा, भाजपा और रालोसपा का गठबंधन पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगा और अपने विरोधियों को परास्त कर देगा.

ललन चंद्रवंशी – लोजपा नेता

महागठबंधन से भाजपा की बोलती बंद हो गई है. पिछड़ों व अतिपछिड़ों की संयुक्त ताकत का एहसास इस उपचुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को हो जाएगा. उनकी पोल खुल चुकी है और हमारा गठबंधन उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहा है.

प्रगति मेहता –राजद नेता

राजद-जदयू-कांग्रेस का गठबंधन हारी हुई ताकतों का जमावड़ा है और हारे हुए घोड़ों पर कोई भी हाशियार आदमी दांव नहीं लगाता है. बिहार की जनता कितनी होशियार है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है. इसलिए तय मानिए भाजपा गठबंधन दस में से दस सीट जीतने जा रहा है.

– संजय मयूख भाजपा नेता

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

ब्लैक कॉटेज की लॉन्चिंग

पटना–मैगपाई फैशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कंपनी के नए ब्राण्ड ब्लैक कॉटेज की लॉन्चिंग की गई. इसे बाजार के फैशन ट्रेंड मे बदलाव को देखते हुए तैयार किया गया है. नए ब्राण्ड में विभिन्न परिधानों में कई विकल्प दिए गए हैं, इसमें कैजुअल और फॉरमल दोनों प्रकार के ड्रेसेज मौजूद हैं. इस ब्राण्ड को बिहार में पहली बार लॉन्च किया गया है, जो विषेशकर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस मौके पर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुशील जाशी ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल फैशन के आधुनिक ट्रेंड को फॉलो करना ही नहीं बल्कि नए ट्रेंड भी स्थापित करना है. साथ ही ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत उनका लक्ष्य पहले वर्ष ब्लैक कॉटेज के 100 स्टोर और वर्ष 2015 के अंत तक 250 का है. इस मौके पर एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया. *– चित्रा भारती*

दो दिवसीय प्रषिक्षण का आयोजन

शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के सोनौल मध्य विद्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों का दो दिवसीय क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. सेंटर फॉर वर्ल्ड सेलिब्रेटी के सहयोग से गांव विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण का उद्घाटन बीडीओ राकेश रौशन, पूर्व जिला पार्षद अजबलाल चौधरी व संस्था के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया. मौके पर रेखा देवी, अल्हा सिंह, भाग्यनारायण सिंह, शंकर दुबे, मनोरमा देवी, नीलम कुमारी समेत अन्य थे. धन्यवाद ज्ञापन फील्ड मॉनीटर वीरेंद्र कुमार ने किया. *– देवेंद्र*

प्रशासन से परेशान जनता

पूर्व मंत्री व राकांपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवल किशोर शाही ने कहा कि सीतामढ़ी जिले की जनता प्रशासन से परेशान है. परिसदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि जरूरतमंदो को राशन कार्ड से वंचित रखा गया है. डीएम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे घर बैठे ही प्रशासन चलाती हैं. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के नाम पर कई बार मुसहरों के नाम से राशि की निकासी की गई परंतु अब तक घर का निर्माण नहीं कराया जा सका है. मिड–डे मिल, वृद्धापेंशन, आंगनबाडी, मनरेगा समेत अन्य योजनाएं नकारा बनी है. उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जबकि डीलर करोड़पति बन रहे हैं. मौके पर यमुना प्रसाद सिंह, प्रो. सुरेश प्रसाद सिंह, सरोज कुमार सिंह व महेंद्र झा समेत अन्य थे. *– ब्रजेश*

अमित बने युवा रालोसपा के जिलाध्यक्ष

युवा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने पार्टी के सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष के रूप में अमित सहाय को मनोनीत किया है. साथ ही जिला कमिटी का संगठन विस्तार करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत/वार्ड अध्यक्षों की सूचि राज्य कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है. अमित के मनोनयन पर सांसद राम कुमार षर्मा, जिलाध्यक्ष राम लक्षण सिंह कुशवाहा, जिला संगठन प्रभारी मोहन कुमार सिंह, राम प्रवेश यादव समेत अन्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है.■ *–विम्मी*

दोस्ती में बहुत कुछ लगा है दांव पर

पृष्ठ 17 का शेष

कांग्रेस की जिद के आगे नीतीश कुमार की एक न चली और घोषणा होने के बावजूद यह सीट एक फिर कांग्रेस के खाते में चली गई. नतीजा यह हुआ कि रश्मि वर्मा ने भाजपा का दामन थामा और नरकटियागंज से मैदान में कूद पड़ीं. जदयू के लोग लालू प्रसाद के साथ बराबरी के समझौते को लेकर भी नाराज हैं. पार्टी के इस फैसले से गुस्साए लोगों का कहना है कि राजेंद्र राय तो नाम के जदयू में हैं असल में वह लालू प्रसाद के ही नुमाइंदे हैं. इस तरह लालू ने दस में से पांच सीटों पर अपना दावा बना लिया. दूसरी तरफ भाजपा विरोध के नाम पर जंगल राज को भूल जाने वाली कहानी भी जदयू के वोटरों और समर्थकों को नहीं पच रही है क्योंकि बीस सालों से ये लोग लालू प्रसाद का विरोध करते आ रहे हैं और अचानक उनका गुणगान करने में वे असहज महसूस कर रहे हैं.

अब इस दुविधा की स्थिति में वे कितनी मजबूती के साथ उपचुनाव की जंग में उतरेंगे यह कहना मुश्किल है. जानकार बताते हैं कि यह दोस्ती लालू प्रसाद व नीतीश कुमार के लिए जीवन–मरण जैसे हालात पैदा करने वाली है. अगर नतीजे पक्ष में आए तो निश्चित तौर पर ये दोनों नेता अपने दल में मजबूत होंगे और नई ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे. इस जीत से इनको अपने दल के विरोधियों को खामोश करने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वह अन्य दलों को साथ मिलाकर यह प्रयोग देश भर में करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे. लेकिन अगर दोस्ती का दांव उलटा पड़ गया तो फिर मुसीबतों की लंबी लिस्ट इन नेताओं के सामने आकर खड़ी हो जाएगी. खासकर जदयू में तो बवाल तेज होना तय है. नीतीश के विरोधियों को यह कहने का और मौका मिल जाएगा कि आपका यह कदम आत्मघाती साबित हुआ. नई परिस्थति में जदयू के वैसे भी विधायक व नेता खुलकर नीतीश का विरोध कर सकते हैं जो अभी हां व ना की दहलीज पर खड़े हैं.

चूंकि विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं इसलिए उन्हें हर हाल में एक रास्ता चुनना ही होगा. नीतीश समर्थकों को यही डर सता भी रहा है. इसलिए न चाहते हुए भी नीतीश कुमार ने सीट व टिकट के बंटवारे पर अपने स्वभाव के विपरीत बहुत ही लचीला नजरिया अख्तियार किया. नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यह उनका अंतिम प्रयोग है और उन्हें हर हाल में इस प्रयोग को सफल करना ही होगा वरना फिर उनके लिए विकल्प बहुत ही कम रह जाएंगे. इसलिए नीतीश कुमार खुद पहल करते हुए गठबंधन के रोड़े को दूर करते रहे और अब उपचुनाव में जीत के लिए अपने सारे तर्जुबे और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक छोटू सिंह कहते हैं कि उपचुनाव में सांप्रदायिक ताकतों का सफाया हो जाएगा. भाजपा ने जो भ्रमजाल फैला कर रखा हुआ है, उसका अंत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इस उपचुनाव में कर देंगे और भाजपा और उसके सहयोगी पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे. लोकसभा चुनाव भाजपा ने छल से जीता है पर अब बिहार की महान जनता इस छल को समझ चुकी है और हमारा नया गठबंधन दस में दस सीटों पर कब्जा जमाएगा. इसी तरह राजद के मीडिया प्रभारी प्रगति मेहता कहते हैं कि महागठबंधन से भाजपा की बोलती बंद हो गई है. पिछड़ों व अतिपछिड़ों की संयुक्त ताकत का एहसास इस उपचुनाव में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टी को हो जाएगा. उनकी पोल खुल चुकी है और हमारा गठबंधन उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहा है.

लेकिन दूसरी तरफ लोजपा नेता ललन चंद्रवंशी कहते हैं कि नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यूं गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं. यह ट्रेन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी. लोजपा भाजपा और रालोसपा का गठबंधन पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगा और अपने विरोधियों को परास्त कर देगा. इसी तरह भाजपा के एमएलसी संजय मयूख कहते हैं कि महागठबंधन हारी हुई ताकतों का जमावड़ा है और हारे हुए घोड़े पर कोई भी होशियार आदमी दांव नहीं लगाता है. बिहार की जनता कितनी होशियार है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है. इसलिए तय मानिए भाजपा गठबंधन दस में से दस सीट जीतने जा रही है. इन दावों और प्रतिदावों के इतर जो सच्चाई है वह यह है कि यह उपचुनाव नीतीश और लालू के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. हालात ऐसे हैं कि इन दोनों को इस परीक्षा में पास करना ही होगा और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो फिर बस राख ही राख बच जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

पाया कुछ नहीं, गंवाया बहुत कुछ

उद्घाटन भाषण में सांसद भोला सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की. लेकिन इसी बीच वे लीक से हटकर आपबीती सुनाने लगे. अपने भाषण के क्रम में सांसद ने यह रहस्योद्घाटन किया कि जब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी तो पार्टी के कई पुराने स्थानीय नेता इसे पचा नहीं पाए और उनके (नेताओं के) पेट में दर्द होने लगा. सांसद का यह वाक्य मंचासीन पार्टी के कुछ वरीय नेताओं को नागवार गुजरा क्योंकि सांसद का परोक्ष इशारा उन्हीं वरीय नेताओं की ओर था. सांसद भोला सिंह के भाषण के दौरान खोदाबंदपुर मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह, बेगूसराय उत्तर मंडल अध्यक्ष सुनिल कुमार मुन्ना, बरौनी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष फुलेना सिंह, मटिहानी मंडल अध्यक्ष सीताराम सिंह सहित अन्य ने खड़ा होकर जोरदार शब्दों में अनेक बार लोक सभा चुनाव की समीक्षा करने की पुरजोर मांग उठाई.

सुरेश चौहान

बेगूसराय जिले में लंबे समय के बाद हुई भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई दिए. बैठक के दौरान शोर–शराबे के कारण भाजपा में अंतर्कलह उजागर हो गई. मंडल अध्यक्षों की मांगों को सांसद एवं जिला अध्यक्ष ने पूरी तरह अनसुना कर दिया. सदस्यों की मांग से ऊबकर जिलाध्यक्ष कुछ समय के लिए बैठक से बाहर चले गए. सांसद ने भी मंच से किनारा कर लिया. वहीं बैठक के दौरान गुरुदक्षिणा कार्यक्रम भी रखा गया जिसे सदस्यों ने जिलाध्यक्ष की नासमझी करार दिया.

लगभग दो वर्ष के कार्यकाल में भाजपा जिला कार्यसमिति की यह दूसरी बैठक थी. एमआरजेडी इंटर कॉलेज, विष्णुपुर में आयोजित बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों से अधिक संख्या भाजपा कार्यकर्ताओं की थी. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में यह बैठक अहम थी. बैठक में गत लोकसभा चुनाव की समीक्षा, सदस्यता अभियान, जन समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाने एवं आगामी विधान सभा चुनाव के संबंध में चर्चा कर रूपरेखा तय करना था. लेकिन बैठक की शुरुआत ही सही नहीं हुई. कार्य समिति की पिछली बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत नहीं की गई. उद्घाटन भाषण में सांसद भोला सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की. लेकिन इसी बीच वे लीक से हटकर आपबीती सुनाने लगे. अपने भाषण के क्रम में सांसद ने यह रहस्योद्घाटन किया कि जब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी तो पार्टी के कई पुराने स्थानीय नेता इसे पचा नहीं पाए और उनके (नेताओं के) पेट में दर्द होने लगा. सांसद का यह वाक्य मंचासीन पार्टी के कुछ वरीय नेताओं को नागवार गुजरा क्योंकि सांसद का परोक्ष इशारा उन्हीं वरीय नेताओं की ओर था. सांसद भोला सिंह के भाषण के दौरान खोदाबंदपुर मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह, बेगूसराय उत्तर मंडल अध्यक्ष सुनिल कुमार मुन्ना, बरौनी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष फुलेना सिंह, मटिहानी मंडल अध्यक्ष सीताराम सिंह सहित अन्य ने खड़ा होकर जोरदार शब्दों में अनेक बार लोक सभा चुनाव की समीक्षा करने की पुरजोर मांग उठाई. लेकिन सांसद एवं अध्यक्ष द्वारा बार–बार इसे टाल दिया गया. सांसद मंच से उतरने के लिए पग बढ़ा चुके थे लेकिन समिति सदस्यों की जोरदार मांग पर उन्होंने पुन: माइक थामकर कहा कि वे भी समिति के सदस्यों का मांग का समर्थन करते हैं. लोकसभा चुनाव की समीक्षा उनके सामने हो. इस समीक्षा में वे भी उपस्थित रहना चाहते हैं. इसके लिए शनिवार/रविवार या फिर लोकसभा सत्र की समाप्ति के बाद किसी भी दिन निर्धारित की जा सकती है.

दूसरी ओर बैठक में तेघड़ा विधायक ललन कुंवर समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद सिंह, कुंदन कुमार, वंदना देवी आदि के उपस्थित नहीं रहने पर तरह–तरह की चर्चा भाजपाइयों में होती रही. भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला कार्यसमिति की बैठक में काफी विलंब से पहुंचे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संगठन प्रभारी मिथिलेश तिवारी ने आगे के कार्यक्रमों की जानकरी दी. बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह, महेश्वर सिंह बाबा, राधाकृष्ण प्रसाद सिन्हा, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी संजय कुमार, ललन प्रसाद सिंह, डॉ. सुरेश प्रसाद राय, जिला महासचिव कृष्ण मोहन पप्पू, सुधीर कुमार राय मुन्ना, जयराम दास, विश्वनाथ सिंह, आशुतोष पोद्दार हीरा सहित पार्टी के विभिन्न विंग के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे.

भाजपा कार्यसमिति की बैठक में परंपरा से हटकर आरएसएस के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो चर्चा का विषय बना रहा. पार्टी की अल्पसंख्यक सेल सहित अनेक भाजपाईयों ने इस कार्यक्रम की आलोचना की. पार्टी के एक वरीय महासचिव सहित अन्य भाजपाईयों ने इस आयोजन को जिला अध्यक्ष संजय कुमर की नासमझी बताया. दूसरी ओर कुछ वरीय सदस्यों ने कार्यसमिति की बैठक पार्टी संविधान द्वारा निर्धारित अंतराल पर नहीं बुलाए जाने को अध्यक्ष के तानाशाही रवैये का परिणाम करार दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध विश्वविद्यालय ने एनसीटीई पर खड़ा किया सवाल

सुनील सौरभ

बीएड कॉलेजों को मान्यता देने वाली भारत सरकार की संस्था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) पर मगध विश्वविद्यालय ने सवाल खड़ा कर दिया है. बीएड कॉलेजों में नामांकित छात्रों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालयों की होती है. बस यहीं विश्वविद्यालय की ओर से निजी बीएड कॉलेजों का दोहन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा बार–बार निजी बीएड कॉलेजों को तंग किए जाने से आहत संबद्ध बीएड कॉलेजों ने अपने को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखने का मन बना लिया है. मगध विश्वविद्यालय में जब भी कोई नया अधिकारी आता है नए सिरे संबद्ध बीएड कॉलेजों को परेशान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है.

अभी हाल में मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ. कृतेश्वर प्रसाद ने निजी बीएड कॉलेजों पर शिकंजा कसने का तथा कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट नहीं लेने का बयान देकर, उन्हें हड़काने का प्रयास किया है. इस बयान में मगध विश्वविद्यालय ने बी.एड. कॉलेजों को मान्यता देने वाली एनसीटीई पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि एनसीटीई अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त भूमि पर बने भवन और सारे संसाधनो के उपलब्ध होने के बाद ही बीएड कॉलेजों को मान्यता प्राप्त होती है. इसके बाद ही संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए मान्यता प्रदान की जाती है. बीएड के लिए कॉमन एन्ट्रेन्स टेस्ट कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय की है. इसके लिए संबद्ध बीएड कॉलेज अनेक बार मांग कर चुके हैं लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है. इसलिए बीएड कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेकर निष्पक्ष रूप से विद्यार्थियों का नामांकन करते है. इसी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाकर अक्सर कॉलेजों को परेशान किया जाता है.

आक्रोशित मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 60 निजी बीएड कॉलेजों में से कई संचालकों ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तथा कुलाधिपति व राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है. कई बीएड कॉलेज के संचालको ने बताया की राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन निजी बीएड कॉलेजों के शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चों को जोड़ कर प्रति छात्र नामांकन राशि लेने के लिए निर्धारित कर दें तथा कॉमन एन्ट्रेन्स टेस्ट लेने का मानदंड निर्धारित कर दें. हमलोग इसी आदेश का पालन करेंगे. मगध विश्वविद्यालय द्वारा सैकड़ों डिग्री कॉलेजों की मान्यता दी गई है, जिनमें एक कमरे बोर्ड लगाकर कक्षाएं चल रही हैं. अभी हाल में मगध विश्वविद्यालय की ओर से राज्य सरकार के आदेश पर ऐसे कॉलेजों की जांच कराई गई थी. लेकिन इन कॉलेजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी. क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इन कॉलेजों के संचालक किस तरह के है और मगध विश्वविद्यालय के कर्मियों तथा पदाधिकारियों से उनके कैसे संबंध है. हर तीन साल पर विश्वविद्यालय के तीन शीर्ष पदाधिकारियों का पदस्थापन राज्य सरकार की सलाह से राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा किया जाता है. जब जब नए पदाधिकारियों का आगमन होता है, तब तब मगध विश्वविद्यालय के संबद्ध डिग्री तथा निजी बीएड कॉलेजों को विभिन्न तरह के फरमानों का पालन करना मजबूरी बन जाता है. निजी बीएड कॉलेजों से मगध विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क समेत अन्य तरह के शुल्कों से करोड़ों की आमदनी होती है.■

पद की लड़ाई में पितृपक्ष मेले की नहीं हो रही तैयारी

सुनील सौरभ

गया में प्रत्येक वर्ष लगने वाले पितृपक्ष मेले के आरंभ होने में ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं लेकिन शहर के लोग गंदगी, पेयजल समस्या और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी दूसरी समस्याओं ने जूझने के लिए बाध्य हैं. सिर्फ इतना ही नहीं शहर में अनेक विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं. शहर में जिन पार्षदों को इन विकास योजनाओं को पूरा करवाना है, वे आपसी झगडे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

पछले तीन महीने से गया नगर निगम के 53 वार्डों में विकास के तमाम कार्य ठप पड़े हैं. मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा जमाने के लिए पार्षदों में होड़ मची है. वार्ड पार्षद कुछ ज्यादा हीं आपसी राजनीति कर गया शहर का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं. पद की लालसा में गया शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को भी ताक पर रखकर वार्ड पार्षद अपना हित साधने में ही लगे हुए हैं. गया नगर निगम के सिटी मैनेजर प्रकाश कुमार के अनुसार शहर में करीब 20 करोड़ की योजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण रुकी हुई हैं, जिसमें तेरह वित्त, नागरिक सुविधा, बीआरजीएफ तथा फोर्थ स्टेट फायनेंस की योजनाएं शामिल हैं. गया नगर निगम के आयुक्त रामविलाश पासवान इन योजनाओं के रुके रहने के संबंध में कहते हैं कि निगम से चयनित योजनाओं का टेंडर होने से पूर्व नगर निगम बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है. इन योजनाओं पर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलने के कारण ही इन योजनाओं का टेंडर रुका हुआ है. मेयर विभा देवी ने इस संबंध में बताया कि मैंने नगर आयुक्त को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने को पत्र लिखा है परन्तु नगर आयुक्त का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद मेरी अध्यक्षता में बैठक नहीं हो सकती है. लेकिन पिछली 23 जुलाई को मेयर के खिलाफ अविष्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास हो गया. वार्ड पार्षदों के आपसी झगड़े में मेयर और डिप्टी मेयर का पद खाली हो गया. नगर निगम की राजनीति में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को हटाए जाने के बाद गत 15 जुलाई को डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव को स्थगित होने के बाद तेजी आई. वार्ड पार्षदों की इस लड़ाई से गया में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारी भी प्रभावित हो रही है. ज्ञात हो कि पंद्रह दिनों के इस मेले में देश–दुनिया से करीब दस लाख लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंड दान करने गया आते हैं. इस अवसर पर सरकार जिला प्रशासन तथा नगर निगम की ओर से तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाते हैं लेकिन इस बार शहर की तमाम विकास योजनाओं के साथ पितृपक्ष मेले की तैयारी की व्यवस्था भी नगर निगम की आपसी राजनीति के कारण ठप पड़ी हुई है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

मांगों के समर्थन में दिया धरना

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने 29 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया. सीतामढ़ी जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर स्मारक स्थल पर आयोजित धरने की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष विंदेश्वर महतो व संचालन सचिव दिलीप कुमार शाही ने किया. धरना स्थल पर डीइओ प्रेमचंद्र, डीपीओ जय शंकर ठाकुर ने पहुंच कर शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की. बाद में संगठन का एक शिष्टमंडल डीएम को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. कार्यक्रम को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला, उपाध्यक्ष विनोद बिहारी मंडल, द्विजेंद्र कुमार सुमन, प्रमंडलीय सचिव ज्ञान प्रकाश, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कर्मवीर पासवान, सचिव विजय कुमार, बैंकर्स एसोसिएशन के दिनेशचंद्र द्विवेदी, अवधेश कुमार, नागेंद्र पासवान, उमा शंकर साह व योगेंद्र पासवान समेत अन्य ने संबोधित किया. *– देवेंद्र*

जनता के नहीं हो सके जर्नादन

जनता के नहीं हो सके जनार्दन. यह बात आजसू के कार्यकर्ता सम्मलेन में चतरा विधान सभा प्रभारी अशोक गहलोत के द्वारा बनसिंह जोरी में कही गई. आजसू के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने इस बात को लेकर काफी असंतुष्टी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यहां के विधायक ने केवल अपनी कमाई बढ़ा ली है. जबकि जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसे कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं हैं. चतरा जिले में एक भी महिला महाविद्यालय इंजिनियर कॉलेज नहीं है. यहां के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. जबकि चतरा झारखण्ड राज्य के सबसे अमिर जिलों आता है. चतरा विधान सभा के आजसू प्रभारी अषोक गहलोत ने कहा कि राजद विधायक जर्नादन पासवान हत्या की राजनीति करते है. इनके द्वारा स्व0 संतु दास की हत्या 1995 के विधान सभा चुनाव में करा दिया था. जो सभी को मालूम ह. इन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद झारखण्ड में विधान सभा चुनाव होना है. जनता इनको सबक सिखाने को बेताब है. अन्त: में सभा का सम्बोधन आजसू प्रावक्कता सुदर्शन भागत स्व. तिलेषर साहु की पत्नी साबों देवी हजारीबाग जिला आजसू अध्यक्ष विकास राणा, जोरी प्रखण्ड अध्यक्ष इन्द्रदेव यादव , बिनोद कुमार सरस सम्बोधित किया.

पाण्डेपुरा कावंरिया संघ देवघर रवाना

पांडेपुरा फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार सहित दर्जनो कांवरिया बोल बंम देवघर के लिये रवाना हुए. प्रतापपुर मोड़ स्थित देवी मां का पुजा अर्चना कर देवघर के लिए निक पड़े इनके साथ बिरेन्द्र प्रसाद, विजय प्रसाद, संतोश साह, धनु कुमार, सुरेश पासवान, सुरेश भारती, उमेश ठाकुर , दीपक कुमार, मनोज प्रसाद, संदीप कुमार, अनिल कुमार, सरयु प्रसाद, विजय कुमार, इत्यादि ने सोमवारी जल उठा कर देवघर चल दिये ■ *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

मर रहे हैं मक्का किसान

खगड़िया

मनेन्द्र कुमार

चौथम की धरती को चीरकर अपने खून पसीने से अनाज उपजाने वाले किसानों के पसीने की कोई कीमत नहीं है. जेठ की दोपहर हो या पूस की रात हो, ये किसान अपने शरीर को कष्ट देकर अनाज पैदा करते हैं, लेकिन अनाज पैदा करने वाले किसानों के परिवार की हालत देखने वाला कोई नहीं है. हम मक्का किसानों के हालात के संबंध में कह रहे हैं. मक्का के उत्पादन में एशिया में प्रथम स्थान रखने वाले खगड़िया जिले के मक्का उत्पादकों के हाल ऐसे हो गए है, जिसके संबंध में जितना भी कहा जाय वह कम है. यहां के किसान महाजन से कर्ज लेकर खेती करते हैं. किसान बताते हैं कि हमलोग मक्के के बीज ही महंगे खरीदते हैं.

बीज के बाद खेती में काफी लागत होती है. लेकिन जब हम मक्के का उत्पादन कर लेते हैं तो पहले इसका कोई खरीददार नहीं होता है और खरीददार भी होता है तो हमारे मक्के का उचित दाम नहीं मिल पाता है. किसान राधेश्याम कहते हैं कि एक एकड़ भूमि में मक्का लगाने के लिए कम से कम तीन बार बुआई से पहले खेतों की जुताई की जाती है. जिसकी लागत 2100 रुपये आती है. बीज और मजदूरी में तीन हजार, तीन बोरा डीएपी, 5 बोरा यूरिया, दो बोरियां पोटाश, तीन बार पटवन जो करीब 35 घंटे के आसपास होती है. 150 रुपये के दर से पटवन की कीमत 5250 रुपये पड़ती है. कुल मिलाकर एक एकड़ में किसानों का खर्च 15000 हजार से अधिक हो जाता है. जिसमें बीस से पच्चीस क्विंटल मक्के का उत्पादन होता है. मक्के की कटाई और ढुलाई भी अलग से लग जाते हैं. लेकिन त्रासदी यह है कि किसानों के पास इसे सुरक्षित रखने लिए भी कोई जगह मुहैया नहीं कराई गई है. किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान भी कभी–कभी दिया जाता है और वह भी सही समय पर नहीं मिल पाता है. जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है. उत्पादन के बाद किसानों को मक्का बेचने में भी परेशानी होती है. रैक प्वाइंट पर व्यापारियों द्वारा यह मक्का औने पौने दाम पर खरीदा जाता है. किसान कहते हैं कि गांव में मक्के को बेचने में और भी ज्यादा परेशानियों आती हैं. व्यापारी लोग चाहते हैं कि किसानों से जितना कम से कम दाम पर मक्का खरीद लें. किसान कहते हैं कि किसान इस भय से भी मक्के को बेच देते हैं कि कहीं बारिश में ये सड़ न जाए. किसान हरि पासवान, अनिल सिंह, नंदन सिंह, प्रमोद सिंह, सुबोध सिंह, भोला सिंह, महिंद्र सिंह आदि ने कहा कि यदि फरकिया क्षेत्र के किसानों को आवागमन की सुविधा मिल जाए तो मक्के का सही मूल्य मिलने में सहूलियत हो जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

पांच माह में ही शिक्षक इधर से इधर

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के प्रमोशन दिए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्धारा शिक्षकों का बड़ी संख्या में किए गए स्थानांतरणों का मामला चर्चा का विषय बन गया है. सूत्रों की मानें तो जून माह में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दो बार शिक्षकों का तबादला किया है और तबादले में इस बात का ध्यान रखा है कि जिस–जिसने जो जगह मांगी उसको वह जगह दे दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई को एक बार फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बाद चार दर्जन शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया. इसमें स्थानांतरण की तिथि 30 जून दी गई है, जबकि पत्र शिक्षकों को 11 जुलाई को दिया गया है. सूत्रों की मानें तो तबादले का खेल करीब तीन माह से चल रहा है. जिन लोगों ने अपनी पहुंच बनाई, उनका तबादला कर दिया गया. तबादले में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लोग गांव के अंदर शिक्षक थे, उन्हें सड़क के किनारे वाले विद्यालय में भेजा गया है. हालांकि इस तबादले पर शिक्षकों ने अंगुली उठानी शुरू कर दी है. कई शिक्षकों ने कहा कि हमलोगों ने भी तबादले के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था.लेकिन हमलोगों का तबादला नहीं किया गया. शिक्षकों ने तबादले को रोकने की मांग जिलाधिकारी से की है. कई शिक्षकों ने बताया कि इस मामले को लेकर हमलोग जिलाधिकारी के जनता दरबार में मिलने जाएंगे.■

विस चुनाव में टिकट के दावेदार भाजपा के कई बड़े नेता यह मानते हैं कि इस बार के चुनाव में दूसरे दलों से आए अनुभवी नेताओं को भी भाजपा का टिकट मिलना तय है. वैसे भाजपा में भी पुराने और अनुभवी नेताओं की कमी नहीं हैं, ऐसे में उनके साथ टिकट बंटवारे में नाइंसाफी होती है तो भाजपा नेतृत्व के लिए यह मामला गले की हड्डी बन सकता है. ऐसे कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर दूसरे दल में जाने का भी संकेत दे दिया है.

झारखंड विस चुनाव

भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भयभीत

मंगलानंद

झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूं तो सभी राजनीतिक दलों का अंदरूनी तापमान एकाएक बढ़ ही गया है लेकिन बात जब भाजपा की आती है तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है. इस बार सबसे अधिक आयातित नेता भाजपा में ही होंगे. पूर्ण बहुमत–संपूर्ण विकास का नारा लेकर मिशन 42 प्लस का लक्ष्य हासिल करने की कवायद में जुटी भाजपा में टिकट बंटवारे का फार्मूला फिलहाल उलझा हुआ है. पार्टी के इन सर्मपित नेताओं को अब यह भय सताने लगा है कि आने वाले चुनाव में उनका क्या होगा? भाजपा के टिकट की आस में दूसरे दलों को छोड़ने वाले नेता भी टिकट को लेकर सशंकित हैं.

विस चुनाव में टिकट के दावेदार भाजपा के कई बड़े नेता यह मानते हैं कि इस बार के चुनाव में दूसरे दलों से आए अनुभवी नेताओं को भी भाजपा का टिकट मिलना तय है. वैसे भाजपा में भी पुराने और अनुभवी नेताओं की कमी नहीं हैं, ऐसे में उनके साथ टिकट बंटवारे में नाइंसाफी होती है तो भाजपा नेतृत्व के लिए यह मामला गले की हड्डी बन सकता है. ऐसे कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर दूसरे दल में जाने का भी संकेत दे दिया है. प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी में इंट्री कर चुनाव लड़ने की जुगत में हैं. भाजपाइयों की मानें तो प्रदेश नेतृत्व ने पलामू में एक बड़ा धमाका किए जाने की बात कह कर वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में आने की चर्चा मनीष जायसवाल के नाम की सबसे ज्यादा है लेकिन यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा विधानसभा चुनाव मैदान में आ सकते है. ऐसे में मनीष जायसवाल के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा ये तो समय ही बताएगा?

लोकसभा चुनावों में अकेले ही सत्ता की गद्दी पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी का राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर फार्मूला है, उससे समर्पित कार्यकर्ताओं में भय का माहौल है. इसका कारण है कि पार्टी के टिकट वितरण का फार्मूला का काफी उलझा हुआ है. अगर भाजपा को इन चुनावों में बड़ी जीत हासिल करनी है तो उसे इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि टिकट का वितरण पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही किया जाएगा.

लोकसभा चुनाव के पूर्व झाविमो को छोड़ कर भाजपा का दामन थामने वाले मनीष जायसवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान भाजपा सांसद को जीत दिलाने में सबसे अहम रोल अदा किया था. हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश कुमार की मानें तो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मनीष जायसवाल को मिला तो उनकी जीत को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने नेतृत्व का लोहा मनवा दिया है.

धर, गिरिडीह में भारत सरकार के लेबर वेलफेयर फंड डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के चेयरपर्सन विनोद सिन्हा की भाजपा के भीतर की अचानक बढ़ी सक्रियता से वहां से भाजपा के दो बार विधायक रह चुके चंद्रमोहन प्रसाद की बेचैनी बढ़ गई है. उन्होंने विनोद सिन्हा के भाजपा में शामिल होने के दावे पर सवाल खड़ा किया है. उधर, भाजपा के टिकट के लिए नजर गड़ाए बैठे कई लोगों ने अपनी पुरानी पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन अब उन्हे भी अब टिकट नहीं मिलने का भय सता रहा है. यहां जो तस्वीरें बन रही हैं, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में भाजपा समेत कई अन्य दलों में नेताओं का आना–जाना बढ़ सकता है. भाजपा के लिए टिकट का बटंवारा इस बार गले की हड्डी बन सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में कितना सफल हो पाएंगे मधुसूदन मिस्त्री

बडोदरा संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आमने–सामने की लड़ाई में नाकाम रहने के बावजूद पूरे देश में चर्चित रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस ने झारखंड का जिम्मा सौंपा है. मिस्त्री ने पूरे जोशो–खरोश के साथ झारखंड कांग्रेस की कमान भी संभाल ली है लेकिन वे झारखंड में कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा? इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है मिस्त्री के झारखंड का कमान संभालने के बाद से खंड–खंड में बंटे झारखंड कांग्रेस में फिर से एक नई जान आ गई है. 81 विधानसभा क्षेत्र के लिए दूसरे राज्यों से पर्यवेक्षक भी बुला लिए गए है. मिस्त्री द्वारा चुने गए पर्यवेक्षकों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति भी ली जा चुकी है. इस बार झारखंड में हर–हाल में सभी सीटों पर जीत की तैयारी शुरू कर दी गई है. विधानसभा चुनाव नतीजे बेहतर हों, इसके लिए आला अधिकारियों के साथ–साथ पार्टी संगठन के सभी नेता जुट गए हैं. प्रदेश कमेटी ने गठबंधन का निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया है. इधर, लोक सभा चुनाव के बाद पार्टी के कार्यकताओं में काम को लेकर कुछ नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन आलाकमान के निर्देश ने कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टीव कर दिया है. कार्यकर्ता अपने–अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं. ग्राम, प्रखंड एवं जिले से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकताओं में काम जोरों पर चलने लगी है. कांग्रेस आलाकमान व नियुक्त पर्यवेक्षक ग्राम, प्रखंड व जिले स्तर तक न सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं, बल्कि चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की भी तलाश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि महासचिव मधुसूदन मिस्त्री के निर्देश से साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देने पर सहमति बनी है. कोई कमी न रहे, इसलिए राज्य के बार से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं. कांग्रेस ने इस बार पार्टी में गुटबाजी करने वालों को साइड कॉर्नर दिखाने का निर्देश है. टिकट उसी को मिलेगा, जो पार्टी के समर्पित और एक्टिव कार्यकर्ता हैं. लगातार सभी जिलों में पार्टी की तरफ से कार्यशाला व सम्मेलन का आयोजन करके लोगों में उत्साह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.■

संक्षिप्त ख़बरें

पुनर्वास एक गंभीर समस्या

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गंगा के प्रलंयकारी कटाव से विस्थापित हजारों परिवार को पुर्नवासित करना एक गंभीर समस्या बनी हुई है. यह बात तेमथा करारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के सामुदायिक भवन के प्रांगण में विस्थापितों द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप कुमार तिवारी ने कही. उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि इस विधान सभा में आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में अगर भाजपा का उम्मीदवार जीतता है तो पुर्नवास की आस में बर्ष 1975 से टकटकी लगाए परिवारों को पुनर्वासित करने का प्रयास कराया जाएगा. ■

आम बजट को सराहा

मन्टू राय ने आम बजट पर कहा कि देश के हित में बजट पेश किया गया है. वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है कि जिसमें देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो सके. उन्होंने कहा कि बजट में नेशनल हाइवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विशेष बल देने कि बात कही गई है. उन्होंने कहा कि भारत किसानों का देश है. बजट में किसानों के लिए भी सिंचाई के लिए अलग से प्रवधान किया गया है . दूसरी तरफ प्रमिता देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम लोग पहले ही मंहगाई की मार से त्रस्त है. बजट से मंहगाई और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि आम लोगों के हित में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए था. जिससे लोगों की परेशानी कम हो सकती थी. अच्छे दिनों का वादा पूरा करने में केन्द्र सरकार पिछड़ गयी है.■

किसान विरोधी है केंद्र सरकार

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के परबत्ता प्रखंड में राजद के द्वारा धरना दिया गया. इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने कहा की केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग मंहगाई से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता से वादा किया था कि हम सता में आएंगे तो मंहगाई दूर कर देंगे लेकिन उनके सत्ता में आते ही मंहगाई और बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय अच्छे दिन आने का वादा किया था लेकिन अच्छे दिन आने के वजाए खराब दिन आने लगे हैं. डीजल पेट्रोल की मूल्य की वृद्धि के साथ–साथ किसानों के द्वारा उत्पादित समान कोरी के दाम में बिकने पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिप अध्यक्ष ने कहा कि हम जनता की दु:ख दर्द को लेकर आंदोलन करेंगे. इस अवसर पर राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर, राजद प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास, जिला राजद अध्यक्ष रामचरित्र सदा, कैलाश प्रसाद यादव आदि ने इस धरना को संबोधित किया मौके पर दशरथ दास, निरंजन यादव अंजनी यादव, क्षींगर पंडित, जुलूम यादव, रामविलास शर्मा, राजाराम यादव, कैलाश भारती आदि कार्य कर्तागण उपस्थित थे. ■ *– गीता कुमार*

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

11 अगस्त–17 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

लकड़ी माफियाओं के आगे बेबस पुलिस

लकड़ियों से भरी ट्रालियों की गिनती करता पुलिसकर्मी.

एक तरफ़ जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और प्रदेश के हर ज़िले में अवैध लकड़ी कारोबार तेज़ी के साथ संचालित है. उत्तर प्रदेश में सीतापुर ज़िला किसी भी ज़िले से अवैध लकड़ी के कारोबार में पीछे नहीं है. यहां प्रतिदिन 25 से लेकर 30 लाख तक का लकड़ी का अवैध कारोबार होता है. लकड़ी कारोबारियों में चर्चा का विषय अवैध लकड़ी कारोबार में पुलिस की 40 फ़ीसद हिस्सेदारी है. जनपद में नियम क़ानून की धज्जियां उड़ाते हुए कई प्लाईवुड फैक्ट्रिया एवं बिना लाइसेंस के बिनियर मशीनें संचालित की जा रही हैं. ज़िले में ज़िम्मेदार अधिकारियों से संवाददाता हिमांशु कुमार ने जब इस मसले पर जानकारी लेनी चाही, तो अधिकारी एक-दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते नज़र आए.

हिमांशु कुमार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में पुलिस और वनाधिकारियों की निगरानी में व्यापक पैमाने पर लकड़ी का अवैध कारोबार हो रहा है. इस कारोबार में चौकीदार से लेकर आलाधिकारी तक शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि यह कारोबार पिछले कई वर्षों से चल रहा है. आज़ादी के समय सीतापुर के 33 प्रतिशत भाग पर जंगल था, जिधर नज़र जाती थी, उधर तरह-तरह के पेड़ दिखाई देते थे, लेकिन आज इस जनपद में लकड़ी के अवैध कारोबार के कारण चार प्रतिशत भूमि पर भी वृक्ष नहीं रह गया है. ज़िले में लकड़ी माफियाओं, पुलिस और वन विभाग की मिली भगत से प्रतिबंधित आम, नीम, शीशम जैसे पेड़ों और बड़े-बड़े बागों को चंद वर्षों में समाप्त कर दिया गया. इस जनपद में पुलिस की निगरानी में सबसे अधिक अवैध लकड़ी का कारोबार हो रहा है. पुलिस को सबसे अधिक काली कमाई अवैध पेड़ों की कटाई से प्राप्त हो रही है. इस अवैध कारोबार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी पुलिस की रहती है. इसलिए अवैध लकड़ी कटान की ख़बरें पर्यावरण प्रेमियों के लिए चिंता का विषय भले ही बनती हों, पर ज़िले के पुलिस और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को कौन रोके, क्योंकि लकड़ी कारोबार से जुड़े लोग अधिकारियों की आंख के तारे बने रहते हैं. जनपद में लकड़ी के अवैध कारोबार में अधिक सम्मानित लोग भी शामिल हैं और कई माननीयों का अपने पद पर पहुंचने से पहले लकड़ी का अवैध करोबार ही उनकी राज़ी-रोटी का जरिया था. इन लोगों ने लकड़ी के अवैध कारोबार के ज़रिए खूब धन इकट्ठा किया है. उसके बाद वे राजनीति में आ गए. आज यही माननीय कहीं एक पौधा लगाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्द्धन और वृक्षों की उपयोगिता पर लंबे चौड़े भाषण देकर अख़बारों में अपनी तस्वीरें प्रकाशित कराते हैं. जिससे लगता है कि माननीय बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण की चिंता है, तो केवल उन्हें ही है. व्यापक पैमाने पर कभी लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले एक महाशय दो बार से उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं, जबकि एक महाशय नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन पालिकाध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने लकड़ी का कारोबार नहीं छोड़ा है, बल्कि इस कारोबार को पहले से अधिक बृहद स्तर पर चला रहे हैं. अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी से पालिकाध्यक्ष व लकड़ी के व्यवसाय के संबंध में पूछा जाए तो वह सबसे अधिक तारीफ़ उन्हीं माननीय की करते हैं. तारीफ़ के पीछे अधिकारियों का मक़सद क्या है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं. सीतापुर शहर के बीचों बीच लालबाग स्थित लकड़ी मंडी में खुलेआम अवैध लकड़ी की नीलामी होती है. इस नीलामी में शामिल ज़्यादातर लोगों की शहर के सम्मानित नागरिकों में गिनती होती है. यहीं नहीं पुलिस की सरपरस्ती में लकड़ी के कारोबारी प्रतिबंधित पेड़ को काटने के बाद किसी भी समय कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा खुली छूट मिली हुई है. वे इन अवैध लकड़ियों को ढोने के काम आने वाले ट्रॉली-ट्रैक्टरों के कागज और रजिस्ट्रेशन भी नहीं चेक करते कि इन ट्रॉली-ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन व्यवसायिक है या कृषि कार्य में काम करने हेतु, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन फीस नाम मात्र ही कर रखी है. पूरे जनपद में लकड़ी का व्यापक पैमाने पर कारोबार होता है. इस कारोबार में चार चांद लगाने का काम अवैध लकड़ी की मंडियों द्वारा किया जाता है. सीतापुर नगर, लहरपुर, तंबौर, बिसवां, महमूदाबाद तथा सिधौली में अवैध लकड़ी की मंडी है. पूरे ज़िले में तक़रीबन 25 से 30 लाख की अवैध लकड़ी का प्रतिदिन कारोबार होता है. जिसकी आमदनी का 40 से 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी पुलिस की रहती है. लकड़ी आढ़तियों के यहां डायरी पर जो लकड़ी संबंधी हिसाब का लेखा-जोखा लिखा रहता है, उसमें जो रकम पुलिस को दी जाती है उसे कोड वर्ड में डंडा शुल्क का नाम दिया जाता है. लकड़ी के इस अवैध कारोबार में वन विभाग भी शामिल है. वह हरे-भरे वृक्षों को काटने के लिए परमिट जारी कर देता है. इसमें वन विभाग के साथ-साथ उद्यान विभाग भी दोषी है, क्योंकि वह पैसे की ख़ातिर पेड़ काटने की अनुमति संबंधी रिपोर्ट जारी कर देता है. इसी आधार पर फलदार वृक्षों का कटान निर्बाध रूप से लकड़ी माफिया व अवैध लकड़ी के कारोबारी कराते हैं. यह भी चर्चा रहती है कि लकड़ी माफिया अगर दस पेड़ों की कटान का परमिट बनवाते हैं तो उसकी आड़ में वह पचासों पेड़ों को अवैध रूप से कटवा लेते है. ज़िले में अवैध लकड़ी का कारोबार दिनों दिन फल-फूल रहा है. ज़िले के गोंदलामऊ ब्लॉक के कई गांवों में जहां लकड़ी से कोयला बनाने वाली अवैध भट्ठियां पुलिस और वनकर्मियों की सरपरस्ती में चालू रहती हैं. वहीं तंबौर सहित जनपद के विभिन्न स्थानों पर बिना रोक-टोक और लाइसेंस के बिनियर मशीनें रात-दिन लकड़ी की चिराई का काम कर रही हैं. यही नहीं ज़िले में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट प्लाईवुड फैक्ट्री संचालित हैं, जो शासन द्वारा निर्गत नियम क़ानून का पालन नहीं कर रही हैं. वृक्षों की अंधाधुंध कटान के चलते सीतापुर जनपद का पर्यावरण संतुलन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के पक्षी जिनका जीवन वृक्षों पर निर्भर है. उनमें से अनेक पक्षी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं. जो शेष बचे हैं वह भी विलुप्त होने की कगार पर हैं. चाहे होरिल पक्षी हो, सफेद चील, गिद्ध, कठफोड़वा सहित कई पक्षी इस ज़िले से समाप्त होने के कगार पर हैं. नीलकंठ, उल्लू, लहबड़िया तोता सहित अनेक पक्षी भी विलुप्त होने की कगार पर हैं. वहीं शहरों के रिहायशी क्षेत्रों में बंदरों के आतंक का मुख्य कारण बागों, नहरों व सड़कों के किनारे वृक्षों का समाप्त होना ही है, लेकिन अवैध पेड़ों के कटान से अपनी जेबें भरने वाले लकड़ी माफिया, पुलिस, वन विभाग, उद्यान विभाग, लकड़ी कारोबारियों को पर्यावरण व प्रकृति की हरियाली व उनके ऊपर निर्भर पशु, पक्षी, जीवों से क्या लेना देना है. उन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस धंधे से धन इकट्ठा ही करना है. अगर अवैध लकड़ी के कारोबार पर समय रहते अंकुश न लगाया गया, तो सीतापुर जनपद में वृक्षों की हरियाली की बजाय मरुस्थलीय दृश्य ही दिखाई देंगे. साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि प्राणी जगत का सीतापुर की सरज़मीं पर जीवन ही ख़तरे में पड़ जाएगा. बहरहाल, आज जबकि भारत समेत संपूर्ण दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह हरे वृक्षों की कटाई हो रही है, वह वाकई एक चिंता का विषय है. राज्य सरकार को चाहिए कि वह लकड़ी के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसे, वरना भविष्य में जंगलों का नामोनिशान मिट जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

अवैध वृक्ष कटान से पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है : राजेश कृष्ण

अवैध लकड़ी कटान और कारोबार से जुड़े सवाल पर जब पुलिस अधीक्षक राजेश कृष्ण से जब जानकारी ली गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए सारा ठीकरा वन विभाग पर ही फोड़ दिया. उनका कहना है कि वृक्षों के कटान से संबंधित मामलों से पुलिस का कोई लेना देना नहीं रहता है. लकड़ी के कटान का परमिट वन विभाग जारी करता है. वैध कटान होती है या अवैध, यह वन विभाग जाने, क्योंकि इस विभाग में रेंजर, वन दरोगा और सिपाही की तैनाती होती है. अवैध वृक्ष कटान की ज़िम्मेदारी वन विभाग की होती है, अगर वन विभाग मामले को नहीं संभाल पाता है और पुलिस से सहायता मांगते हैं, तो पुलिस उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है. ■

सुरक्षाकर्मियों की कमी से नहीं हो पाती वनों की सुरक्षा: डीएफओ

प्रभागीय वन निदेशक ने कहा कि कार्रवाई अवैध वृक्ष कटान की सूचना पर की जाती है और अवैध कटान को रोकने की ज़िम्मेदारी जितनी वन विभाग की है, उतनी ही पुलिस की भी है. फलदार वृक्षों के कटान परमिट के लिए अपनी संस्तुति उद्यान विभाग देता है. सीतापुर ज़िले में अंधाधुंध हो रहे अवैध कटान और कारोबार से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में प्रभागीय वन निदेशक डीके सिंह ने बताया कि विभाग के पास इतनी संख्या में कर्मचारी और सुरक्षाबल के लोग नहीं हैं कि वह हर बाग-बगीचे और वृक्षों की रक्षा कर सकें. हालांकि जब कभी हमारे विभाग को अवैध कटान और अवैध लकड़ी कारोबार की सूचना मिलती है, तो अवैध कटान करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कराई जाती है. इसके अलावा, उनसे समन शुल्क भी वसूला जाता है. अवैध कटान रोकने की ज़िम्मेदारी जितनी वन विभाग की है, उतनी ही पुलिस विभाग की भी है. अवैध कटान पर पुलिस को भी कार्रवाई करने का अधिकार मिला हुआ है. उन्होंने बताया कि अवैध कटान को रोकने के लिए जहां वन विभाग द्धारा समय-समय पर कदम उठाये जाते रहे हैं, वहीं पुलिस महकमा भी अवैध लकड़ी कटाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करती है. प्रभागीय वन निदेशक सिंह ने बताया कि आम सहित जितने भी प्रतिबंधत और फलदार वृक्ष हैं, उनका परमिट हमारा विभाग तभी देता है, जब ज़िला उद्यान विभाग के अधिकारी उस पर अपनी संस्तुति प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि कभी-कभी शिकायतें आती हैं कि प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन जब जांच कराई जाती है, तब उनमें से अधिकांश पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति के निकलते ही नहीं हैं और शिकायत झूठी पाई जाती है. उन्होंने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर अवैध लकड़ी काटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाती है और उनसे समन शुल्क भी वसूला जाता है. ■

लखनऊ जनपद वृक्षों की अवैध कटाई में अव्वल

एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि लखनऊ ज़िला अवैध लकड़ी कटान के मामले में अव्वल है. प्लॉटिंग कराने वाले लोग दिन के उजाले में ही वृक्षों का अवैध कटान कराते हैं. लखनऊ से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में बाग-बगीचों की हरियाली की जगह कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं. सीतापुर ज़िले में पुलिस की निगरानी में हो रहे व्यापक पैमाने पर अवैध लकड़ी के कारोबार से संबंधित सवाल पर एक पुलिस अधिकारी ने अपना नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि सीतापुर जनपद की कौन कहे. उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में से सर्वाधिक अवैध पेड़ों की कटान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है. अधिकारी ने कहा कि लखनऊ महानगर का क्षेत्रफल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यहां विभिन्न रिहायशी कालोनियां विकसित हो रही हैं. लखनऊ के सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और कानपुर रोड पर कालोनियों के विकसित होने से भू-माफियाओं और लकड़ी माफियाओं की चांदी हो गई है. लखनऊ ज़िले के दस किमी क्षेत्र में ज़मीन की ख़रीद-फरोख्त और प्लाटिंग का धंधा ज़ोरों से चल रहा है. ज़िले के आस-पास के क्षेत्रों में अधिकांश ज़मीनों पर आम, जामुन, नीम, अमरूद जैसे प्रतिबंधित और गैर प्रतिबंधित बगीचे थे, जिन्हें प्लॉटिंग करने वालों ने कटवा दिया. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

क्या सीबीआई पंढेर को बचा रही है?

प्रभात रंजन दीन

सुरेंदर कोली को भले ही फांसी हो जाए और मोनिंदर सिंह पंढेर भले ही रिहा हो जाए, लेकिन निठारी की पैशाचिक घटना का भूत भुक्तभोगियों के दिलो-दिमाग में बैठ गया है. जिस तरह अनगिनत बच्चे अगवा किए गए, जिस तरह उनके साथ अमानुशिक बरताव किया गया, जिस तरह उनकी नृशंस हत्या की गई और जिस तरह मासूमों की लाशें तक चबा डाली गईं. उसने मानवता को हिला दिया, लेकिन अपना सिस्टम बगैर हिले अमानवीयता की पटरी पर दौड़ता रहा. इतनी बड़ी घटना को हल्के-फुल्के तरीके से लेने और क्षुद्र बयान जारी करने वाले नेता आज भी मस्त हैं. जघन्य हत्याकांड की जांच करने वाली सीबीआई एक असली अभियुक्त को रिहा कराने पर आमादा है, क्योंकि बड़े-बड़े लोग ऐसा चाहते हैं. जिसने अपने निर्देशन में अपराध कराया उसे फांसी नहीं होगी और जिसने मालिक के हुक्म पर अपराध किया, वह फांसी पर लटका दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश ऐसे अर्ध-सत्य वाले न्याय से मर्माहत है.

अभी पिछले ही दिनों देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुरेंदर कोली की दया याचिका को खारिज करते हुए उसकी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी. यह बिल्कुल औपचारिक तरीके से हुआ. कोली की दया याचिका के साथ-साथ कुछ और दया याचिकाएं भी खारिज हुईं, लेकिन अन्य दया याचिकाओं और कोली की दया याचिका में जो मौलिक क्रूर फर्क था उस पर देश की सर्वोच्च संवैधानिक पीठ पर आसीन अभिभावक ने एक बार देश के सिस्टम से यह नहीं पूछा कि निठारी में नारकीय तौर-तरीके से मारे गए उन अनगिनत बच्चों के अभिभावकों को कोली की फांसी से क्या न्याय मिल गया? अपराध के असली सूत्रधार मोनिंदर सिंह पंढेर को रिहा कराने के लिए सीबीआई क्यों छटपटाई रही है? इस घटना के अन्य सारे अभियुक्त फांसी पर क्यों नहीं लटका दिए जाएं? सीबीआई को क्यों नहीं मिले सबूत? या सीबीआई ने साजिश करके सबूत नहीं जुटाए? जबकि बच्चों की लाशें निठारी के नालों में सबूतों की तरह पड़ी और सड़ती रहीं, जिसे पुलिस और सीबीआई ने केवल बोरों में ठूंस देने वाला मलबा समझा था. सीबीआई की रुचि मासूमों के बर्बर हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बजाय शिमला के आलीशान बिशप कॉटन स्कूल और दिल्ली के सेंट स्टीफंस में पढ़े-लिखे ऊंची पहुंच वाले धनाढ्य मोनिंदर सिंह पंढेर को बचाने में थी.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के निठारी में जिस समय घटना हुई थी उन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. बदायूं बलात्कार कांड में मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मौके पर नहीं जाने को लेकर बहुत बवाल मचा, लेकिन मुलायम के निठारी नहीं जाने पर उतना बवाल नहीं मचा था. तब केवल भरपाई करने के लिए उस समय के भी और आज के भी ताकतवर मंत्री शिवपाल सिंह यादव मौके पर गए थे. लेकिन वहां जाकर बोल आए कि ऐसी छोटी-मोटी घटना तो होती ही रहती है. शिवपाल ने यूपी पुलिस के काम करने के तौर तरीके की प्रशंसा की थी और यह भी कहा था कि सीबीआई से जांच कराने पर जांच में अनावश्यक देरी होगी. शिवपाल के इस बयान पर भुक्तभोगी अभिभावकों का राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया. इस पर सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर निंदा के तमाम प्रस्ताव भी पारित हुए, लेकिन इन प्रस्तावों से राजनीतिकों पर क्या फर्क पड़ता है. निठारी घटना में मारे गए (आधिकारिक तौर पर) 17 बच्चों के परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई. निठारी घटना में संदेह के दायरे में आए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, वह भी पूरी नहीं हुई. शिवपाल सिंह यादव के विवादास्पद बयान पर उनकी भूमिका की जांच की मांग भी पूरी नही हुई. केवल दुखी परिवारों को पंढेर की फांसी की खबर से ही थोड़ी संतुष्टि हुई है. यह मांग उस समय भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने की थी. उन्होंने निठारी कांड को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए उपयुक्त स्थिति माना था. आज रविशंकर केंद्र में ताकतवर मंत्री हैं. जांच का स्कोप आज भी उतना ही है.

निठारी की घटना को भारत का शर्म करार दिया गया था. निठारी की घटना कहीं मानव अंगों के व्यापार से जुड़ा मामला तो नहीं था? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है. निठारी स्थित मोनिंदर सिंह पंढेर के घर से जो चार महिलाओं और 15 बच्चों के कंकाल मिले थे, उससे यही आशंका थी कि उनके शरीर के प्रमुख अंग निकाल लिए गए थे. पहले इसे मानव अंगों के क्रूर व्यापार से जोड़ा गया, लेकिन पंढेर को बचाने की गरज से इस मामले को बच्चों की लाशें खाने की मनोवैज्ञानिक विकृति से जोड़ दिया गया. अंगों के व्यापार का मामला खुलता तो कई लोग फंसते. लेकिन लाशें खाने की विकृति केवल दो लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रह गई. सरकार ने आधिकारिक तौर पर केवल 17 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन अनधिकृत सूत्र तीन दर्जन से अधिक बच्चों के मारे जाने की बात बताते रहे, लेकिन सीबीआई ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया. केवल निठारी गांव से ही उस समय 38 बच्चे लापता हुए थे, जिनका आज तक पता ही नहीं चला. ■

feedback@chauthiduniya.com

पंढेर का साथी एसपी बन गया

निठारी हत्याकांड का अभियुक्त और बच्चों की नृशंस हत्याओं का सूत्रधार मोनिंदर सिंह पंढेर को बचाने और जांच की लीपापोती करने वाला नोएडा का तत्कालीन सर्किल अधिकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सरकार की नाक का बाल बन बैठा है. इसी अधिकारी ने निठारी मामले के अनुसंधान की ऐसी-तैयारी कर दी. अदालती औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उक्त अधिकारी पंढेर के पैसे पर ही नोएडा से इलाहाबाद या अन्य जगहों पर जाता था और तफरीह करता था. निठारी प्रकरण में इस अधिकारी और सपा नेता के बीच मोबाइल पर बातचीत भी पकड़ी गई थी. भारी जन-दबाव पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी जांच-पड़ताल में सोची-समझी लापरवाही बरतने का दोषी पाया था.

ऐसे कई रहस्य सच्चाई बताते हैं

निठारी कंकाल कांड के पीड़ित जतिन सरकार की मौत का रहस्य आज तक रहस्य के घेरे में है. जतिन सरकार की गलती यही तो थी कि उसने अपनी बेटी पिंकी सरकार की गुमशुदगी और निठारी कांड में उसकी हत्या पर न्याय पाने की कोशिश की थी. पिंकी सरकार की मौत जिस तरह न्याय के दरवाजे तक पहुंचने से रह गई, उसी तरह उसके दुखी पिता की रहस्यमय मौत पर यह पर्दा छाया ही रह गया कि उनकी मौत हत्या थी या हादसा. तब जबकि यह सामने आ गया था कि जतिन सरकार की हत्या के मामले की जांच कर रहे मुर्शीदाबाद के दो पुलिसकर्मियों पर सीबीआई व पुलिस विभाग के आला अधिकारी दबाव बना रहे थे, ताकि इस मामले को लीप-पोत कर दोषी को बचा लिया जाए. जतिन सरकार की पत्नी वंदना सरकार व उनके बेटे ने पहले ही जतिन की मौत पर गहरे सवाल खड़े किए थे.

बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने में प्रशासन नाकाम

सुधीर कुमार

उत्तर-प्रदेश में गंगा, घाघरा व शारदा समेत अनेक नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जनपद के गांव के लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है. लोग अपने मवेशियों और सामानों के साथ पलायन को मजबूर हैं. प्रशासन ने राहत के नाम पर बाढ़ चौकियों को एलर्ट कर अपने दायित्वों की पुरा कर लिया है. गांव, खेत, खलियान बाढ के पानी में डूब चुका है और ग्रामीणों को अब तमाम बीमारियों का डर सता रहा है. बाराबंकी जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे इस जिले के लगभग 50 से अधिक गांव पानी में घिर गए हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित रामनगर और टिकैटनगर क्षेत्रों से सड़के पानी डूब जाने के कारण संपर्क टूट गया है और लोगों को बाहर निकलने में नावों का प्रयोग करना पड़ रहा है. फैजाबाद जिले में घाघरा उग्र रूप धारण किए हुए है और यहां खतरा निशान पर ही बह रही है. रौनाही तटबंध से सटे गांव और रुदौली तहसील को बाढ़ग्रस्त घोषित किए जा चुका है. क्षेत्र के ग्राम महंगू का पुरवा, नूरगंज समेत आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं, जिससे गांव के लोगो को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. मऊ, आजमगढ़ में भी घाघरा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है. सीतापुर जिले के रेउसा, रामपुर, मथुरा, तंबौर क्षेत्र में घाघरा, शारदा व चौका नदी का जलस्तर बढने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. लोगों में नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंता बनी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. घाघरा ने बहराइच में तबाही मचा के लिए तैयार है और नदी लहरों की आवजा सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं. इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस इशारे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं.

चारों तरफ से नदियों से घिरे जनपद बलिया में घाघरा व गंगा नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जिले में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. नदी के किनारे के गांव बढ़रामपुर, सुंदरपुरवा, खातेपुर, गड़वियमपुरवा, मल्लाहनपुरवा, नासीरगंज, बड़ालीपुरवा, नरपतपुर, जुग्गीलालपुरवा (कैसरगंज तहसील) समेत दर्जनों गांव इसकी चपेट में हैं.

लखीमपुर जिले में भी एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और निघासन तहसील में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. पलियांकला में शारदा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से समय पर जरूरत का सामान नहीं मुहैया कराया जा रहा है. जिले में बाढ़ की गम्भीरता को देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है. मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना इनके लिए चुनौती बन गई है. कई परिवारों के लोग अपनी जान पर खेलकर इनके चारे और खुद के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं. ऐसे में ये कभी भी किसी अनहोनी के शिकार हो सकते हैं.

बदायूं में गंगा में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने लगी है और नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आस-पास तक पहुंच गया है. उधर शाहजहांपुर में रामगंगा में गत दिनों छोड़े गए 1.08 लाख क्यूसेक पानी के यहां पहुंचते ही रामगंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगी है. बरेली में रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके अलावा रामगंगा की सहायक नदियों में पानी बढ़ गया है. बिजनौर में गंगा व मालन नदी के पानी से रावली, ब्रह्मपुरी समेत कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

तटबंधों के टूटने का कारण

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार तमाम जगहों पर बनाए जाने वाले बाधों में बलुआ मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है. जबकि अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार बलुआ मिट्टी बाध बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है. दूसरा कारण है कि बांध बनाते समय या उसके मजबूतीकरण के समय मिट्टी के कार्य में कम्प्लेक्शन का कार्य नहीं किया जाता, जिससे मिट्टी में छोटे-छोटे छिद्र नदियों के पानी के तेज बहाव के कारण बड़े हाते रहते हैं और उसकी देखभाल न होने के कारण तटबंध टूट जाते हैं. बाराबंकी जनपद में शारदा नदी के एल्गिन चरसरी तटबंध के डाउन स्ट्रीम में तो सिंचाई विभाग के लापरवाह अभियंताओं ने तटबंध के निर्माण में बड़ी लापरवाही की. यहां तटबंध का समरेखन (एलायमेंट) ही ठीक नहीं है. हर बार बाढ़ के आने के पहले करोड़ों रुपए के पूंजीगत व्यय बांध बनाने में तथा अनुरक्षण व्यय बने हुए बांधों के मरम्मत में खर्च करने के बाद भी हर साल प्रदेश की प्रत्येक नदियां सूबे के अधिकांश जिलों में कहर बरपाती है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का रकबा हर साल बढ़ता रहता है. प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने घोषणा की थी कि इस बार पूर्वांचल में बाढ़ से तबाही नहीं होने दी जाएगी. ठीक इसके उलट एक सप्ताह भी नहीं गुजरा कि पूर्वांचल के कई जनपदों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी. ऐसा नहीं है कि तटबंधों के निर्माण के लिए धन की कमी होती है. धन तो बहुत मिलता है, लेकिन काबिल सिंचाई अभियंता इस धन को खर्च ही नहीं कर पाते. धन का खर्च नहीं होना कार्य का न होना दर्शाता है. इसके अलावा तटबंधों के कटान के पीछे अभियंताओं का भ्रष्टाचार भी कम उत्तरदाई नहीं है.

बदायूं में गंगा में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने लगी है और नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आस-पास तक पहुंच गया है. उधर शाहजहांपुर में रामगंगा में गत दिनों छोड़े गए 1.08 लाख क्यूसेक पानी के यहां पहुंचते ही रामगंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगी है. बरेली में रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके अलावा रामगंगा की सहायक नदियों में पानी बढ़ गया है.

'चौथी दुनिया' साप्ताहिक समाचार पत्र का जनपद सीतापुर में शुभारंभ होने पर हार्दिक शुभकामनाएं

आशीष मिश्रा एडवोकेट
पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सीतापुर
अध्यक्ष, जागरूक नागरिक मंच
पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, सीतापुर
अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता संघ, सीतापुर

'चौथी दुनिया' साप्ताहिक समाचार पत्र का जनपद सीतापुर में शुभारंभ होने पर हार्दिक शुभकामनाएं

राकेश सिंह
सदस्य विधान परिषद
बहुजन समाजवादी पार्टी
सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

'चौथी दुनिया' साप्ताहिक समाचार पत्र का जनपद सीतापुर में शुभारम्भ होने पर हार्दिक शुभकामनाएं

राजेश वर्मा
सांसद
भारतीय जनता पार्टी
सीतापुर (उप्र)

'चौथी दुनिया' साप्ताहिक समाचार पत्र का जनपद सीतापुर में शुभारंभ होने पर सीतापुर व्यापारिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

विनय गुप्ता
प्रदेश उपाध्यक्ष
यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन
सीतापुर, (उत्तर प्रदेश)

अनूप कुमार गुप्ता
सपा विधायक, महोली क्षेत्र
जनपद सीतापुर
(उत्तर प्रदेश)

संजीव गुप्ता 'टिन्तू'
नगर अध्यक्ष

मुकेश अग्रवाल
जिला उपाध्यक्ष

तुषार साहनी
चेयरमैन

कन्हैया गुप्ता
जिला कोषाध्यक्ष

गोपाल टंडन
नगर जिलाध्यक्ष